सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 165, नई दिल्ली, शनिवार 23 अगस्त 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन में शांति चाहते हैं तो दुसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें। ...

03 40 डॉक्टर शिकायत दे चुके हैं, फिर भी एफआईआर नहीं हुई...
06 महिलाओं का सशक्तिकरण एक बहु-आयामी अवधारणा है
08 श्रीमंदिर में 15 सितंबर से लाइन दर्शन शुरू होगा - कानून मंत्री

दिल्ली के बॉर्डरों पर अब नहीं लगेगा जाम, मौजूदा टोल प्लाजा की जगह गैंट्री टोलिंग से मिलेगी राहत

दिल्ली की सीमाओं पर टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम को कम करने के लिए गैंट्री टोलिंग व्यवस्था जल्द शुरू की जाएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री और एमसीडी एनएचएआई की समन्वय बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा पर बूम बैरियर नहीं होंगे जिससे गाड़ियां बिना रुके गुजर सकेंगी। यह व्यवस्था सिरहोल–रजोकरी बॉर्डर दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे समेत कई जगहों पर लागू होगी।

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली की सीमाओं पर बने टोल प्लाजा पर जल्द आधुनिक टोलिंग व्यवस्था शुरू होगी। टोल प्लाजा पर लग रहे जाम को दूर करने के लिए Gantry Tolling System शुरू किया जाएगा। जिसमें टोल प्लाजा पर बूम बैरियर नहीं होंगे, ऐसे में वाहन टोल प्लाजा पर नहीं रुकेंगे, उनकी रफ्तार कुछ धीमी होगी। टोल प्लाजा पर लगा सिस्टम गाड़ी में लगे स्टीकर को पढ़ेगा और वाहन मालिक के खाते से पैसे कट जाएंगे।

माना जा रहा है कि गैंट्री-आधारित टोलिंग, एएनपीआर कैमरे, आरएफआईडी रीडर और फास्टैग इंटीग्रेशन से टोल पर देरी घटेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। गैंट्री टोलिंग व्यवस्था सिरहोल–रजोकरी बार्डर (एनएच-48), दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे (पैकेज-एक टोल प्लाज़ा), बदरपुर बार्डर (एनएच-19/44), द्वारका एक्सप्रेसवे टोल प्लाज़ा (बिजवासन के पास), और यूईआर-दो (नजफगढ़–बहादुरगढ़ मार्ग) पर अवैध अवरोधों की समीक्षा की गई है।

इन जगहों को दिल्ली की यातायात व्यवस्था के लिए सबसे गंभीर बाधा बताते हुए आधुनिक टोलिंग व्यवस्था को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ हुई नगर निगम और एनएचएआई की समन्वय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और दिल्ली नगर निगम के बीच लंबित मुद्दों पर चर्चा हुई।

मुख्य रूप से टोल प्लाजा पर जाम की समस्या, राजस्व विवादों का समाधान, तकनीक-आधारित टोलिंग सिस्टम की शुरुत, और सड़क अवरोधों, अवैध विज्ञापनों व कचरा फेंकने जैसी समस्याओं पर कार्रवाई पर जोर दिया गया। बैठक में एनएचएआई, यातायात पुलिस, लोकक निर्माण विभाग, बीएसईएस, दिल्ली जल बोर्ड, पर्यावरण विभाग, नगर निगम, राजस्व विभाग और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

रजोकरी टोल प्लाजा पर 50.18 करोड़ के किराये के बकाये और बदरपुर एलीवेटेड फीस प्लाजा पर यूजर फीस जमा करने से जुड़ी लंबित अदायगी की समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि जनता का पैसा विवादों में फंसकर या लापरवाही से बर्बाद नहीं हो सकता।

हर एजेंसी को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। हर रुपये का उपयोग जनता की बेहतर सड़कों, बेहतर सुविधाओं और बेहतर सेवाओं के लिए होना चाहिए।

अतिक्रमण और कचरा फेंकने पर सख्ती

नजफगढ़–बहादुरगढ़ रोड (यूईआर-दो) पर अवैध अतिक्रमण के मामले में एमसीडी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मंत्री ने एजेंसियों को सड़क किनारे कचरा फेंकने पर भी कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अतिक्रमण और डंपिंग केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि दिल्ली की तरक्की में रोड़े हैं। इसे तुरंत बंद करना होगा।

अवैध विज्ञापन और पार्किंग

महिपालपुर फ्लाईओवर (एनएच-48), दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे (एनएच-9) और दिल्ली–सहारनपुर मार्ग (एनएच-709बी) पर बड़े स्तर पर अवैध होर्डिंग्स व विज्ञापनों की पहचान हुई। इसी तरह एनएच-709बी एलिवेटेड रोड पर गांधी नगर के पास एमसीडी पार्किंग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।

मंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सड़कें अवैध विज्ञापनों और पार्किंग से कमाई का ज़रिया नहीं हैं। राजमार्ग जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए हैं, उन्हें हर हाल में खाली और कार्यशील रहना चाहिए।

महिपालपुर फ्लाईओवर और बदरपुर एलीवेटेड सेक्शन (एनएच-2) की ख़राब हालत पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने तुरंत मरम्मत और रखरखाव के निर्देश दिए और कहा कि लापरवाही से नुकसान और असुविधा दोनों बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ बने बरसाती नालों में अवैध सीवर कनेक्शन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने इसे तुरंत बंद करने और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में दिए गए निर्देश

गैंट्री-आधारित टोलिंग पायलट तुरंत शुरू किए जाएं।

जाम कम करने, राजस्व वसूली, अतिक्रमण हटाने और अवैध कचरा रोकने पर एक माह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दी जाए।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध विज्ञापनों और पार्किंग को निर्धारित समय सीमा में हटाया जाए।

एनएचएआई को टोल प्रबंधन और रखरखाव में तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

टायर कंपनियों द्वारा छोटे वाहन मालिकों के साथ भेदभाव सहित नो क्लेम नीति और बड़े फ्लीट मालिकों के लिए वेलकम मोड चिंता का विषय - डॉ यादव

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली– "उफ्तत्सा" राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने आज टायर कंपनियों की नीतियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रमुख टायर कंपनियां छोटे ट्रक और वाहन मालिकों के क्लेम को अस्वीकार करने की नीति अपनाती हैं, जबकि बड़े फ्लीट मालिकों को विशेष सुविधाएं, ऑफर और स्किम्स के साथ वेलकम मोड के तहत विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती है। यह भेदभाव छोटे परिवहनकर्ताओं की आर्थिक स्थिति को लगातार और कमजोर कर रहा है, जो पहले से ही स्पेयर पार्ट्स, इंश्योरेंस, टैक्स, टोल फ्री की बढ़ती लागत और ईंधन कीमतों से जूझ रहे हैं।

डॉ. यादव ने तथ्यात्मक ब्योरे साझा करते हुए बताया कि भारत की प्रमुख टायर कंपनियां समान्यतः अपनी वारंटी नीतियों में स्पष्ट रूप से अंतर रखती हैं। उदाहरण के लिए:

छोटे वाहन मालिकों के लिए नो क्लेम नीतिः छोटे ट्रक मालिकों (1-5 वाहनों वाले) द्वारा दायर किए गए वारंटी क्लेम में से लगभग 80-90% मामलों में कंपनियां क्लेम को अस्वीकार कर देती हैं, कारण बताते हुए कि उपयोग की शर्तें पूरी नहीं हुईं, और लेने पर मैन्युफैक्चरिंग लीकेज को भी अस्वीकार करते हुए या दोष निर्माण संबंधी नहीं है कह कर लौटाना सामान्य बात है 1 एक हालिया सर्वेक्षण (ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन रिपोर्ट, 2024) के अनुसार, छोटे मालिकों को क्लेम प्रक्रिया में औसतन 45-60 तो कभी-कभी 90 से 120 दोनों का लम्बा इंतजार करना पड़ता है, और कई मामलों में कोई प्रतिक्रिया ही नहीं मिलती यह क्लेम क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा फोन ही रिसीव नहीं किए जाते । यह नीति छोटे परिवहनकर्ताओं को अतिरिक्त खर्च के लिए मजबूर करती है, क्योंकिइससे वे नए टायर खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं।

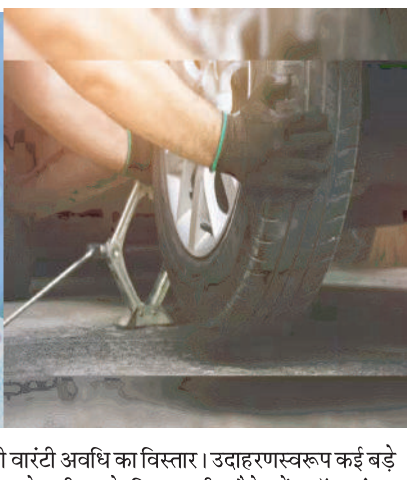

बड़े फ्लीट मालिकों के लिए वेलकम मोड के तहत इसके विपरीत, 50 से अधिक वाहनों वाले बड़े फ्लीट मालिकों को कंपनियां विशेष ₹फ्लीट प्रोग्राम₹ के तहत वेलकम मोड प्रदान करती हैं। इसमें शामिल हैं - विशेष डिस्काउंट, कैश खरीद पर अलग डिस्काउंट, प्राथमिकता वाली क्लेम प्रोसेसिंग (24-48 घंटों में), समर्पित अकाउंट मैनेजर, मुफ्त ऑन-साइट इंस्पेक्शन और कभी-कभी वारंटी अवधि का विस्तार। उदाहरणस्वरूप कई बड़े ब्रांड बड़े फ्लीट्स के लिए ₹फ्लीट मैनेजमेंट सॉल्यूशंसर₹ ऑफर करते हैं, ऑनसाइट सर्विस जहां क्लेम स्वीकृति दर 90% से अधिक होती है। यह विशेष व्यवस्था बड़े ऑपरेटरों को प्रतिस्पर्धी का लाभ प्रदान करती है, जबकि छोटे मालिकों को बाजार से बाहर धकेला जा रहा है।

डॉ. यादव ने कहा, ₹यह भेदभाव न केवल अनुचित है, बल्कि राष्ट्रीय परिवहन नीति के विरुद्ध भी है। छोटे ट्रक मालिक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, जो ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में माल ढुलाई का बड़ा हिस्सा संभालते हैं। टायर कंपनियों की यह नीति उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है, जिससे बेरोजगारी और परिवहन लागत में वृद्धि हो रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि टायर उद्योग में समानता सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएं वही नोक्लेम की नकारा नीति को तुरंत खत्म किया जाए व इसके लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की जाए ।₹

₹उफ्तत्सा₹ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की योजना बना रहा है और सभी छोटे वाहन मालिकों से अपील करता है कि वे अपनी शिकायतें संगठन से सामान्य रूप से साझा करें। परिवहन उद्योग के सभी भाग संभाग के लिए वह सभी धड़ों के लिए हमारी संस्था प्रतिबद्ध है व आख़री पंक्ति मैँ खड़े ट्रक मालिक, चालक व परिवहन व्यवसाईयों के हक़ मैँ उनकी लड़ाई के आखिरी क्षण तक हम उनके साथ खड़े हैं1

डॉ. राजकुमार यादव
राष्ट्रीय अध्यक्ष
"उफ्तत्सा" राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी)

नई दिल्ली सहित सभी बड़े स्टेशनों पर बड़ा बदलाव, रेलवे के एक फैसले से यात्रियों की बड़ी परेशानी दूर; खजाना भी भरेगा

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अनारक्षित टिकट लेने में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे एम–यूटीएस सहायकों की तैनाती करेगा। यह सहायक मोबाइल मशीन से यात्रियों को प्लेटफार्म पर पहुंचने से पहले ही टिकट देंगे। पायलट प्रोजेक्ट नई दिल्ली से शुरू होगा और बाद में अन्य स्टेशनों पर लागू किया जाएगा। इससे बेटिकट यात्रियों पर भी लगाम लगेगी और रेलवे को राजस्व मिलेगा।

नई दिल्ली। नई दिल्ली सहित अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट लेने में यात्रियों को होने वाली परेशानी दूर होगी। उन्हें प्लेटफार्म पर पहुंचने से पहले गेट पर ही टिकट मिल जाएगा। इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर मोबाइल-अनारक्षित टिकट प्रणाली (एम-यूटीएस) सहायकों की तैनाती की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से होगी। इसके परिणाम की समीक्षा करने के बाद अन्य स्टेशनों पर इसे लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था से बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को रोकने में भी मदद मिलेगी।

नई दिल्ली सहित अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट काउंटर पर यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। इसे कम करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर आटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) लगाए गए हैं। इसके बावजूद परेशानी दूर नहीं हो रही है।

शीघ्र ही स्टेशनों पर तैनात एम-यूटीएस सहायक यह परेशानी दूर करेंगे। एम-यूटीएस मोबाइलनुमा एक मशीन है। इसमें एक छोटा सा प्रिंटर भी लगा होता है। इससे यात्री को मौके पर उनका गंतव्य पूछकर अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हें टिकट खरीदने के लिए काउंटर या एटीवीएम के सामने लाइन में नहीं खड़ा होना होगा।

अपील

आप सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को अवगत किया जाता है की कल दिनांक 23-08-2025 को दोपहर 1 बजे फरुखनगर केएम्पी टोल प्लाजा पर HSIIDC के उच्चस्तरीय अधिकारीयों के साथ बैठक रखी गई है, जिसमे भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा केम्पी पर धड़ल्ले से चल रही अवैध टोल वसूली के सम्बन्ध में अपना विरोध दर्ज करवाया जायेगा, जिस भी किसी ट्रांसपोर्टर साथी का डबल टोल कट रहा हो वो अपना फास्टैग के डिटेल आदि लेकर केमपी टोल प्लाजा फारुखनगर में समयानुसार पहुंचे।

समय – दिनांक 23-08-2025, दोपहर 1 बजे
स्थान – फरुखनगर केएमपी टोल प्लाजा
निवेदक
भारत ट्रक एन्ड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन

आमत्रंण

डिअर प्रेस /मीडिआ रिपोर्टर
नमस्कार
दिनांक 25 अगस्त 2025 (3 PM)क़ो दिल्ली के टूरिस्ट टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एन्ड टूर ऑपरेटर्स दिल्ली में पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए एक टूरिज्म पर सेमिनार, स्पीकर हॉल, कंस्टीटूशन क्लब रफ़ी मार्ग में कर रहें हैं.
जिसमे मुख्य अथिति श्री कपिल मिश्रा जी, पर्यटन मंत्री दिल्ली सरकार होंगे.
वहाँ पर्यटन मंत्री, पर्यटन उद्योग दिल्ली में कैसे बढ़ाया जाए और दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा देशी विदेशी पर्यटक आये और उनको दिल्ली में साहूलित मिले, साथ ही टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स और टूर ऑपरेटर्स को भी दिल्ली पर्यटन मंत्रालय से कुछ साहूलित मिले.
इन सब बातो पर पर्यटन मंत्री, श्री कपिल मिश्रा जी कुछ घोषणा भी कर सकते हैं? या इस पर चर्चा कर सकते हैं.
आपसे नम्र निवेदन हैं की
दिनांक 25 अगस्त, 2025 समय 3 PM तक किसी प्रेस /मीडिआ रिपोर्टर को भेज कर इस टूरिज्म सेमिनार को कवर करवा दें
धन्यवाद
संजय सम्राट
अध्यक्ष
दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन.

किफायती गाड़ियों का दौर लौटेगा? 18% जीएसटी से क्या होगा असर

संजय अग्रवाला, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल

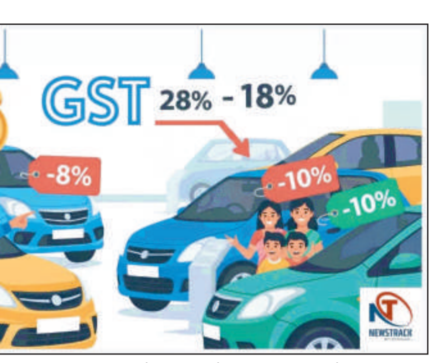

भारतीय ऑटो उद्योग लंबे समय से उच्च कर दरों और कमजोर उपभोक्ता मांग के दोहरे दबाव का सामना कर रहा है। इस परिदृश्य में केंद्र सरकार का दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने का प्रस्ताव उद्योग जगत के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। यह कदम केवल कर राहत भर नहीं है; इसका उद्देश्य वाहन खरीदने की क्षमता को बढ़ाना, एंट्री-लेवल सेगमेंट को फिर से जीवंत करना और व्यापक पैमाने पर मांग को गति देना है। लेकिन सवाल यह है कि इस नीति का दीर्घकालिक असर कितना स्थायी होगा और इससे उद्योग की संरचना किस तरह बदल सकती है? भारत का दोपहिया बाजार, जो दशकों से 100–150 सीसी वाले कम्यूटर मॉडलों पर टिका हुआ था, पिछले कुछ वर्षों में अपनी पकड़ खो रहा था। उपभोक्ता अब अधिक फीचर-युक्त, प्रीमियम विकल्पों की ओर बढ़ रहे थे। ग्रामीण और अर्ध-शहरी बाजार, जो कीमत के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, लगातार महंगे होते वाहनों के कारण हिचकिचा रहे थे। यदि पेट्रोल मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दी जाती है, तो अनुमान है कि कीमतें लगभग 8–10% तक कम हो सकती हैं। इसका सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि 80–90 हज़ार रुपये की रेंज वाले स्कूटर पर लगभग 6–9 हज़ार रुपये की बचत होगी। यह बचत ग्रामीण ग्राहकों को फिर से आकर्षित कर सकती है और एंट्री-लेवल मोटरसाइकिलों के लिए एक बार फिर मांग का द्वार खोल सकती है। हालांकि यह कटौती केवल एंट्री-लेवल के लिए ही फायदेमंद नहीं है। 200–350 सीसी श्रेणी के प्रीमियम मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी लगभग 30 हज़ार रुपये या उससे अधिक की कमी आ सकती है। इससे उन ग्राहकों के लिए अपग्रेड का सपना साकार हो सकता है, जो लंबे समय से रॉयल एनफील्ड या बजाज की प्रीमियम बाइक्स की ओर देख रहे थे लेकिन ऊँची कीमतों के कारण निर्णय नहीं ले पा रहे थे। यह कदम उद्योग में कुल मिलाकर एक सकारात्मक उछाल ला सकता है, लेकिन अंततः यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उपभोक्ता का मनोविज्ञान किस दिशा में जाता है और कंपनियां इस मौके का कितना सदुपयोग करती हैं।

जहां तक डीलरों का सवाल है, यह कटौती उनके लिए एक सुनहरा अवसर बन सकती है। आने वाले त्योहारी सीज़न में बिक्री का जोश वर्षों में सबसे ऊँचे स्तर पर पहुंच सकता है। अधिक बिक्री का मतलब है तेज़ी से इन्वेंटरी टर्नओवर, कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत, बैंक से लिए गए उधार पर कम ब्याज और अंततः बेहतर लाभप्रदता। दूसरे शब्दों में, यह नीति डीलरशिप नेटवर्क को एक नई ऊर्जा दे सकती है और उनके वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत कर सकती है।

लेकिन हर नीति के कुछ अनपेक्षित परिणाम भी होते हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, जो अब तक 5% की न्यूनतम जीएसटी दर और सब्सिडी की वजह से प्रतिस्पर्धा में आगे थे, अचानक अपनी लागतीय बढ़त खो सकते हैं। जब पेट्रोल बाइक की कीमतें गिरेंगी तो कई मूल्य-संवेदनशील ग्राहक ईवी की बजाय आईसीई (आंतरिक दहन इंजन) विकल्प को ही प्राथमिकता दे सकते हैं। अल्पावधि में ईवी की बिक्री पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है, जब तक कि ईवी निर्माता केवल कम लागत ही नहीं बल्कि बैटरी रेंज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टिकाऊपन जैसे कारकों पर भी अपनी वैल्यू प्रपोज़िशन मजबूत न करें।

चारपहिया वाहनों के मामले में प्रस्तावित जीएसटी दर कटौती का लाभ मुख्यतः मास-मार्केट वाहनों को मिलेगा। 1200 सीसी तक के इंजन और 4 मीटर तक की लंबाई वाली पेट्रोल कारों की कीमतें 10–12% तक घट सकती हैं। इसका सीधा फायदा मारुति, हुंडई, टाटा, होंडा, टोयोटा और महिंद्रा जैसी कंपनियों को होगा, जो एंट्री और मिड-सेगमेंट में दबदबा बनाए हुए हैं। खास तौर पर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को इससे सबसे ज्यादा लाभ होगा। पहले से ही एसयूवी-करण की प्रवृत्ति भारतीय कार बाजार को बदल रही है और अब टैक्स लाभ से टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, किया सोनेट जैसी गाड़ियां और ज्यादा आकर्षक हो जाएंगी।

इसके विपरीत, डीजल वाहनों के लिए यह खबर अच्छी नहीं है। जीएसटी संरचना में डीजल कारों के लिए कोई रियायत नहीं है, जिससे पेट्रोल और डीजल मॉडलों के बीच कीमत का अंतर और बढ़ जाएगा। भारत में डीजल की मांग पहले ही गिरावट पर है और यह नीति उस प्रवृत्ति को तेज कर सकती है। प्रीमियम और लग्ज़री कार कंपनियां भी इस कटौती का लाभ नहीं उठा पाएंगी क्योंकि उनकी गाड़ियां आमतौर पर 1500 सीसी से ऊपर के इंजन और 4 मीटर से अधिक लंबाई के साथ आती हैं। उनके लिए उच्चतम कर स्लैब बरकरार रहेगा। स्पष्ट है कि यह प्रस्ताव उद्योग के हर हिस्से को समान रूप से प्रभावित नहीं करेगा। यह उन ब्रांड्स के लिए वरदान होगा जो सस्ते और ईंधन-किफायती वाहनों में काम करते हैं, लेकिन उन कंपनियों के लिए कोई राहत नहीं जो लग्जरी सेगमेंट में हैं। इसके बावजूद, यह कदम भारतीय ऑटो उद्योग में बिक्री की एक नई लहर ला सकता है। हालांकि, यह कटौती अपने आप में समाधान नहीं है। भारतीय उपभोक्ता का स्वाद बदल चुका है। अब उन्हें केवल सस्ते वाहन नहीं चाहिए, बल्कि तकनीक, सुरक्षा और स्टाइल भी चाहिए। यदि कंपनियां इस मौके पर नवाचार में निवेश नहीं करतीं, नए फीचर और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी नहीं लातीं, तो जीएसटी कटौती का लाभ अल्पकालिक होगा। उद्योग को केवल लागत पर ध्यान देने के बजाय अनुसंधान एवं विकास, इलेक्ट्रिफिकेशन और भावी गतिशीलता समाधानों में निवेश करना होगा। इस नीति का सबसे बड़ा सबक यही है कि टैक्स में कमी केवल सांस लेने का समय देती है; असली जीवनदान नवाचार से ही मिलेगा। जो कंपनियां भविष्य की जरूरतों को पहचानकर कदम उठाएंगी, वही इस अवसर का सबसे ज्यादा लाभ उठाएंगी। बाकी के लिए यह राहत केवल थोड़े समय के लिए होगी। अंततः, प्रस्तावित जीएसटी दर कटौती भारत के ऑटो उद्योग के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। यह न केवल बिक्री और उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है, बल्कि उद्योग को उपभोक्ताओं की नई आकांक्षाओं के अनुरूप ढालने का मौका भी देती है। अब जिम्मेदारी कंपनियों की है कि वे इस मौके को कैसे इस्तेमाल करती हैं। अगर वे टिकाऊ, तकनीकी और सुरक्षित वाहनों की दिशा में ठोस कदम उठाती हैं, तो यह जीएसटी कटौती भारत को ऑटोमोबाइल क्रांति के अगले चरण में ले जा सकती है। अन्यथा, यह सिर्फ एक क्षणिक राहत बनकर रह जाएगी।

कॉमरेड वी.एस. अच्युतानंदन : एक कम्युनिस्ट का महाकाव्यात्मक जीवन : आलेख : निधीश जे. विलट्ट, अनुवाद : संजय पराते)

अपने हाई स्कूल के दिनों में मैंने प्रसिद्ध मलयालम लेखक थकाझी शिवशंकर पिल्लई का क्लासिक उपन्यास ₹रंदीदंगाझी₹ पढ़ा था, जो मुझे अच्छी तरह से याद है। इस उपन्यास में मुख्यतः दलित खेतिहर मज़दूरों और गरीब बंटाईदारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और केरल के धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध अलपुझा के कुट्टनाड में कम्युनिस्टों द्वारा आयोजित साम्राज्यवाद-विरोधी, ज़मींदारी-विरोधी प्रतिरोध का चित्रण किया गया है। यह उपन्यास मुख्यतः 1940 के दशक के कृषि संबंधों को दर्शाता है। मेरी पीढ़ी के छात्रों के लिए, ₹रंडीदंगाझी₹ में चित्रित ज़मींदारों द्वारा मेहनतकश लोगों पर शोषण और हिंसा के चरम रूप, उदाहरण के लिए : खेतिहर मज़दूरों और गरीब किसानों पर हृदयविदारक और सामान्यीकृत यौन हिंसा का मामला, अकल्पनीय थे। जब मैंने 1999 में यह उपन्यास पढ़ा था, तब केरल में वर्गीय सहसंबंध इतने बदल चुके थे कि उपन्यास में वर्णित घटनाएँ हमें कहीं और की लग रही थीं। सामाजिक संबंधों में यह युगांतकारी बदलाव कम्युनिस्टों द्वारा ₹कृषि क्रांति₹ को आगे बढ़ाने के लिए किए गए अथक मेहनत का परिणाम था।

5 दिसंबर 1922 को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की चौथी कांग्रेस में, पूर्वी क्षेत्र के सवालों पर आयोग ने ₹पूर्वी क्षेत्र के सवालों पर शोध₹ शीर्षक से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। लेनिन की राजनीतिक देखरेख में, इस प्रस्ताव में एक बुनियादी तर्क दिया गया था : ₹औपनिवेशिक और अर्ध-औपनिवेशिक देशों की कम्युनिस्ट मज़दूर पार्टियों के पास दो कार्यभार हैं : राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने के उद्देश्य से बुर्जुआ-लोकतांत्रिक क्रांति के कार्यभार के सबसे क्रांतिकारी समाधान के लिए संघर्ष करना, और साथ ही राष्ट्रवादी बुर्जुआ-लोकतांत्रिक खेमे के सभी अंतर्विरोधों का लाभ उठाते हुए, मज़दूर-किसान जनता को उनके विशिष्ट वर्ग हितों के लिए संघर्ष में संगठित करना।"

कॉमरेड वीएस अच्युतानंदन के निधन के साथ -- जिन्हें वीएस के नाम से जाना जाता है -- केरल के मेहनतकश लोगों ने बोल्शेविकों की एक दुर्लभ प्रजाति से अपने अद्वितीय युद्ध-प्रशिक्षित कॉमरेड को खो दिया है, जो 1940 में अविभाजित सीपीआई में शामिल हुए थे, ताकि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के "दोहरे कार्यभार" के सिद्धांत को आगे बढ़ाया जा सके। वीएस अक्सर बताया करते थे कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के काम ने उनकी पीढ़ी को कैसे प्रेरित किया, जो 1929 की आर्थिक महामंदी के दुख और भयावहता को देखते हुए बड़ी हुई थी। 1923 में एक पिछड़ी जाति के बंटाईदार किसान परिवार में उनके जन्म ने उन्हें औपनिवेशिक क्रूरताओं के साथ-साथ रक्तपिपासु सामंती शोषण, इसके हिंसक दमन और जातिगत भेदभाव का अनुभव कराया। 102 वर्षों की अपनी लंबी यात्रा में जहां उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री और भारत की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएम के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बनने का सफर तय किया, वहीं वी.एस. एक कट्टर साम्राज्यवाद-विरोधी व्यक्ति बने रहे, जो विश्व के क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध थे।

मैंने अपने कम्युनिस्ट नाना से यह जाना कि कुट्टनाड में जमींदारी हिंसा —सामंती और पूंजीवादी— को समाप्त करने में वीएस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसका वर्णन ₹रंदीदंगाझी₹ उपन्यास में किया गया है। इससे मुझे गहराई से वीएस की महानता से अवगत होने का मौका मिला। केरल में अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही, मलयालम समाचार पत्रों के एक उत्साही पाठक के रूप में, मुझे यह भी याद है कि कैसे केरल के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों — मलयाला मनोरमा (जो स्वदेशी सीरियाई ईसाई पूंजीपति वर्ग द्वारा शुरू किया गया) और मातृभूमि (जो पतनशील उच्च जाति के हिंदू जमींदारों द्वारा शुरू किया गया) — ने वीएस को सबसे बड़े अवरोधक के रूप में खलनायक के रूप में चित्रित किया था। पूंजीपति वर्ग और जमींदारों के लिए, वीएस विकास के नवउदारवादी मॉडल में बाधा डाल रहे थे, जिसके प्रति वे एक वर्ग के रूप में प्रतिबद्ध थे। वीएस के लिए किसानों, खेतिहर मजदूरों, बागान मजदूरों और अन्य सभी मेहनतकश लोगों की आजीविका के साथ-साथ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना नवउदारवाद का पोस्टर बॉय बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण था।

केरल में अविभाजित सीपीआई के संस्थापक सचिव कॉमरेड पी कृष्णा पिल्लई थे, जिन्होंने वीएस को पार्टी में भर्ती किया था। उनके द्वारा वीएस को कुट्टनाड भेजने का फैसला लिया गया। इस फैसले ने उभरते खेतिहर मजदूरों और केरल में ग्रामीण सर्वहारा वर्ग के आंदोलन की दिशा बदल दी। एस्पिनवॉल कंपनी में अपने काम के दौरान आधुनिक नारियल जटा फैक्ट्री के मजदूरों को संगठित करने के लिए वे शुरू में प्रशिक्षित हुए, लेकिन वीएस ने जल्दी ही खेतिहर मजदूरों का दिल और दिमाग भी जीत लिया। 1940 के दशक की शुरुआत में जब वीएस कुट्टनाड गए, तो कृषि में पूंजीवादी निवेश कई क्षेत्रों में फल-फूल रहा था। 1943 तक, वीएस कुट्टनाड के कावलम और कुन्नुमल इलाकों में केंद्रित हो गये। इस क्षेत्र में जोसेफ मुरिकन, चालायिल पणिक्कर और मनकोम्बु स्वामी जैसे बड़े जमींदार थे। पूंजीवादी निवेश के बावजूद, जमींदारों ने ₹संलग्न श्रम₹ की प्रणाली के माध्यम से कृषि दासों के सामंती दमन के भयावह तरीकों को जारी रखा था।

यह एक कटु सामाजिक-राजनीतिक विरोधाभास था कि पूंजीवादी कृषि पद्धति के आगमन से, अमानवीय दमनकारी दासता और जाति व्यवस्था की प्रतिक्रियावादी संस्था के पुरातन सामंती बंधन से मुक्ति पाने के बजाय, ये क्रूर राक्षसी चरित्र शैतानी तीव्रता के साथ और भी मज़बूत होते गए। यह ब्रिटेन में कपड़ा मिलों के औद्योगिक उछाल जैसा था, जिसने अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में दास प्रथा को समाप्त करने के बजाय, उसे फलने-फूलने दिया, ताकि सबसे सस्ते दामों पर कच्चा कपास मिल सके! बाद में, अमेरिका के उत्तरी राज्यों में रेलवे के विकास ने ही उस गृहयुद्ध की वस्तुगत पृष्ठभूमि तैयार की, जिसने दक्षिणी राज्यों में दास प्रथा को समाप्त किया!

उक्त 'संलग्न मजदूर' मुख्यतः पुलाया और पराया दलित जातियों से आते थे। संलग्न मजदूरी की अत्यधिक शोषणकारी व्यवस्था ने बहुत ही कम मजदूरी पर ज्यादा काम का बोझ सुनिश्चित किया था। एलेक्स जॉर्ज लिखते हैं कि ₹जबरन आर्थिक निर्भरता, घर से बेदखल करने की धमकी, शारीरिक हिंसा और जाति प्रथा के सामाजिक रूप से निर्योग्य करने वाले नियमों द्वारा अधीनता₹ -- वे तरीके थे, जिनके द्वारा जमींदार संलग्न मजदूरी को नियंत्रित करते थे।

खेत मजदूरों को संगठित करने के विचार से वीएस ने संलग्न मजदूरों को संगठित करने में आने वाली चुनौतियों का दस्तावेजीकरण किया। ये संलग्न मजदूर मानते थे कि उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना और यहाँ तक कि मार डालना ज़मींदारों का स्वाभाविक अधिकार है। वीएस ने लगातार उनमें जोश भरा, उनमें लड़ने की भावना जगाई और धैर्यपूर्वक उन्हें ज़मींदारों द्वारा उनका अधिकतम शोषण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दुर्भावनापूर्ण तरीकों के बारे में बताया। अपने व्यवस्थित प्रयासों से, वीएस उन्हें उत्साहित करने और समझाने में सफल रहे। अंततः, ग्रामीण सर्वहारा वर्ग, यानी खेत मजदूर वर्ग का आंदोलन कुट्टनाड में स्थापित हुआ और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में औद्योगिक सर्वहारा वर्ग के विस्तार के रूप में अलप्पुझा और केरल के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। पुन्नप्रा-वायलार विद्रोह में खेत मजदूरों ने भी बहादुरी के साथ भागीदारी की।

1948 में जब कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा, तो ज़मींदारों ने अलप्पुझा में ₹सन्नाधा सेना₹ नामक एक स्वयंसेवी दल बनाया, ताकि खेतिहर मज़दूरों और बंटाईदार किसानों के खिलाफ हिंसा फैलाई जा सके। रिवाज़ के अनुसार, मेहनतकशों के घरों की नवविवाहित महिलाओं को तीन महीने तक ₹कोचा₹ जैसे ज़मींदारों के साथ रहना होता था। राजनीतिक रूप से जागरूक ग्रामीण सर्वहारा वर्ग ने इन प्रथाओं का विरोध किया। एन के कमलासन एक कम्युनिस्ट खेतिहर मज़दूर, जिसका नाम ₹गोपालन₹ था, की कहानी सुनाते हैं, जो सामंती हिंसा का जुझारू प्रतिरोध कर रहा था। ज़मींदार कोचा के लेफ्टिनेंट नलुकेट्टुंगल रमन ने पुलिस की मिलीभगत से गोपालन के परिवार को निशाना बनाया। पुलिस और ज़मींदारों के गुंडों ने गोपालन और उसकी माँ को नंगा कर दिया और दोनों को आमने-सामने बाँध दिया। गोपालन की पत्नी के साथ उसके सामने बलात्कार किया गया। बदले में, रमन को मज़दूरों ने मार डाला।

'कलकत्ता थीसिस' के वर्षों के दौरान कम्युनिस्ट विरोधी क्रूर हिंसा ग्रामीण सर्वहारा वर्ग, यानी खेतिहर मजदूरों के आंदोलन को खत्म नहीं कर सकी। वीएस द्वारा स्थापित कुट्टनाड स्थित खेत मजदूरों के आंदोलन, त्रावणकोर कार्शका थोझिलाली यूनियन (टीकेटीयू), पर 1946 में पुन्नप्रा-वायलार विद्रोह के तुरंत बाद प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस चरण में कठिन भूमिगत गतिविधियों ने टीकेटीयू को और अधिक जुझारू बना दिया। इस संगठन पर प्रतिबंध 1951 में ही हटाया गया। उस वर्ष, वीएस ने कावलम में खेत मजदूरों का एक ऐतिहासिक विशेष सम्मेलन आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सम्मेलन ने एक व्यापक मांग पत्र भी स्वीकृत किया, जिसने श्रम विभाग को एक त्रिपक्षीय सम्मेलन और समझौता करने के लिए मजबूर किया। बहरहाल, बड़े ज़मींदारों ने मज़दूरी और काम करने की शर्तों पर हुए इस समझौते को लागू करने से इंकार कर दिया। इससे जुझारू हड़तालों में तेज़ी आई। वीएस के दस्तावेज़ों के अनुसार, 1950 और 1957 के बीच कुट्टनाड में 4279 श्रमिक विवाद हुए।

सर्वहारा वर्ग के जुझारूपन का नया रूप जोसेफ मुरिकन और केएम कोरा जैसे ₹डूबान क्षेत्र के राजाओं (बैकवाटर्स किंग) के विरुद्ध छेड़े गए जुझारू संघर्षों में स्पष्ट दिखाई दिया। केएम कोरा, जो एक बड़े ज़मींदार होने के साथ-साथ कांग्रेस नेता और त्रावणकोर-कोचीन मंत्रिमंडल में तत्कालीन कृषि मंत्री भी थे, के विरुद्ध 1956 के ऐतिहासिक मज़दूरी संघर्ष ने ग्रामीण सर्वहारा वर्ग के जुझारूपन को प्रदर्शित किया। केएम कोरा ने हड़ताली मज़दूरों के विरुद्ध पुलिस और गुंडों की हिंसा का सहारा लिया। तीखी हिंसा भी संघर्ष को तोड़ नहीं सकी और अंततः कोरा को मज़दूर वर्ग के दावे के आगे झुकना पड़ा। बाद में कोरा ने एक वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता से शिकायत की कि ₹हमें खेतिहर मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है ; यह उनकी अकड़ है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़रा उन्हें देखिए — मूँछों के साथ, घुटनों तक धोती मोड़े, और तौलिये को पगड़ी में लपेटे हुए, अकड़ते हुए।₹ यह बदलते वर्गीय संबंधों का स्पष्ट संकेत था।

कोरा के शब्दों से यह स्पष्ट था कि नया पूंजीवाद दुर्भावना से ग्रस्त एक उभयचर जानवर था, जो पतनशील सामंतवाद से आदिम कृषि पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा था, जो उन्मत्त लाभ से प्रेरित था, उसमें अवसरवादी ढंग से मजदूरों को काम पर रखने की लागत कम करने की सहज प्रवृत्ति थी और इसलिए उसने सामंती क्रूरताओं को चरम शोषण के साधन और अमानवीय उत्पीड़न के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। इसलिए, एक क्रांतिकारी संगठन के लिए यह आवश्यक था कि वह एक ही झटके में नवोदित कृषि सर्वहारा वर्ग को ₹स्वयं में वर्ग₹ और ₹स्वयं के लिए वर्ग₹ के रूप में जन्म दे। अविभाजित भाकपा और उसके अग्रणी कैडर कॉमरेड वीएस ने कुट्टनाड में इसे संभव बनाया। यह एक अनूठा परिवर्तन था। इसने केरल के खेतिहर मजदूर वर्ग को राज्य में राजनीतिक रूप से जागरूक सर्वहारा वर्ग का एक दुर्लभ पक्ष बना दिया। यह अनुभव तमिलनाडु के तंजावुर, महाराष्ट्र के वारली क्षेत्र और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में कम्युनिस्टों के अनुभव के समान था। लेकिन यह उन लोगों से अलग था, जो आदिम कृषि पूंजीवाद के खिलाफ अथक लड़ाई का परिणाम था, न कि ठेठ सामंतवाद के खिलाफ।

वी.एस. के नेतृत्व में ग्रामीण सर्वहारा वर्ग के जुझारू आंदोलन ने ₹केरल के एकीकृत राज्य₹ के गठन और 1957 में ई.एम.एस. नंबूदरीपाद के नेतृत्व में प्रथम कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1959 में पारित ₹कृषि संबंध विधेयक₹, जिसने केरल की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया, में झोपड़ीवासियों को अधिकार देने के प्रावधान थे। 1957 में अलप्पुझा जिले में औद्योगिक संबंध समिति (आईआरसी) के गठन के अलावा, ई.एम.एस. सरकार ने 1958 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (भारत) 1948 के प्रावधानों को कृषि कार्यों तक भी लागू किया। ई.एम.एस. की नई पुलिस नीति — श्रम विवादों में हस्तक्षेप न करना — ने भी खेतिहर मजदूरों का आत्मविश्वास बढ़ाया।

ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करने के कम्युनिस्टों के प्रयास को विफल करने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद की सहायता से बुर्जुआ-ज़मींदार वर्ग द्वारा एक प्रतिक्रांतिकारी लामबंदी देखी गई। ईएमएस मंत्रालय के खिलाफ कुख्यात ₹विमोचन संग्राम₹ में दलित खेतिहर मज़दूरों पर लक्षित हमले किए गए और उन्हें जातिवादी गालियाँ दी गईं। ज़मींदारों की सेनाएँ चिल्ला उठीं, ₹हम तुम्हें हमको सामंत कहने पर मजबूर कर देंगे ; हम तुम्हें पत्तों का दलिया पिलाएँगे ; दलित को खेत जोतना पड़ेगा है और चाको (उच्च जाति का कांग्रेसी नेता) ज़मीन पर राज करेगा।₹ 1959 में ईएमएस सरकार की बर्खास्तगी के बाद के महीनों में मेहनतकशों को तीखे हमलों का सामना करना पड़ा।

वी.एस. के नेतृत्व में कृषि श्रमिकों, अर्थात ग्रामीण सर्वहारा वर्ग के बीच किए गए श्रमसाध्य संगठनात्मक और वैचारिक कार्य ने 1967 में दूसरे ईएमएस मंत्रालय के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1968 में खेत मजदूरों के लिए राज्य-स्तरीय पृथक संगठन, केरल राज्य कार्शका थोजिलाली संघ (केएसकेटीयू) के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन (एआईएडब्ल्यूयू) से संबद्ध है। 1969 में ईएमएस मंत्रालय के पतन के बाद, केएसकेटीयू ने एआईकेएस के साथ मिलकर ₹मिच्छा भूमि संग्राम₹ नामक 'अतिरिक्त भूमि पर दावा आंदोलन' का नेतृत्व किया।

इस आंदोलन ने हदबंदी से ऊपर की अतिरिक्त भूमि की पहचान की और सरकार को उसका विवरण दिया। इस आंदोलन का तात्कालिक उद्देश्य अतिरिक्त भूमि पर दावा आंदोलन (₹मिच्छा भूमि संग्राम₹) था। केएसकेटीयू और एआईकेएस के कार्यकर्ताओं ने बहादुरी से ज़मींदारों के नियंत्रण वाली अतिरिक्त भूमि पर कब्ज़ा किया और नीचे से इस आंदोलन के दबाव ने भूमि सुधारों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को गति दी। इसके परिणामस्वरूप राज्य के कई हिस्सों में आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक शारीरिक झड़पें भी हुईं, जो ज़मींदारों के दक्षिणपंथी गुंडों के रूप में काम करते थे। ज़मींदारों और राज्य तंत्र के साथ इस राजनीतिक संघर्ष और सड़क पर हुई लड़ाईयों ने केरल के लोकतांत्रिक ताने-बाने को तार-तार कर दिया।

वीएस वैश्विक वित्त के बढ़ते प्रभाव और कृषि प्रश्न से उसके संबंध के भी गंभीर प्रेक्षक थे। उन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था में नवउदारवादी मोड़ के विरुद्ध लगातार लेखन और आंदोलनों का नेतृत्व किया। धान और आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए उनके बहु-प्रलेखित संघर्षों के साथ-साथ रबर जैसी नकद कृषि फसल की नवउदारवादी लूटपाट का विरोध करने के लिए उनके वैचारिक और संगठनात्मक आलोचनात्मक हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में, वे ₹भूमि सुधार के अगले चरण₹ की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे, जहाँ मजदूरों और किसानों की वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन की गई जीवंत उत्पादन और विपणन सहकारी समितियाँ उन्नत राजनीतिक-आर्थिक अंतर्वस्तु और उन्नत रूपों के साथ एक मजबूत मजदूर-किसान गठबंधन की नींव का काम करेंगी; और कृषि क्रांति को उसकी पूर्णता तक ले जाएँगी।

लाल सलाम, कॉमरेड वीएस!

(लेखक स्वतंत्र लेखन से जुड़े हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।

बेलाफुल का औषधीय सीरप

बेला फूल का सीरप, एक आयुर्वेदिक औषधीय है। जिसका उपयोग, विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए किया जाता है। इसमें बेला फूल के गुण होते हैं जो एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं। इस सीरप को पीने से विभिन्न स्वास्थ्य लाभ होते हैं।

1- सामग्री --------

बेलाफुल – 200 ग्राम (पंखुड़ियाँ), मिश्री – 500 ग्राम, पानी – 1 लीटर, तुलसी या सौंफ – वैकल्पिक (पाचन हेतु), साइट्रिक एसिड – 1 ग्राम (सुरक्षा हेतु), सोडियम बेंजोएट – 1 ग्राम (रक्षोपाय हेतु)।

2- निर्माण विधि ---------

* पानी में बेलाफुल की पंखुड़ियाँ उबालें (धीमी आँच पर 20 मिनट)।

* छानकर, इस अर्क में मिश्री घोलें और तब तक उबालें, जब तक यह सिरप गाढ़ा न हो जाए।

* साइट्रिक एसिड और सोडियम बेंजोएट मिलाकर, कांच की बोतलों में भरें।

3- औषधीय उपयोग --------

(1) गर्मी और पित्त विकारों में -- शीतल, शरीर की जलन, घबराहट, एसिडिटी में आराम देता है।

(2) कब्ज व गैस में -- हल्का विरेचक व पाचन में सहायक।

(3) मानसिक थकान व चिड़चिड़ापन में -- मस्तिष्क को शांत करता है, मूड बेहतर करता है।

(4) महिलाओं में मासिक धर्म विकार -- अनियमित मासिक धर्म, जलन और थकावट में लाभदायक।

(5) श्वसन प्रणाली में उपयोगी -- सुखी खाँसी, गले की खराश में लाभकारी।

4- सेवन विधि ------

आयु वर्ग/ मात्रा/ कैसे लें

(1) वयस्क/ 2–3 चम्मच/ दिन में दो बार, जल या दूध में मिलाकर।

(2) बालक (5–12 वर्ष)/ 1–2 चम्मच/ गुनगुने जल के साथ।

(गर्मी में ठंडे पानी के साथ और सर्दी में गुनगुने पानी के साथ देना उचित।)

5- सेवन अवधि --------

(1) गर्मी के पूरे मौसम में लिया जा सकता है (मार्च से जून तक)।

(2) औषधीय रूप में, 21 से 40 दिन की अवधि उपयुक्त मानी जाती है।

6- सावधानियाँ ------

(1) मधुमेह रोगी, सेवन से पहले चिकित्सक से सलाह लें।

(2) अत्यधिक सेवन से शीत प्रकृति वालों को, सर्दी-जुकाम हो सकता है।

(3) सीरप को ठंडी जगह या रेफ्रिजरेटर में रखें।

(4) बेला फूल का सीरप गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है।

यह खांसी और सर्दी में आराम देने, पाचन में सुधार करने, शरीर की सूजन को कम करने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में सहायता करता है। यदि आप बेला फूल का सीरप पीना चाहते हैं, तो पहले अपने चिकित्सक से बात करें।

मंजिष्ठा और चंदन क्रीम ...

(स्किन ब्राइटनिंग के लिए)....

यह क्रीम त्वचा को निखारने और चमकदार बनाने में सहायता करती है।

■ 1- घटक द्रव्य ......

2 चम्मच मंजिष्ठा पाउडर,

1 चम्मच चंदन पाउडर,

2 चम्मच एलोवेरा जेल,

1 चम्मच नारियल का तेल,

1 चम्मच गुलाब जल

■ 2- निर्माण विधि ....

(1) सभी सामग्री मिलाएं ......

एक कटोरे में मंजिष्ठा पाउडर, चंदन पाउडर, एलोवेरा जेल, नारियल का तेल और गुलाब जल मिलाएं।

(2) फेंटें ....

इस मिश्रण को अच्छे से फेंटें, ताकि यह स्मूद क्रीम के रूप में तैयार हो जाए।

(3) स्टोर करें .....

इसे एक स्वच्छ और सूखे कंटेनर में भरकर, फ्रिज में स्टोर करें।

(4) उपयोग करें .....

इसे सुबह और रात दोनों समय चेहरे पर लगाएं, इससे त्वचा की रंगत निखर जाएगी और त्वचा स्वस्थ लगेगी।

3- गुणकारी और उपयोगी ....

* त्वचा को निखारने और उसकी प्राकृतिक चमक को बढ़ाने में सहायता करती है।

* मुंहासों, दाग-धब्बों और त्वचा की अन्य समस्याओं को कम करती है।

* त्वचा को शीतलता और ताजगी प्रदान करती है, विशेषकर गर्मी में।

* त्वचा को पोषण प्रदान कर उसे स्वस्थ और हाइड्रेटेड बनाए रखती है।

ये दोनों सामग्रियां मिलकर एक प्रभावी स्किनकेयर क्रीम बनाती हैं, जो त्वचा को गहराई से पोषण देकर उसे स्वस्थ और सुंदर बनाए रखती हैं।

प्रेम पच्चीसा (भाग 8)

राजेन्द्र रंजन गायकवाड़
सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक
बिलासपुर, छत्तीसगढ़

रोहन ने एक बड़े फ़िल्म निर्माता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और जल्द ही हिंदी फ़िल्मों में गीत लिखने का सफर शुरू कर दिया। पहली ही फ़िल्म के गीतों ने धूम मचा दी—रेडियो पर बजते, सोशल मीडिया पर वायरल होते और दर्शकों की ज़ुबान पर चढ़ गए। मुंबई की चकाचौंध वाली ज़िंदगी ने रोहन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हर शाम पार्टियाँ, मीटिंग्स, और सेलिब्रिटीज़ के साथ मुलाकातें। पैसा बहता हुआ आ रहा है नाम हर अखबार में छप रहा था। लेकिन हर रात, जब वह अपने लग्ज़री अपार्टमेंट में अकेला लेटता तो भोपाल की यादें सतातीं—माया की मुस्कान, राशि की खिलखिलाहटें, और घर की सादगी।

एक शाम, रोहन ने माया से फोन पर बात की। माया, मुंबई में सब कुछ इतना तेज है। अगर हम यहाँ शिफ्ट हो जाएँ, तो राशि को अच्छी स्कूलिंग मिलेगी, तुम्हें प्र

नई ज़िंदगी... नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ। माया ने हल्के से हँसकर कहा, ₹रोहन, तरक्की अच्छी है, लेकिन सोपान दर सोपान। भोपाल में हमारी जड़ें हैं—दोस्त, परिवार, वो छोटा-सा घर जहाँ राशि बेफ़िक्री खेलती है। मुंबई की भागदौड़ में क्या हम खो नहीं जाएँगे? मैं तो वही सादा जीवन चाहती हूँ, जहाँ खुशियाँ छोटी-छोटी चीज़ों में हों।

रोहन का मन द्वंद्व में फँस गया। एक तरफ करियर की ऊँचाइयाँ, दूसरी तरफ परिवार की खुशियाँ। अगले दिन, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के दौरान, एक पुराने दोस्त और गीतकार ने उसे सलाह दी, ₹भाई, सफलता की सीढ़ी चढ़ते वक्त पीछे मुड़कर देखना मत भूलना। कई लोग यहाँ आकर सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन खुद को खो देते हैं।₹ शाम को रोहन ने फैसला किया कि वह माया और राशि को मुंबई बुलाएगा लेकिन सिर्फ़ एक हफ़्ते के लिए—देखें कि वे यहाँ एडजस्ट कर पाती हैं या नहीं।

रोहन सोचता है गलतफहमी या कोई ग़लती जिससे हो उसी से बात करो, दूसरों से करोगे तो बात बढ़ ही जाएगी। लोगों को सच और झूठ से कोई मतलब नहीं होता है, लोग अपने अपने पक्षपात में बड़ी मजबूती से खड़े रहते हैं, वे अपने पक्ष के बने रहते हैं, सत्य के नहीं। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ है, इसीलिए हमें दूसरों के अंदर की उत्कृष्टता को हृदय की गहराइयों से नमन करना है। अगर हममें अपने कर्तव्यों को निभाने की शक्ति है तो ही अधिकार पाने की आशा रखनी है।

जब माया और राशि मुंबई पहुँचीं, तो शहर की रौनक ने राशि को उत्साहित कर दिया। वह समुद्र किनारे घूमी, मॉल्स में शॉपिंग की, लेकिन माया को सब कुछ अजनबी लग रहा था। ₹यहाँ की हवा में भी जल्दबाजी है,₹ उसने रोहन से कहा। एक रात, डिनर पर जाते हुए, रोहन को एक और रहस्यमयी कॉल आई वही आवाज, ₹रोहन, वो खास प्रोजेक्ट याद है? अब वक्त आ गया है। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुंबई में रहना होगा... हमेशा के लिए।₹ रोहन ने कॉल काट दिया, लेकिन मन में सवाल उमड़ने लगे। क्या यह प्रोजेक्ट कोई बड़ा ब्रेक है, या कोई जाल?

दिन बीतते गए। माया ने देखा कि रोहन कितना व्यस्त है सुबह से रात तक काम, कोई परिवार के लिए वक्त नहीं। राशि भी घर की याद करने लगी। आख़िरकार, माया ने रोहन से कहा, ₹तुम्हें चुनना होगा यह चमक-दमक या हमारा साथ। तरक्की जरूरी है, लेकिन खुशी से ज्यादा नहीं।₹ रोहन ने गहरी साँस ली और सोचने लगा...

ज़िंदगी यहाँ थमती है? क्या रोहन मुंबई में रहकर परिवार को खोने का जोखिम लेगा, या भोपाल लौट आएगा? क्या वो रहस्यमयी प्रोजेक्ट उसकी ज़िंदगी में नया मोड़ लाएगा?

ईश्वर ने मनुष्य का शरीर बहुत उत्तम बनाया। शरीर में अनेक अंग हैं, वे अपना-अपना कार्य करते हैं।

इन सब में एक बहुत ही उत्तम अंग है, हृदय जिसमें हमारी बहुत सी भावनाएं रहती हैं। इस अस्तित्व ने तो हृदय को मधुर स्मृतियों और उत्तम भावनाओं के लिए एक सुवर्ण पात्र के समान बनाया था लेकिन हमने उसमें दुर्भाव/पीड़ा/दुख/विरोध/जलन/ईर्ष्या से भर दिया। जिसमें से रक्त की गंगा बहती है उसके स्त्रोत में ही हमने बोझिलता/पत्थर भर दिए। यह जो हृदय में दुखदायक स्मृतियों तथा दुर्भावनाओं का कचरा है, यह मनुष्य जीवन का विनाश करता है। आश्चर्य यह है कि छाती की ऐसी बोझिलता अब हमें 'सामान्य' प्रतीत होने लगी है जैसे हम रोगों को ही स्वास्थ्य मान बैठे हों। ध्यान रहे कि हृदय को एक उत्तम सुवर्ण पात्र के समान समझते हुए, प्रेम/सद्भावना/मैत्री की मधुर स्मृतियों को स्थान दें। जिससे यह समस्त अस्तित्व सेवा/परोपकार/दान/दया/करूणा/सभ्यता/नम्रता आदि सकारात्मक सद्भावनाओं से परिपूर्ण हो सके।

भारतीय जातव समाज संस्था उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित, सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

नवमनोनीत पदाधिकारी डॉ बाबा साहब जी के विचारों को जन–जन तक पहुँचाने और जाटव समाज के उत्थान हेतु पूरी निष्ठा और सक्रियता से कार्य करेंगे – राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह

यह नई कार्यकारिणी न केवल संगठन की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम – राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह

आगरा, संजय साग़र सिंह। भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के आदर्शों और उनके सामाजिक न्याय के मार्गदर्शन को आत्मसात करते हुए, भारतीय जाटव समाज संस्था ने उत्तर प्रदेश इकाई की नई कार्यकारिणी की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष नेतृपाल सिंह ने जारी की है।

यह महत्वपूर्ण निर्णय संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह के मार्गदर्शन एवं राष्ट्रीय महासचिव सोहन सिंह आज़ाद तथा राष्ट्रीय संगठन सचिव पूर्व न्यायाधीश अनिल कुमार की सहमति से लिया गया। संस्था के अनुसार, यह पुनर्गठन समाज हित में किये जा रहे कार्यों को गति देने एवं संगठनात्मक ढांचे को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है।

घोषित पदाधिकारियों की सूची निम्नलिखित है:

प्रदेश कार्यकारिणी (उत्तर प्रदेश) आर. डी. राम (बनारस) प्रदेश उपाध्यक्ष (प्रभारी - पूर्वी उत्तर प्रदेश), विनोद प्रियदर्शी (अलीगढ़) उपाध्यक्ष (प्रभारी - पश्चिमी उत्तर प्रदेश), डॉ. मुन्ना लाल भारतीय (आगरा) प्रदेश महासचिव, रामहेत प्रदेश कोषाध्यक्ष, रविंद्र कुमार (आगरा) प्रदेश सचिव, शैलेन्द्र कुमार (औरैया) प्रदेश सचिव, आनन्द कुमार वर्मा (इटावा)

प्रदेश सचिव, लक्ष्मण सिंह (मुरादाबाद) प्रदेश सचिव, श्रीमती रचना सिंह (गाज़ियाबाद) प्रदेश सचिव घोषित किये गए।

आगरा मंडल कार्यकारिणी

तेज कपूर (आगरा) मंडल अध्यक्ष (आगरा मंडल), सुरेंद्र कुमार (आगरा) मंडल महासचिव (आगरा मंडल), सुनील कुमार जाटव (फिरोजाबाद)

मंडल सचिव (आगरा मंडल), नवीन कुमार (आगरा)

मंडल कोषाध्यक्ष (आगरा मंडल) एवं मीडिया प्रभारी मनोज सोन घोषित किये गए।

प्रशासनिक दायित्व

अनिल कुमार (आगरा) कार्यालय प्रभारी बनाया गया।

इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने आशा व्यक्त की है कि नवमनोनीत पदाधिकारी डॉ बाबा साहब जी के विचारों को जन-जन तक पहुँचाने, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने और जाटव समाज के उत्थान हेतु पूरी निष्ठा और सक्रियता से कार्य करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह नई कार्यकारिणी न केवल संगठन की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है।

40 डॉक्टर शिकायत दे चुके हैं, फिर भी एफआईआर नहीं हुई, भाजपा डॉक्टरों के नहीं, अपने विधायक के साथ खड़ी है- सौरभ भारद्वाज

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली के आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल में तैनात डॉक्टर से मारपीट मामले में अभी तक भाजपा विधायक हरीश खुराना के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अब इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने पुलिस कमिश्नर और बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने पत्र लिखकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहा है कि सरकारी अस्पताल में भाजपा विधायक हरीश खुराना द्वारा डॉक्टरों से कथित मारपीट की एफआईआर दर्ज़ नहीं हुई है, जबकि 40 डॉक्टर भी एफआईआर के लिए लिखकर शिकायत दे चुके हैं।₹आप₹ विधायक कमिश्नर से इस मामले में मिलना चाहते हैं। गुरुवार से हम मिलने का समय माँग रहे हैं, मगर पुलिस कमिश्नर से बात नहीं हो पाई है । आज फिर हमने मिलने का समय मांगा है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में गुरुवार को एक सरकारी अस्पताल के इंटर्न डॉक्टर के साथ भाजपा के विधायक हरीश खुराना और उनके समर्थकों ने गाली गलौज, बदतमीजी और मार-पिटाई की, यह बहुत शर्म की बात है।एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उनके साथ अगर किसी ने हमले की कोशिश की तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और पांच दिन की रिमांड पर लिया।उसके ऊपर हत्या का प्रयास (अटेम्प्ट टू मर्डर) का मुकदमा दर्ज कर दिया। दूसरी तरफ, उसी दिल्ली में सरकारी डॉक्टर के साथ भाजपा के विधायक हरीश खुराना ने मारपीट की, मगर आज तक उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हादसे के बाद पूरे देश में डॉक्टरों की हड़तालें हुई और यह तय हुआ कि ऐसे मामलों में डॉक्टर नहीं इंस्टीट्यूशन यानी कि अस्पताल एफआईआर कराएगा। एमएस ने अब तक इंस्टीट्यूशनल एफआईआर (संस्थान द्वारा संबंधित के खिलाफ एफआईआर) क्यों नहीं कराई? हरीश खुराना के विषय में 40 से ज्यादा डॉक्टरों ने लिखित में शिकायत की है। उसके बावजूद भाजपा और उनकी सरकार अपने विधायक के साथ खड़ी है, डॉक्टर के साथ नहीं। आम आदमी पार्टी ने आज पुलिस कमिश्नर से मिलने का समय मांगा है। हम पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे। हमने केंद्रीय गृह मंत्री से भी समय मांगा है और हम इनकी एफआईआर दर्ज कराएंगे।

उधर, बुराड़ी से "आप" विधायक संजीव झा ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा है कि 21 अगस्त को दिल्ली स्थित आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों के साथ एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर घटना घटी। इस घटना में मोती नगर क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना द्वारा अस्पताल परिसर में ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों के साथ बदतमीजी एवं मारपीट की गई।

उन्होंने ने कहा है कि इस घटना से अस्पताल के डॉक्टरों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, एफआईआर की मांग की है और अपनी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। डॉक्टर समाज का वह वर्ग है, जो निरंतर रोगियों की सेवा एवं जनहित में कार्यरत रहता है। उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार न केवल शर्मनाक है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी प्रसारित करता है। हाल ही में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला सामने आया था, जिसके विरोध में न केवल उस अस्पताल और पश्चिम बंगाल के डॉक्टर हड़ताल पर गए थे, बल्कि पूरे देश के डॉक्टरों ने एक लंबा देशव्यापी हड़ताल कर और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई थी। उस घटना में हम सबने यह अनुभव किया कि चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन चुका है।

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन किया है कि दोषी व जनप्रतिनिधि पर उचित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। इस मारपीट की घटना के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। और डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएँ।

संजीव झा ने कहा है कि इस विषय पर मैं एवं आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर अपनी बात विस्तार से रखना चाहते हैं। गृह मंत्री से अनुरोध है कि कृपया हमें शीघ्र समय प्रदान करें, ताकि इस प्रकरण पर न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके और भविष्य में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

आख़िरकार मासाब का पुराना मकान मिल ही गया

नंदू बड़ी खुशी और हल्की घबराहट के साथ शहर पहुँचा था। उसका बेटा अब शादी के बंधन में बंधने वाला था। दिल में उसने ठान रखा था कि जिन लोगों ने जीवन में उसे राह दिखाई, उनकी चौखट पर जाकर निमंत्रण देना उसका फ़र्ज़ है। सबसे पहले उसे याद आए अपने बड़े मासाब, वही, जिनकी सेवा उसने बचपन में मन से की थी।स्कूल में जब बाकी बच्चे खेलों में मस्त रहते, तब नंदू कभी तख़्ती धोता, कभी ब्लैकबोर्ड चमकाता, तो कभी कापी-कागज़ सजाता। डाँट भी पड़ी, थप्पड़ भी खाए, मगर नंदू के लिए मासाब की हर डाँट ममता जैसी ही थी।और आज... बरसों बाद जब शादी का कार्ड लेकर उनके दरवाज़े पर पहुँचा तो शहर की भीड़, गर्मी और अजनबी गलियों ने उसे पसीने में नहला दिया। घर ढूँढने में मुश्किल हुई, पर आख़िरकार मासाब का पुराना मकान मिल ही गया।दरवाज़ा खोला तो सामने मासाब थे।

"सलाम मासाब! मैं नंदू... आपका पुराना शागिर्द।₹पहले तो सहसा पहचान न पाए, फिर आँखों में चमक आ गई, "अरे, नंदू? तू आज भी याद करता है मुझे?"

नंदू ने कांपते हाथों से शादी का कार्ड उनके आगे रखा,

"मासाब, मेरे लिए सम्मान ये होगा कि आप ज़रूर आइए। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जाने कि उसके बाप ने अपने गुरू को हमेशा दिल में रखा।₹मासाब ने कार्ड लिया भी, मगर उनकी आँखों में कोई और सवाल तैर रहे थे। सोचने लगे,

"कहीं ये ग़रीब मुझसे पैसे-वगैरह मांगने तो नहीं आया?"

चेहरे पर मुस्कान थी मगर जुबान पर दूसरा ही रस।

उन्होंने बात बदलते हुए कहा,₹थक गया होगा, आ चाय पी ले।"चाय आ गई, पर भोजन का ज़िक्र तक न हुआ। बच्चों को पुकार कर बुलाया भी नहीं।

नंदू ने चुपचाप चाय पी और भारी मन से उठ गया। दिल में सोचता रहा,₹शायद बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। हम तो दिल से रिश्ते निभाते हैं, वे बस रस्म निभा देते हैं।₹उसे याद आया, कैसे कभी मासाब के बेटा-बेटियों को उसने अपनी गोद में उठाकर घुमाया था, उनके लिए मिठाइयाँ लाया था, मेले से खिलौने खरीद कर दिए थे। मगर आज? कोई भी दरवाज़े पर आकर उसे पहचानने तक न निकला।

गाँव लौटते समय उसके दिल में कसक तो थी, मगर उसने खुद को समझाया,

₹मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। बुलाना मेरा काम था, आना-न-आना अब उनकी मर्ज़ी।₹

शादी भव्य रूप से संपन्न हुई। नंदू ने जी-जान से अहसान चुकाया, मेहमानों को इज़्ज़त दी। केवल मासाब न आए। उनका घर वैसा ही बंद रहा, और उसी बंद घर में कहीं दबा रहा नंदू का शादी का कार्ड, खुला तक नहीं।

कुछ दिन बाद शुक्ला जी, जो उसी गाँव में अध्यापक थे, अचानक मासाब से मिलने पहुँचे। मुलाक़ात पर मासाब ने पूछा,

₹अरे भई शुक्ला जी, कहाँ से आ रहे हो?₹

शुक्ला जी हँसते हुए बोलेः

₹नंदू के लड़के की शादी से आ रहा हूँ साहब... क्या शानदार शादी की है! पूरे गाँव ने देखा, बड़ा रुतबा हुआ उसका।₹मासाब सुनते ही निःशब्द रह गए। भीतर कहीं एक दर्द-सा घर कर गया। उस कार्ड को जिस पर उन्होंने नज़र तक न डाली थी, उसी में वो खुशी लिखी थी जिसे सबने देखा, बस उन्होंने नहीं।शुक्ला जी चले गए। कमरे में अकेले मासाब की निगाह मेज़ पर पड़ी। वहाँ धूल तले दबा वही कार्ड रखा था। काँपते हाथों से उठाकर खोल ही लिया। और जब पढ़ा ₹डॉ. आनंद (एम.बी.बी.एस.)₹

नंदू के बेटे का नाम देख उनकी आँखें फटी की फटी रह गईं।सालों तक जिन्हें उन्होंने ग़रीब समझा, उसी नंदू ने अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया।और विडंबना देखिये, खुद मासाब अपने ही बेटे को अच्छी तालीम भी न दिलवा पाए थे।कार्ड उनके हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिर पड़ा, मगर दिल पर जो बोझ गिरा, वो ज़िन्दगी भर न उठ सका।मासाब की आँखें नम हो गईं। उन्होंने सोचा,

₹मैंने पूरी उम्र किताबें पढ़ाईं, मगर आज शागिर्द ने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया, कि मेहनत और सच्चा दिल ही असली गुरू हैं।₹उस दिन मासाब की आँखें धुँधली थीं। उनका दिल पछतावे से भरा था। और उसी कमरे में, धूल-जमे कैलेंडर और गिरे हुए कार्ड के बीच, समय की सबसे सख़्त सच्चाई दर्ज थी,

कभी-कभी शिष्य वही हासिल कर लेता है, जो गुरू नहीं कर पाता।

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह
हरदा मध्य प्रदेश

देशभर में बॉक्सिंग को मशहूर करने के लिए दिल्ली में "फाइट नाइट फेस्ट": डॉ. राकेश मिश्र

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। देश में बॉक्सिंग के खेल को युवाओं में और लोकप्रिय बनाने और ओलंपिक में मेडल के लिए इंडियन ऐमच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में "फाइट नाइट फेस्ट" आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दो दिनों तक देशभर से आए बॉक्सर्स अपनी प्रो बॉक्सिंग स्किल का प्रदर्शन करेंगे। दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बॉक्सिंग का एक नया रूप लोगों के सामने आएगा। जोकि अभी तक विदेशों में ही मशहूर था।

दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए इंडियन ऐमच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. राकेश मिश्र ने बताया कि बॉक्सिंग को देशभर में मशहूर करने के लिए हमने यह अभियान चलाया है। पहले दिल्ली में हम देशभर के बॉक्सर्स के बीच प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं। जोकि कल से शुरु होने जा रहा है। इसके बाद हम पूरे देश के सभी राज्यों में इस तरह के बॉक्सिंग इवेंट कराएंगे। ताकि हमारे युवा खिलाड़ियों को इस खेल का तजुर्बा मिले।

इसके बाद आईपीएल की तर्ज इसकी एक लीग भी तैयार की जाएगी। जिससे हम अपने यहां युवाओं में इस खेल को मशहूर करने के साथ साथ खिलाड़ियों को ट्रेनिंग और उपकरणों के लिए स्पासंरशिप का इंतज़ाम भी करवा पाएं। इससे हमारे यहां ओलंपिक खेलों के लिए बेहतर खिलाड़ी तैयार हो पाएंगे।

मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम बनेगा बॉक्सिंग का नया गवाहःराकेश ठाकरान

इस मौके पर फेडरेशन के सचिव राकेश ठाकरान ने बताया कि ओलंपिक में अब प्रो बॉक्सिंग खेलने वाला खिलाड़ी भी जा सकता है। इसलिए अब खिलाड़ी इस ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम कई सालों से उपेक्षित इस खेल को भारत में दोबारा ऊंचाइयों तक पहुंचा सके, ताकि बॉक्सिग में भारत ओलंपिक मेडल ले सके।

यह कार्यक्रम 23-24 अगस्त दो दिन होगा, जिसमें 5 बजे से इंट्री होगी और 6:30 बजे से बॉक्सिंग शुरु होगी।

फेस मीडिया एवं एक्स लाइव कर रहा भव्य आयोजनः अर्जुन चोपडा

इस बॉक्सिंग का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्टस पर होगा। जिसमें लाइव म्यूजिक भी होगा। इस आयोजन को सफल बनाने हेतु मयंक सोनी, हर्षित हुंडैत, अदिति चौहान की पूरी टीम दिन रात काम में लगी है। दीपक उपाध्याय एवं शबाह ने मीडिया को पूरा ध्यानचंद स्टेडियम परिसर का अवलोकन कराया।

दुनियाभर में हर साल 60 करोड़ लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार, अब एआई करेगा कंट्रोल

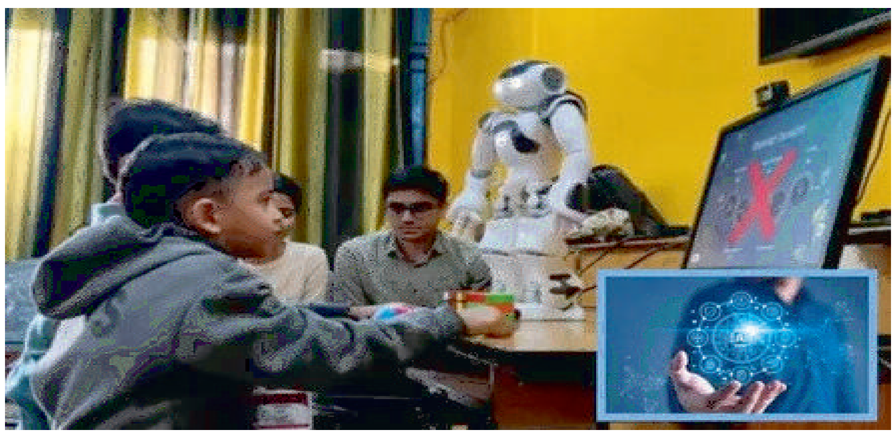

पुनीत उपाध्याय

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विविधआयामी उपयोगों के बीच इसका एक और सकारात्मक पहलू सामने आया है। हाल ही में की गई एक रिसर्च से पता चला है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक की मदद से खाने में छिपे माइक्रोटॉक्सिन्स की पहचान की जा सकती है जिससे फूड पॉयज़निंग पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार हर साल दुनियाभर में करीब 60 करोड़ लोग फूड पॉयज़निंग का शिकार बनते हैं। इनमें से करीब 4 लाख 20 हजार लोगों की मौत हो जाती है। भारत जैसे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों के लिए यह वरदान बन सकता है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को मिल रहे खाने की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती है। नेशनल सेंटर फार डिजीज कंट्रोल के अनुसार भारत जैसे देश में सटीकता के साथ वास्तविक पीड़ितों की संख्या मिलता बहुत कठिन है इसलिए एआई इसमें किसी क्रांति से कम नहीं साबित होगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमेजिंग तकनीकों की मदद से खाने में छिपे जहर को थाली तक पहुंचने से पहले ही खेतों फैक्ट्रियों में पहचान सकता है।

मुक्ति पर्व: देश की स्वतंत्रता के साथ आत्मिक जागृति का पावन पर्व भक्ति में आजादी की मुक्ति निरंकारी राजपिता रमित

दिल्ली स्थित निरंकारी ग्राउंड नं. 8, बुराड़ी रोड पर किया गया जिसमें दिल्ली एवं एन.सी.आर. के क्षेत्रों से हज़ारों श्रद्धालु और भक्तों ने सम्मिलित होकर सतगुरु के आदेशानुसार उन महान संत विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जिन्होंने मुक्तिमार्ग को प्रशस्त करने हेतु अपना सम्पूर्ण जीवन ही मानवता की सेवा में अर्पित कर दिया।

इसके अतिरिक्त विश्वभर में मिशन की सभी शाखाओं में भी मुक्ति पर्व के अवसर पर विशेष सत्संग का आयोजन कर इन दिव्य संतों को नमन किया गया। श्रद्धालुजनों ने शहनशाह बाबा अवतार सिंह, जगत माता बुद्धवंती, राजमाता कुलवंत कौर, माता सविंदर हरदेव, भाई साहब प्रधान लाभ सिंह एवं अन्य अनेक समर्पित भक्तों को हृदय से स्मरण कर उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त की।

आध्यात्मिकता के इस पावन वातावरण में समस्त श्रद्धालुजनों को सम्बोधित करते हुए निरंकारी राजपिता ने फरमाया कि आज 15 अगस्त को जहाँ देश आज़ादी का पर्व मना रहा है, वहीं संतजन इसे मुक्ति पर्व के रूप में आत्मचेतना और भक्ति के संदेश के साथ मना रहे हैं। जैसे झंडा और देशभक्ति गीत आज़ादी के प्रतीक हैं, वैसे ही एक भक्त का जीवन सेवा, समर्पण और भक्ति की महक से भरा होता है। सद्गुरु का दिया ब्रह्मज्ञान ही असली आज़ादी है, जो हमें 'मैं' और अहंकार से मुक्त करता है।

जगत माता जी, शहंशाह जी, राजमाता जीए माता साविंदर जी एवं अनेक संतों का जीवन केवल जिक्र के लिए नहीं, बल्कि प्रेरणा और आचरण के लिए है। भक्ति तब सच्ची है जब हम तू कबूल, तो तेरा किया सब कबूल है के भाव में जीते हैं। वर्षों की गिनती से नहीं, समर्पण की गहराई से भक्ति का मूल्य है। मुक्ति का यह पर्व हमें बार-बार चेताता है कि नाम लेकर नहीं, नाम में रमकर ही जीवन सफल होता है।

निसंदेह, इन संतों का तप, त्याग और सेवा आज भी लाखों आत्माओं के जीवन में प्रकाश का कार्य कर रहा है। जीवन की विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने ब्रह्मज्ञान की मशाल को जलाए रखा और मिशन का संदेश जन-जन तक अपने जीवन के माध्यम से पहुंचाया। वास्तव में, निरंकारी जगत का हर भक्त उनके ऋग्ण से सदैव अभिभूत रहेगा।

इस पर्व की शुरुआत 15 अगस्त 1964 को जगत माता बुद्धवंती जी की स्मृति में हुई जिसे तब 'जगत माता दिवस' के रूप में आयोजित किया गया। 17 सितम्बर 1969 में बाबा अवतार सिंह जी के ब्रह्मलीन होने पर यह दिवस सन् 1970 से 'जगत माता-शहनशाह दिवस' कहलाने लगा। 1979 में प्रथम प्रधान भाई साहब लाभ सिंह जी के ब्रह्मलीन होने पर बाबा गुरबचन सिंह जी ने इसे 'मुक्ति पर्व' नाम दिया। 2018 से माता सविंदर हरदेव जी को भी इस दिन श्रद्धा सुमन अर्पित किये जाते है।

मुक्ति पर्व की मूल भावना यही है कि जैसे भौतिक स्वतंत्रता हमें राष्ट्र की उन्नति का मार्ग देती है, वैसे ही आत्मिक स्वतंत्रता यानि जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति - मानव जीवन की परम उपलब्धि है। यह मुक्ति केवल ब्रह्मज्ञान की दिव्य ज्योति से ही संभव है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, और इस जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध कराती है।

बिटर कोटिंग और चाइल्ड-रेज़िस्टेंट पैकेजिंग के साथ 'सेफ़्टी–फ़र्स्ट' इनोवेशन, भारत में बैटरी उद्योग को दे रहा नया मानक

मुख्य संवाददाता

दुनिया की अग्रणी बैटरी निर्माता कंपनी ड्यूरासेल ने भारत में अपनी नई लिथियम कॉइन बैटरी रेंज लॉन्च करने की घोषणा की है। यह बैटरियां तीन साइज़ – CR2025, CR2016 और CR2032 में उपलब्ध होंगी। इस नई रेंज के साथ, ड्यूरासेल ने कुछ मॉडलों में बिटर कोटिंग और चाइल्ड-रेज़िस्टेंट पैकेजिंग पेश की है, जो छोटे बच्चों को इन्हें निगलने से रोकने में मदद करती हैं और आधुनिक घरों को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं।

छोटी और चमकदार बटन बैटरियां बच्चों के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। इन्हें गलती से निगल लेने पर तुरंत मेडिकल मदद की आवश्यकता पड़ती है। ये बैटरियां घर के कई सामान्य उपकरणों में पाई जाती हैं और बच्चों की आसान पहुँच में आ जाती हैं। बढ़ती चिंताओं के बावजूद, भारतीय बाज़ार में उपलब्ध अधिकांश प्रोडक्ट्स में अब भी ऐसी सुरक्षा सुविधाएँ नहीं हैं, जो इस जोखिम को कम कर सकें।

इस स्थिति को देखते हुए, ड्यूरासेल ने नई लिथियम कॉइन बैटरी रेंज पेश की है, जिसमें परफ़ॉर्मेंस और सुरक्षा दोनों पर ज़ोर दिया गया है। इनकी मुख्य खूबियाँ हैं –

- बिटर कोटिंगः बैटरी की सतह पर एक विशेष, नॉन-टॉक्सिक बिटर कोटिंग दी गई है। यह लार के संपर्क में आते ही कड़वा स्वाद छोड़ती है, जिससे बच्चे इसे निगलने से बचते हैं।
- चाइल्ड-रेज़िस्टेंट पैकेजिंगः यह बैटरियां एक टेम्पर-प्रूफ डबल ब्लिस्टर पैक में आती हैं, जिसे केवल कैंची से ही खोला जा सकता है। इससे 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पहुँच लगभग असंभव हो जाती है।

इस रेंज की बैटरियों में बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए विशेष विज़ुअल सेफ़्टी फीचर्स जोड़े गए हैं। पैकिंग पर "बच्चा बाहर थूक रहा है" का प्रतीक, "बिटर कोटिंग" लेबल और स्पष्ट चेतावनियाँ दी गई हैं। इससे माता–पिता आसानी से पहचान सकते हैं कि यह वही सुरक्षित बैटरी है जो न केवल लंबे समय तक पावर देती है बल्कि बच्चों द्वारा गलती से निगल लेने की संभावना को भी कम करती है।

दोनों रेंज की बैटरियां विभिन्न उपकरणों के लिए उपयुक्त हैं — जैसे की फॉब्स, छोटे रिमोट, स्केल्स, वेयरेबल्स, सेंसर, ग्लूकोमीटर और थर्मामीटर जैसे मेडिकल डिवाइस, स्पोर्ट्स गियर और होम सिक्योरिटी सिस्टम। 10 साल तक की इन-स्टोरेज गारंटी के साथ, ये बैटरियां रोज़मर्रा की ज़रूरतों और आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए भरोसेमंद विकल्प साबित होती हैं।

ड्यूरासेल इंडिया के जनरल मैनेजर सुनील गाडगिल ने नए रेंज पर बात करते हुए कहा, "ड्यूरासेल में सुरक्षा और परफॉर्मेंस साथ-साथ चलते हैं। एक ऐसे ब्रांड के रूप में, जिस पर दुनिया भर के परिवार भरोसा करते हैं, हम लगातार नयी चुनौतियों के अनुसार नवाचार करते रहते हैं।

ड्यूरासेल सिर्फ़ सुरक्षित बैटरियां बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जागरूकता बढ़ाने पर भी ज़ोर दे रहा है। 2023 से कंपनी यूरोपियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (EAP) के साथ मिलकर काम कर रही है।

भारत की पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा ने कहा, "एक माँ के रूप में मेरे लिए बच्चों की सुरक्षा सबसे अहम है। यही वजह है कि मैं ड्यूरासेल के #BunnyKids कैम्पेन को सपोर्ट कर रही हूँ। क्योंकि जागरूकता फैलाकर ही घर को सुरक्षित बनाया जा सकता है। यह कैम्पेन हमें ज़्यादा सतर्क और जागरूक बनाता है और दूसरे माता-पिता को भी प्रेरित करता है कि वे छोटे-छोटे लेकिन ज़रूरी कदम उठाकर अपने नन्हें बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।"

नई ड्यूरासेल लिथियम कॉइन बैटरी रेंज फिलहाल केवल अमेज़न इंडिया पर उपलब्ध है। इस बार कंपनी ने बैटरी परफॉर्मेंस के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया है। सुरक्षित पैकेजिंग और भरोसेमंद क्वालिटी के साथ, ड्यूरासेल सिर्फ पावर नहीं दे रहा, बल्कि भारत में लिथियम कॉइन बैटरी सेगमेंट में 'सेफ़्टी–फ़र्स्ट' आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। यह लॉन्च न केवल जागरूकता को बढ़ावा देता है, बल्कि बैटरी इंडस्ट्री में सुरक्षा और नवाचार का नया मानक स्थापित करता है।

भाजपा नेता विनय चौधरी "किक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया" के वाइस चेयरमैन नियुक्त -

मुख्य संवाददाता

बॉक्सिंग रिंग की गूंज अब राजधानी की गलियों से निकलकर गाँव–गाँव तक पहुंचेगी। कमान संभाल ली है भाजपा नेता विनय चौधरी ने। किक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया द्वारा उन्हें निर्विरोध वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा – "अब चैंपियन केवल स्टेडियम से नहीं, गाँव की मिट्टी से भी निकलेंगे।"

विनय चौधरी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारी हैं और रिसर्च एंड पॉलिसी के राष्ट्रीय सह-प्रभारी के रूप में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वे पार्टी के सक्रिय प्रवक्ता भी हैं। खेलों और खिलाड़ियों के प्रति उनकी भावना जगजाहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "लोकल फॉर ग्लोबल" अभियान से प्रेरित होकर उन्होंने खेल परिधान का ब्राण्ड Taurus स्थापित किया, जो देशी खिलाड़ियों को वैश्विक मंच से जोड़ने का कार्य कर रहा है। वह Taurus Group के चेयरमैन और डायरेक्टर हैं।

पिछले पाँच वर्षों से वे रियल कबड्डी लीग से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम योगदान दे रहे हैं। खेलों में उनकी दूरदर्शिता और संगठनात्मक क्षमता के कारण उन्हें किक बॉक्सिंग फेडरेशन में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के प्रति उनकी निष्ठा और खेलों के प्रति समर्पण का यह संगम निश्चित ही देश के युवा खिलाड़ियों को नई दिशा और प्रेरणा देगा।

विनय चौधरी का स्पष्ट मानना है कि खेल केवल करियर नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का माध्यम हैं। उनका विज़न है कि आने वाले समय में भारत गाँव–गाँव से उभरते खिलाड़ियों की बदौलत विश्व खेल शक्ति के रूप में स्थापित हो।

जब गाँव डूबेंगे और शहर सूखेंगे: इंसान कहाँ जाएगा?

पानी जब अपनी सीमा लांघता है, तो न मानचित्र की रेखाओं को पहचानता है, न दीवारों को, न सरहदों को। और जब धरती की छाती फटती है, तो वह खेत, घर और जीवन सबको निगल लेती है। यही जलवायु संकट है, जिसके सामने आज दुनिया खड़ी है। यह संकट केवल ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के बढ़ने या तापमान के उबलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसानी अस्तित्व के सबसे बड़े सवाल की ओर इशारा करता है—जब गाँव डूबेंगे, जब शहर सूखेंगे, जब खेत बंजर होंगे, तब करोड़ों लोग कहाँ जाएंगे? वे कहाँ अपना घर बनाएंगे, और क्या उन्हें कहीं जगह मिलेगी? यह सवाल न केवल पर्यावरण का है, बल्कि मानवता, नैतिकता और सामाजिक न्याय का है। यह उन करोड़ों लोगों की पुकार है, जो जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे हैं, और जिनके पास न संसाधन हैं, न आवाज़, और न ही कोई ठौर।

विश्व बैंक की 2021 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक 216 मिलियन लोग अपने ही देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करने को मजबूर हो सकते हैं। यह संख्या आज के कुल शरणार्थियों की संख्या से कई गुना अधिक है। ये लोग युद्ध या हिंसा के कारण नहीं, बल्कि प्रकृति के बदलते मिजाज—बढ़ते समुद्र, भीषण सूखा, बेमौसम बाढ़ और चरम मौसमी घटनाओं के कारण उजड़ेंगे। भारत जैसे देश में यह संकट और भी गहरा है, जहाँ 1.4 अरब की आबादी का बड़ा हिस्सा तटीय इलाकों, बाढ़-प्रवण क्षेत्रों और सूखाग्रस्त मैदानों में रहता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आँकड़े बताते हैं कि पिछले 50 वर्षों में भारत में चक्रवातों की तीव्रता में 20% की वृद्धि हुई है, और सूखे की घटनाएँ भी दोगुनी हो गई हैं। सुंदरबन, जो पहले से ही समुद्र के बढ़ते स्तर से जूझ रहा है, वहाँ हर साल हज़ारों लोग अपनी ज़मीन खो रहे हैं। असम में बाढ़ अब सालाना त्रासदी बन चुकी है, जिसने 2022 में 55 लाख लोगों को प्रभावित किया। बुंदेलखंड और मराठवाड़ा जैसे क्षेत्रों में सूखे ने लाखों किसानों को खेती छोड़ने और शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर कर दिया है।

इस संकट की एक और विडंबना यह है कि जलवायु शरणार्थियों को अभी तक अंतरराष्ट्रीय कानून में स्पष्ट रूप से मान्यता नहीं मिली है। 1951 का जेनेवा शरणार्थी सम्मेलन केवल उन लोगों को शरणार्थी का दर्जा देता है जो युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपने देश छोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई बाढ़, सूखा या तूफान के कारण बेघर हो जाए, तो वह इस परिभाषा में फिट नहीं बैठता। इसका मतलब है कि जलवायु शरणार्थियों को न तो अपने देश में और न ही विदेश में कोई कानूनी सुरक्षा मिलती है। यह एक गहरी खामी है, जो दुनिया के नीति-निर्माताओं की उदासीनता को दर्शाती है। कुछ देशों, जैसे न्यूज़ीलैंड और स्वीडन, ने इस दिशा में छोटे-छोटे कदम उठाए हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर अभी तक कोई ठोस ढांचा नहीं बना।

भारत में स्थिति और भी जटिल है। यहाँ पहले से ही आंतरिक विस्थापन एक बड़ी समस्या है। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल औसतन 1.4 करोड़ लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित होते हैं। यह संख्या किसी भी युद्धग्रस्त देश से कहीं अधिक है। और जब ये लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो वे पहले से ही तनावग्रस्त शहरी ढांचे पर बोझ बन जाते हैं। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे महानगरों में झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, और इनमें से अधिकांश लोग जलवायु परिवर्तन के शिकार हैं। लेकिन सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ इन्हें शरणार्थी के रूप में नहीं देखतीं; ये लोग केवल प्रवासी कहलाते हैं, और उनकी कहानियाँ आधिकारिक दस्तावेज़ों में गुम हो जाती हैं।

इस संकट की जड़ें गहरी हैं और केवल प्राकृतिक आपदाओं तक सीमित नहीं हैं। हमारा विकास मॉडल, जो मुनाफ़े और अनियंत्रित शहरीकरण पर आधारित है, इस समस्या को और बढ़ा रहा है। हमने जंगलों को काटा, नदियों को प्रदूषित किया, और जल प्रबंधन को बाज़ार के हवाले कर दिया। भारत में भूजल स्तर पिछले 30 वर्षों में 20% तक गिर चुका है, और अनुमान है कि 2030 तक देश के कई हिस्सों में पानी की भयंकर कमी होगी। साथ ही, हमारी कृषि नीतियों ने छोटे किसानों को कर्ज और निर्भरता के जाल में फँसाया, जिससे वे जलवायु परिवर्तन की मार को झेलने में और कमज़ोर हो गए।

इस संकट का सबसे दुखद पहलू यह है कि यह असमानता को और गहरा करता है। गरीब, दलित, आदिवासी, महिलाएँ और बच्चे—ये वे लोग हैं जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। एक अमीर व्यक्ति हमेशा बेहतर जगह पर जा सकता है, लेकिन जो पहले से ही हाशिए पर हैं, उनके लिए कोई ठौर नहीं है। उदाहरण के लिए, सुंदरबन में रहने वाली आदिवासी महिलाएँ, जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अब समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण अपनी आजीविका और सुरक्षा खो रही हैं। यह केवल पर्यावरण का सवाल नहीं है; यह सामाजिक न्याय का सवाल है।

क्या इसका कोई समाधान है? हाँ, लेकिन इसके लिए साहस, दूरदृष्टि और सामूहिक इच्छाशक्ति चाहिए। सबसे पहले, हमें जलवायु शरणार्थियों को एक मानवाधिकार के रूप में देखना होगा। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट कानूनी ढांचा बनाना होगा, जो इन लोगों को सुरक्षा, पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की गारंटी दे। दूसरा, हमें अपने शहरों को इस तरह से पुनर्गठित करना होगा कि वे विस्थापित आबादी को समायोजित कर सकें। सस्ते आवास, रोज़गार के अवसर, और बुनियादी सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा इस दिशा में अनिवार्य हैं। तीसरा, हमें ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ विकास पर ध्यान देना होगा—जल संरक्षण, जैविक खेती, और स्थानीय संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण लोगों को उनके गाँवों में टिकाए रख सकता है।

सबसे ज़रूरी है वैश्विक स्तर पर जलवायु न्याय की माँग। विकसित देश, जिन्होंने कार्बन उत्सर्जन के ज़रिए इस संकट को जन्म दिया, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दें। पेरिस समझौते में 100 अरब डॉलर की प्रतिबद्धता थी, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा ही अब तक दिया गया है। यह असमानता तब तक बनी रहेगी, जब तक अमीर देश अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी को स्वीकार नहीं करते।

जलवायु शरणार्थियों की त्रासदी केवल आँकड़ों की नहीं है; यह हमारी साझा मानवता का सवाल है। जब समुद्र गाँवों को निगल रहा हो, जब धरती खेतों को बंजर बना रही हो, तब हमारी चुप्पी और निष्क्रियता हमें भी इस संकट का हिस्सा बनाती है। यह समय है कि हम न केवल अपने घरों को बचाएँ, बल्कि उस धरती को भी बचाएँ जो हम सबका घर है। अगर हम अभी नहीं जागे, तो वह दिन दूर नहीं जब लाखों लोग हमारे दरवाज़े पर खड़े होंगे, और हमसे पूछेंगे—"अब हम कहाँ जाएँ?" क्या हमारे पास तब कोई जवाब होगा?

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

भगवान की समस्त लीलाओं और अवतारों की कथाओं का ज्ञान कराने वाली कथा है श्रीमद्भागवत :

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। सेवाकुंज-परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीसिद्ध पीठ इमलीतला में प्रमुख समाजसेवी प्रवीण भाई अम्बालाल पटेल की पावन स्मृति में चल रहे श्रीमद्भागवत कथामृत महोत्सव के अंतर्गत व्यासपीठ से त्रिदण्डी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदान्त मधुसूदन महाराज (विश्वबंधु) ने अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा देश-विदेश से आए समस्त भक्त-श्रृद्धालुओं को भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की कथा का रसास्वादन कराया।

व्यास पीठाधीन त्रिदण्डी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदान्त मधुसूदन महाराज (विश्वबंधु) ने श्रीमद्भागवत की महिमा बताते हुए कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया है। भगवान की समस्त लीलाओं और अवतारों की कथाओं का ज्ञान कराने वाली यह कथा सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, द्वैत-अद्वैत, निर्गुण-सगुण का ज्ञान प्रदान करती है। वस्तुतः श्रीमद्भागवत महापुराण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अक्षय भंडार है। इसीलिए इस ग्रंथ के श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय हो जाता है और भगवान की भक्ति सहज में ही प्राप्त होती है।

इस अवसर पर आयोजित नंदोत्सव में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से सम्बंधित भजनों व बधाईयों का संगीत की मृदुल स्वर लहरियों के मध्य गायन किया गया।साथ ही खेल-खिलौने,रुपए-कपड़े, मेवा-मिष्ठान्न और वस्त्रादि लुटाए गए।

इससे पूर्व महोत्सव के मुख्य यजमान स्वप्निल पटेल (गुजरात) ने वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य श्रीमद्भागवत महापुराण ग्रंथ एवं व्यासपीठ का पूजन-अर्चन कर उनकी आरती की।

महोत्सव में यमुना कुंज के अध्यक्ष श्रीस्वामी भक्ति प्रदीप पद्मनाभ महाराज, इमलीतला के अध्यक्ष गोविन्द दास दामोदर महाराज, प्रख्यात साहित्यकार डॉ. गोपाल चतुर्वेदी, भक्तिवेदांत दामोदर महाराज, भक्तिवेदांत साधु महाराज, डॉ. राधाकांत शर्मा, प्रेम प्रदीप दास, राधा नाथ दास आदि की उपस्थिति विशेष रही।

जय वंश हैल्थ केयर में निःशुल्क परामर्श कैंप 23 अगस्त को

कैंप में नि:शुल्क होंगी बी.पी., शुगर, ई.सी.जी., बी.एम.डी., स्पायरोमेट्री, न्यूरोपैथी आदि की जांचें

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

मथुरा। भूतेश्वर रोड़ (लाल चश्मा घर के सामने) स्थित जय वंश हैल्थ केयर में स्व. कुंवर जयवीर सिंह सिकरवार (बाबूजी) की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 23 अगस्त 2025 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 02 बजे तक निःशुल्क परामर्श कैंप आयोजित किया जाएगा। जिसमें बी.पी., शुगर, ई.सी.जी. (दिल को जांच), बी.एम.डी. (हड्डियों में कैल्शियम की जांच), स्पायरोमेट्री (स्वांस एवं अस्थमा की जांच) न्यूरोपैथी (नसों में कमजोरी की जांच) आदि निःशुल्क की जाएगी।

प्रमुख समाजसेवी डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने बताया है कि

निःशुल्क परामर्श कैंप में वरिष्ठ रिटायर्ड आर्मी फिजिशियन डॉक्टर (मेजर) अजीत सिंह सिकरवार सभी रोगियों को निःशुल्क परामर्श देंगे।

ज्ञात हो कि डॉक्टर (मेजर) अजीत सिंह सिकरवार डायबिटीज, बी.पी., थायराइड. हृदय रोग, फेफड़े, टी.वी. एवं पेट रोग आदि के विशेषज्ञ हैं।

"इलेक्शन कमीशन : पब्लिक का भरोसा या पॉलिटिक्स का प्रेशर"

"जनता की आँखों में भरोसा, आयोग के कंधों पर जिम्मेदारी"

भारतीय चुनाव आयोग कभी लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव माना जाता था। लेकिन हालिया वर्षों में उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे हैं—मतदाता सूची से नाम गायब होना, मतदान प्रतिशत में देरी और असंगति, ईवीएम-वीवीपैट मिलान की सीमाएँ, तथा आयुक्तों की नियुक्ति पर राजनीतिक प्रभाव। आचार संहिता के लागू होने में भी दोहरा मापदंड दिखाई देता है। सबसे बड़ा संकट यह है कि जनता का भरोसा डगमगाने लगा है। लोकतंत्र का अस्तित्व केवल मशीनों पर नहीं, बल्कि नागरिकों के विश्वास पर टिका है। आयोग के लिए यही भरोसा बचाना सबसे बड़ी चुनौती है।

- डॉ. प्रियंका सौरभ

भारतीय चुनाव आयोग कभी लोकतंत्र का सबसे विश्वसनीय प्रहरी माना जाता था। पर हालिया विवादों ने उसकी साख पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं—मतदाता सूची से नाम गायब होना, मतदान प्रतिशत की पारदर्शिता पर संदेह, और नियुक्तियों की प्रक्रिया पर उठते सवाल। चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब नियम बनाने या नोटिस भेजने की नहीं, बल्कि जनता के भरोसे को लौटाने की है। क्योंकि लोकतंत्र केवल वोटिंग मशीनों पर नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास पर चलता है। अगर विश्वास डगमगाया, तो चुनाव सिर्फ रस्म रह जाएंगे और लोकतंत्र अपने असली मायने खो देगा।

लोकतंत्र एक खेल है। खेल का मैदान जनता है, खिलाड़ी राजनीतिक दल हैं और रेफरी चुनाव आयोग। सवाल यह है कि जब रेफरी ही किसी एक टीम की जर्सी पहनकर मैदान में उतर आए तो खेल कितना निष्पक्ष रह जाएगा? हाल के दिनों में यही शंका बार-बार उठ रही है।

मतदाता सूची से नाम हटाने का मामला मानो एक नया सरकारी फैशन बन गया हो। वोटर घर बैठे सोचता है कि लोकतंत्र में उसका अस्तित्व है, लेकिन जब मतदान वाले दिन बूथ पर जाता है तो पता चलता है कि वह तो पहले ही "गायब" कर दिया गया है। जैसे कोई जादूगर टोपी से खरगोश निकालता है, वैसे ही चुनाव आयोग नाम काटने की कला दिखा देता है। और जब आप शिकायत करने जाते हैं तो कहा जाता है—"जी शपथपत्र भरिए, गवाही दीजिए, साबित करिए कि आप जीवित हैं।" यानी इस देश में नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत अब यह नहीं कि आप साँस ले रहे हैं, बल्कि यह है कि आयोग ने आपके नाम पर पेंसिल से टिक लगाई है।

चुनाव आयोग की पारदर्शिता का हाल वैसा ही है जैसे दूल्हे की घोड़ी पर रखा हुआ दर्पण—सबको दिखता है, लेकिन पास जाते ही धुंधला हो जाता है। मतदान प्रतिशत का ऐलान भी किसी बॉलीवुड फिल्म के ट्रेलर जैसा है—पहले झलक दिखा दी, फिर कई दिन बाद असली आंकड़ा आया, और कभी-कभी तो दूसरा ट्रेलर पहले से लंबा निकल आया। जनता पूछती है कि जब बूथ पर वोट तुरंत गिन लिया जाता है, तो फिर प्रतिशत बताने में हफ्ता क्यों लगता है? आयोग का जवाब होता है—"हमारे ऐप पर सब था।" पर जनता सोचती है, जब शादी का कार्ड छपने से पहले सोशल मीडिया पर फोटो लाइव हो जाती है तो मतगणना का डेटा क्यों लटक जाता है?

अब आइए ईवीएम और वीवीपैट पर। आयोग का तर्क है कि मशीनें बिल्कुल सुरक्षित हैं। जनता कहती है—"हमें भी भरोसा है, पर पर्ची दिखा दीजिए।" आयोग कहता है—"पाँच बूथ काफी हैं।" यह वैसा ही है जैसे कोई दुकानदार हर सौ किलो आटे में से सिर्फ पाँच दाने तौलकर कह दे—"लो, साबुत निकले, अब बाकी पर भरोसा कर लो।" सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सौ प्रतिशत मिलान जरूरी नहीं, लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र में भरोसा केवल मशीन से नहीं आता, भरोसा जनता की आँखों से आता है। अगर जनता देखना चाहती है तो दिखाइए, आखिर छुपाना किस बात का है?

आयुक्तों की नियुक्ति का हाल और भी मज़ेदार है। पहले कहा जाता था कि यह नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए। फिर एक नया कानून आया और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ही बाहर कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक मंत्री मिलकर तय करेंगे कि आयोग में कौन बैठेगा। यानी परीक्षा की कॉपी जाँचने वाला मास्टर खुद ही अपने पसंदीदा परीक्षार्थी को पास कराएगा। क्या ही निष्पक्षता है! विपक्ष के नेता की मौजूदगी बस औपचारिक है, वैसे ही जैसे शादी में बारात में आया कोई दूर का चाचा—बस दिखावे के लिए बैठा है, बाकी सारा खेल बड़े-बड़े काका निपटा लेते हैं।

आचार संहिता लागू करने में भी आयोग की अपनी "दृष्टि" है। कोई नेता ज़रा सी टिप्पणी कर दे तो नोटिस झट से चला जाता है। लेकिन वही बात अगर सत्ता पक्ष का नेता कर दे तो आयोग पहले गहरी ध्यान-स्थिति में चला जाता है, फिर योग निद्रा में और अंततः भूलने की बीमारी में। जनता कहती है कि आयोग सब पर बराबर डंडा चलाए, पर आयोग लगता है जैसे किसी शादी में नाचते हुए डीजे पर डंडा तभी चले जब वह पड़ोसी मोहल्ले का हो, घर के बाराती तो चाहे पटाखा फोड़ें, चाहे लाउडस्पीकर बजाएँ, सब मान्य है।

चुनाव चिन्ह और पार्टी विभाजन पर फैसले भी गजब के होते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के मामले में आयोग के निर्णय ऐसे लगे मानो पहले से पटकथा लिखी जा चुकी हो। जनता ने तंज कसा कि आयोग अब चुनाव का नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों का "संपत्ति-विभाजन अधिकारी" बन गया है। किसे पार्टी का नाम मिलेगा, किसे चुनाव चिन्ह—यह सब वैसे तय हुआ जैसे परिवार की जायदाद बंटती है। फर्क बस इतना कि अदालत की जगह अब आयोग बैठा है और फैसला किसके पक्ष में जाएगा, यह जनता पहले से जान लेती है।

असल संकट यह नहीं कि आयोग गलत कर रहा है या सही। असल संकट यह है कि जनता अब मानने लगी है कि आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। लोकतंत्र में धारणा ही सबसे बड़ी हकीकत होती है। अगर जनता को यकीन हो जाए कि वोट डालना महज औपचारिकता है, तो वह लोकतंत्र का उत्सव छोड़ कर अपने कमरे में क्रिकेट मैच देखने लग जाएगी। और अगर वोट डालने वाली कतारें छोटी होने लगीं तो लोकतंत्र की नींव खुद-ब-खुद हिल जाएगी।

सुधार की बातें खूब होती हैं, लेकिन असलियत यह है कि सुधार की ज़रूरत आयोग से ज्यादा उसकी सोच में है। मतदाता सूची से नाम हटाना अगर जरूरी है तो उसे दोहरी पुष्टि से कीजिए। मतदान प्रतिशत अगर तय समय में घोषित किया जा सकता है तो नियम बना दीजिए। ईवीएम सुरक्षित हैं तो पर्ची दिखाने से डर क्यों? नियुक्तियाँ अगर निष्पक्ष हैं तो न्यायपालिका को बाहर क्यों किया? आचार संहिता अगर सब पर लागू होती है तो नोटिस का रंग सत्ता के हिसाब से क्यों बदल जाता है?

लोकतंत्र एक जादुई शब्द है। यह तभी तक चमकता है जब तक जनता का भरोसा कायम रहता है। भरोसा टूटा तो लोकतंत्र का दीपक भी बुझ जाएगा। चुनाव आयोग के लिए यह समय है कि वह अपनी छवि बचाए। क्योंकि संस्थाएँ अपनी शक्ति सत्ता से नहीं, जनता से लेती हैं। सत्ता अस्थायी है, लेकिन जनता स्थायी है। आयोग यदि जनता का विश्वास खो देगा तो वह संवैधानिक ढांचे में केवल एक मुहर बनकर रह जाएगा। आज आयोग के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है—क्या वह सचमुच लोकतंत्र का रेफरी है या सत्ता का बारातबाज़? रेफरी अगर सीटी सही समय पर नहीं बजाएगा तो खेल मैदान में ही तय नहीं होगा, बल्कि इतिहास में तय होगा। और इतिहास उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करता जिन्होंने लोकतंत्र की पवित्रता को दांव पर लगाया।

कानपुर में प्रेमिका के भाई ने दोस्तों संग मिलकर की 16 साल के कुलदीप की हत्या, गिरफ्तार

सुनील बाजपेई

कानपुर। प्यार के बुखार में 16 साल के एक लड़के की हत्या करवा दी । इस घटना को उसकी प्रेमिका के भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया था । पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रेम प्रसंग में हुई इस घटना का संबंध पनकी थाना क्षेत्र से है। यहां कुलदीप निषाद (16) की हत्या का मामला प्रेम प्रसंग का पाया गया है। उसका शव 13 अगस्त को कानपुर देहात के शिवली क्षेत्र में मिला था।

जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया इस मामले में तीन आरोपियों- पवन, नवीन और कौशल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक कुलदीप का पवन की बहन से प्रेम प्रसंग था। इसके लिए उसने कई बार कुलदीप को मना भी किया था, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद तीनों आरोपियों ने कुलदीप को कार से अगवा किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।

परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि कुलदीप हंस विद्या मंदिर में आठवीं का छात्र था और पढ़ाई के साथ-साथ कैंब्रिज चौराहे के पास पानी के बताशे का ठेला भी लगाता था। 13 अगस्त की रात को लौटते समय उसका अपहरण हुआ था। जिसकी रिपोर्ट पनकी थाने में दर्ज कराई गई थी । इसके अगले दिन ही सुबह उसका शव शिवली क्षेत्र में उसकी लाश बरामद हुई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

संविधान का 130 वाँ संशोधन विधेयक, 2025- मंत्रियों के स्तरपर होने वाले भ्रष्टाचार पर सख़्ती से अंकुश लगाने में मील का पत्थर साबित होगा

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

भारतीय स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में 129 बार संविधान संशोधन किए गए हैं और हर बार इनका उद्देश्य लोकतंत्र को मज़बूत करना, जनकल्याण को सुनिश्चित करना और शासन प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना रहा है।वर्ष 2025 में पेश किया गया संविधान (130 वां संशोधन विधेयक) इसी कड़ी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका मुख्य उद्देश्य मंत्रियों के स्तरपर होने वाले भ्रष्टाचार पर सख्ती से अंकुश लगाना है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र,ऐसा मानता हूं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी यदि भ्रष्टाचार उच्च पदस्थ नेताओं और मंत्रियों तक फैला है, कि 10 पेसेंट 20 पेसेंट नामों से उनका संज्ञान लिया जाता है,जो न केवल लोकतंत्र के लिए चुनौती है बल्कि जनता के विश्वास पर भी गहरी चोट है।यही कारण है कि इस विधेयक ने राजनीतिक विमर्श में हलचल मचा दी है।भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में भ्रष्टाचार हमेशा से सबसे गंभीर समस्या रहा है।1960 और 1970 के दशक से लेकर आज तक कई बड़े घोटाले हुए,चाहे वह बोफोर्स हो,कोयला घोटाला हो, 2जी स्पेक्ट्रम,या फिर हाल के वर्षों में विभिन्न मंत्रालयों में सामने आए अनियमितताओं के मामले।अक्सर जनता यह आरोप लगाती रही है कि "कानून केवल छोटे अपराधियों के लिए है, बड़े नेताओं और मंत्रियों पर कभी हाथ नहीं डाला जाता।"यह धारणा लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करती है।संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 75 और 164 में मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की थी,परंतु उनके खिलाफ भ्रष्टाचार-रोधी तंत्र को पर्याप्त दाँत-पंजे नहीं दिए गए।मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कभी सीबीआई,कभी लोकपाल, कभी सीवीसी का सहारा लिया गया, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रक्रिया की जटिलताओं के कारण "न्याय" अक्सर विलंबित हुआ। इसी पृष्ठभूमि में 130 वां संशोधन लाया गया, जो पहली बार संविधान में विशेष प्रावधानों के तहत मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर सीधी कार्रवाई की गारंटी देता है।गृह व सहकारिता मंत्री ने विधेयक पेश करने के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का आग्रह किया, 21 अगस्त 2025 को संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

साथियों बात अगर हम संविधान (130 वां संशोधन) विधेयक 2025 को समझने की करें तो,यह विधेयक 20 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किया गया।सेक्शन वाइज वअन्य संलग्न जानकारीः-(अ) उद्देश्य और नैतिकता को संवारनाः -विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरती नैतिकता को सुधारना, राजनीतिक नेतृत्व में पारदर्शिता लाना, और यह सुनिश्चित करना है कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मंत्री (प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री) जेल से सरकार न चला सकें। (ब) संविधान के अनुच्छेदों में संशोधनः-यह विधेयक निम्नलिखित अनुच्छेदों में संशोधन प्रस्तावित करता है,(1) अनुच्छेद 75 (केंद्र के मंत्रिमंडल)- प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के लिए लागू।(2) अनुच्छेद 164 (राज्य के मंत्रिमंडल) -मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों पर लागू। (3) अनुच्छेद 239AA (दिल्ली विधान सभा और मंत्रिमंडल)-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए लागू।संशोधन का उद्देश्य इन पदों पर बैठे नेताओं को गहन आरोपों के बीच पद में बने रहने से रोकना है (4) मुख्य प्रावधानः-यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री लगातार 30 दिनों तक गंभीर अपराधों (5 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध) के आरोप में गिरफ्तार या हिरासत में रहता है, तो उसे पद से हटाया जाएगा। केंद्रीय स्तरः- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे 31वें दिन पद से हटाएगा; यदि सलाह न दी जाए, तो वह स्वयं पर से अपने आप पदमुक्त हो जाएगा।राज्य स्तरः-राज्यपाल,मुख्यमंत्री की सलाह पर हटाएगा; सलाह न आने पर 31वें दिन स्वतः पद समाप्त मान लिया जाएगा।दिल्ली/केंद्रशासित प्रदेशः इसी तरह, उप-गवर्नर की ओर से हटाव का प्रावधान है। (5) पुनर्नियुक्ति की संभावनाः-यह विधेयक पुनर्नियुक्ति को निषिद्ध नहीं करता। गिरफ्तारी और हिरासत समाप्त होने के बाद पुनः नियुक्ति (फिर से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बनना) संभव है। (6) कानूनी और संवैधानिक चिंताएँ:-न्याय की अधिभारः यह प्रावधान निर्दोष मान्यीकरण के सिद्धांत (प्रेन्सुम्प्शन ऑफ़ इनोसेंस) का उल्लंघन कर सकता है क्योंकि अभियोग के दौरान ही हटाव संभव है, जबकि वर्तमान व्यवस्था में केवल दोषसिद्धि पर पदावसान होता है ।राजनीतिक दुरुपयोग का खतराः विपक्ष का दावा है कि यह विधेयक केंद्रीय एजेंसियों (जैसे सीबीआई, ईडी) के जरिए राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है ।संघीय ढांचे पर असरः यह राज्यों की स्वायत्तता और केंद्र-राज्य संबंधों के संतुलन को प्रभावित कर सकता है, जिससे संघीयता कमजोर हो सकती है। (7) संसदीय प्रक्रिया और वृहद प्रतिक्रियाः-विधेयक को संसद के दो सदनों में विशेष (2/3) बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक है; फिलहाल एनडीए की संख्या पर्याप्त नहीं है, इसीलिए बिना विपक्ष के समर्थन के पारित होना कठिन है।

साथियों बात अगर हम,यह विधेयक लाने कीआवश्यकता और उसकी विशेषताओं की करें तो,इस संशोधन की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि अब तक मंत्रियों के खिलाफ मामलों में

राजनीतिक दबाव हावी रहता था। जांच एजेंसियाँ निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाती थीं। इसके अलावा, कई बार "नैतिक जिम्मेदारी" के नाम पर मंत्री इस्तीफा देते तो थे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से बच निकलते थे। जनता का गुस्सा और असंतोष यही दिखाता है कि केवल इस्तीफा पर्याप्त नहीं है, बल्कि कानूनी दंड और संवैधानिक बाध्यता भी ज़रूरी है।130वें संशोधन की प्रमुख विशेषताएँ:- इस संशोधन में कई व्यापक प्रावधान जोड़े गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं,(1) संवैधानिक दायित्व की स्पष्टता- अब हर मंत्री को शपथ लेते समय यह लिखित घोषणा करनी होगी कि वह भ्रष्टाचार, भाई- भतीजावाद और किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता में संलिप्त नहीं होगा। (2) विशेष जांच आयोग का गठन-संशोधन के तहत मंत्रियों के खिलाफ आने वाली शिकायतों की जाँच हेतु संसद द्वारा एक स्वतंत्र संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग न तो प्रधानमंत्री और न ही किसी मुख्यमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होगा। (3) सीधी जवाबदेही संसद और विधानसभाओं को-यदि किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित होता है, तो उसे तुरंत पद से हटाना अनिवार्य होगा। (4) लोकपाल और न्यायपालिका से समन्वय-यह संशोधन मौजूदा लोकपाल व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाता है तथा सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट की देखरेख में जांच सुनिश्चित करता है। (5)समयबद्ध कार्रवाई-आरोप लगने के 6 महीनों के भीतर जांच पूरी करना और दोषी पाए जाने पर 1 साल के भीतर दंड प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य होगा।

साथियों बातें कर हम इस विधेयकके विपक्ष और समर्थन मैं दी गई दलीलों की करें तो,इस विधेयक को लेकर संसद और समाज में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ आई हैं (अ) समर्थक दलों का तर्क है कि यह संशोधन जनता का विश्वासलौटाने का काम करेगा और मंत्रियों को "जवाबदेही" का असली एहसास कराएगा।इससे न केवल शासन व्यवस्थापारदर्शी बनेगी बल्कि भ्रष्टाचार के मामलों में राजनीतिक संरक्षण भी खत्म होगा। (ब) विपक्षी दलों की चिंताएँ हैं कि इस संशोधन का दुरुपयोग हो सकता है। किसी भी मंत्री को झूठे आरोप लगाकर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत फँसाया जा सकता है। इसके अलावा, यह भी आशंका जताई जा रही है कि जांच आयोग पर भी सत्तारूढ़ दल का अप्रत्यक्ष प्रभाव रह सकता है। आलोचनाएँ और चुनौतियाँ:-(1)भले ही उद्देश्य नेक है, लेकिन इस संशोधन के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ होंगी। (2) राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की आशंका (3) जांच आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न (4) न्यायालय में लंबित रहने वाली अपीलें (5) जनता की अपेक्षाओं और व्यावहारिक परिणामों के बीच अंतर बंनकर उभरा है।

साथियों बातें अगर हम इस विधेयक के दूरगामी परिणामों की करें तो (1)भ्रष्टाचार की लागत बढ़ेगी-अब मंत्री भ्रष्टाचार करने से पहले सौ बार सोचेंगे क्योंकि परिणाम सिर्फ पद से हटना नहीं बल्कि कानूनी दंड भी होगा।(2) नौकरशाही पर भी असर- जब मंत्रियों को कठोर जवाबदेही के दायरे में लाया जाएगा,तो नौकरशाही पर भी पारदर्शिता का दबाव बढ़ेगा।(3)ऐतिहासिक घोटालों का विश्लेषण(4)विपक्ष की दलीलों का गहन मूल्यांकन (5)जनता और मीडिया की भूमिका (6) भ्रष्टाचार पर रोकथाम के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव।

अतः अगर हम अपरोध पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि संविधान का 130 वां संशोधन विधेयक,2025-मंत्रियोंके स्तरपर होने वाले भ्रष्टाचार पर सख़्ती से अंकुश लगाने में मील का पत्थर साबित होगा,भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तरपर भारत की छवि"जवाबदेह लोकतंत्र"की बनेगी संविधान का 130 वां संशोधन विधेयक, 2025- राज्य के मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक घेरे में-भारतीय राजनीति में एक नया युग आएगा।

टाटा हैरियर ईवी से हुए हादसे में शख्स की मौत, टाटा मोटर्स ने दिया जवाब

नई दिल्ली टाटा हैरियर ईवी के समन मोड से जुड़ी एक दुखद घटना सामने आई है जिसमें तमिलनाडु में एक व्यक्ति की जान चली गई। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैसे ढलान पर लुढ़कती कार ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद पीड़ित को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। टाटा मोटर्स ने दुख व्यक्त किया है और मामले की जांच कर रही है।

नई दिल्ली। हाल के समय में आने वाली गाड़ियां चलती-फिरती गैजेट्स की तरह हैं। इनमें कई सॉफ्टवेयर-बेस्ड फंक्शन होते हैं। इसका एक उदाहरण नई Tata Harrier EV है, जो कई ऐसे फीचर्स से भरी है, जिनकी उम्मीद 5 साल पहले तक मास-मार्केट कारों में नहीं की जा सकती थी। इसे जून 2025 में लॉन्च किया गया है। इसमें एक खास फीचर Summon mode दिया गया है। यह ऑटोनॉमस फीचर है जो आपको ड्राइवर की सीट पर किसी के बिना भी कार को थोड़ी दूरी के लिए रिमोट से बुलाने की सुविधा देता है। हाल में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि इन समन मोड की वजह से एक शख्स की जान चली गई। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

तमिलनाडु में Tata Harrier EV से एक व्यक्ति की मौत

Redit पर हाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें Harrier EV एक व्यक्ति के ऊपर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। यह घटना तमिलनाडु के अविनाशी की बताई जा रही है। इस घटना में पीड़ित को सिर में गंभीर चोट लगी। वीडियो में हैरियर ईवी एक ढलान से नीचे लुढ़कती हुई दिख रही है, जबकि ड्राइवर दरवाजा खुलने के बाद भी अंदर नहीं बैठ पाया था। सीसीटीवी के फुटेज में तारीख 14 अगस्त 2025 की शाम 5:53 बजे का है।

Redit पर पोस्ट के अनुसार, उस व्यक्ति ने कार में अंदर जाकर ब्रेक लगाकर वाहन को रोकने की कोशिश की। हालांकि, भारी एसयूवी के मोमेंटम ने व्यक्ति को बाहर खींच लिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और सिर में गंभीर चोट लगी। पीछे जाते समय वाहन उसके पैरों के ऊपर से गुजर गया। कार एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर से गुजरने वाली थी, लेकिन कुछ सतर्क लोगों ने उसे खींचकर बचा लिया।

घटना के बाद उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। रिवार अभी तक सदमे में है, और उन्होंने टाटा मोटर्स के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की है। कंपनी के अधिकारियों ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का सही कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, और यह भी पुष्टि नहीं हुई है कि यह किसी तकनीकी खराबी, मानवीय त्रुटि या बाहरी कारकों के कारण हुआ है। रेडिट पोस्ट का दावा है कि मृतक को पहले भी इस नई कार में सॉफ्टवेयर की समस्या का सामना करना पड़ा था, जब वह सड़क पर रुक गई थी और स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसे शोरूम में फोन करना पड़ा था और तकनीशियनों को आकर वाहन को स्टार्ट करने में मदद करनी पड़ी थी।

टाटा मोटर्स का आधिकारिक बयान

टाटा मोटर्स ने इस मामले पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि हमें इस दुखद दुर्घटना के बारे में जानकारी मिली और हम इस नुकसान से बहुत दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतक के परिवार के साथ हैं। हम फिलहाल सभी प्रासंगिक तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं। ऑनलाइन/सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो से प्रारंभिक अवलोकन यह बताते हैं कि वाहन ढलान से गुरुत्वाकर्षण के कारण पीछे की ओर लुढ़का हो सकता है और किसी अज्ञात वस्तु से टकराकर वापस उछला हो, जिससे यह पता चलता है कि मोटर चालू नहीं थी। वाहन अभी भी परिवार के पास है और घटना के बाद से उसे चलाया गया है, और हमें अभी तक इसका निरीक्षण करने का मौका नहीं मिला है।

Tata Harrier EV के फीचर्स

इसमें कई बेहतरीन एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसमें ADAS सूट के हिस्से के रूप में कई ऑटोनॉमस फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें 2 ऑटोनॉमी भी शामिल है। इसमें ऑटो पार्क असिस्ट (समन मोड के साथ), रिवर्स असिस्ट, और एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, और ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी विभिन्न ADAS फंक्शनलिटी मिलती है। हैरियर ईवी में 540-डिग्री कैमरा सिस्टम भी है, जो बोनट का पारदर्शी व्यू प्रदान करता है और स्थिति के बारे में जानकारी बढ़ाता है।

जानें कैसी है भारत की सबसे सस्ती क्रूज कंट्रोल वाली बाइक, देखें वीडियो

परिवहन विशेष न्यूज

2025 हीरो ग्लैमर एक्स वीडियो समीक्षा नई ग्लैमर को भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया है। यह भारत की सबसे सस्ती क्रूज कंट्रोल वाली बाइक है और 125cc सेगमेंट में पहली है। इसमें तीन राइड मोड LED लाइटिंग USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और डिजिटल LCD क्लस्टर जैसे फीचर्स हैं। जागरण हाई-टेक टीम ने इसे चलाकर देखा और इसका वीडियो रिव्यू किया है।

नई दिल्ली। 2025 हीरो ग्लैमर एक्स 125 को भारतीय बाजार में हाल ही में लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च होते ही भारत की सबसे सस्ती क्रूज कंट्रोल वाली बाइक बन गई है। वहीं, यह क्रूज कंट्रोल के साथ आने वाली 125cc सेगमेंट की पहली बाइक है। इसे कई बेहतरीन फीचर्स के साथ लेकर आया गया है। इसमें इसमें तीन राइड मोड दिया गया है, जो Eco, Road, और Power है। इसके साथ ही फुल LED लाइटिंग, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, और फुली डिजिटल LCD क्लस्टर के साथ 60+ फंक्शन्स जैसे टैर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल/एसएमएस अलर्ट्स, गियर इंडिकेटर, फ्यूल एफिशिएंसी डेटा, रेंज टू एम्प्टी, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। हाल ही में इस बाइक को हमारी जागरण हाई-टेक की टीम को चलाने का मौका मिला। चलाने में यह मोटरसाइकिल कैसी है। वीडियो में देखा जा सकता है।

ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC की कीमत 27 हजार घटी, पावरफुल इंजन और दमदार फीचर्स से है लैस

ब्रिक्सटन मोटरसाइकल्स ने अपनी फ्लैगशिप स्क्रैंबलर Brixton Crossfire 500XC की कीमतों में 27499 रुपये की कटौती की है जिससे इसकी एक्स-शोरूम कीमत 492000 रुपये हो गई है। 486cc इंजन KYB सस्पेंशन और BOSCH ABS जैसे फीचर्स के साथ यह बाइक स्टाइल और परफॉर्मेंस का मिश्रण है। यह कोल्हापुर में स्थानीय रूप से असेंबल की गई है और ऑफ-रोड और शहरी सड़कों के लिए उपयुक्त है।

नई दिल्ली। ब्रिक्सटन मोटरसाइकल्स ने अपनी फ्लैगशिप स्क्रैंबलर Brixton Crossfire 500XC की कीमतों में कटौती की है। इस कदम से यह एडवेंचर-रेडी मशीन भारत में बाइक चलाने वालों के लिए एक और भी आकर्षक ऑप्शन बन गई है। इसकी कीमत में कमी करने के अलावा बाकि किसी और चीज में बदलाव नहीं किया गया है। आइए इसकी नई कीमत और मिलने वाले फीचर्क के बारे में विस्तार में जानते हैं।

Brixton Crossfire 500XC की नई कीमत

ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500XC को पहले 5,19,499 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में ऑफर किया जाता था। अब इसकी कीमत में 27,499 रुपये की कटौती की गई है। इसके बाद अब इसे भारत में 4,92,000 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में ऑफर किया जा रहा है। इस बाइक को उन राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों की मांग करते हैं। ऑस्ट्रियाई इंजीनियरिंग के प्रभाव के साथ एक ग्लोबल स्क्रैंबलर के रूप में इसे डिजाइन किया गया है और कोल्हापुर में स्थानीय रूप से असेंबल की गई, 500XC एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो मजबूत परफॉर्मेंस को आकर्षक डिजाइन के साथ मिलाती है।

Brixton Crossfire 500XC के फीचर्स

ब्रिक्सटन क्रॉसफायर 500 XC एक मजबूत और बहुमुखी स्क्रैंबलर है। इसमें 486cc लिक्विड-कूल्ड, दो-सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 47 hp की पावर और 43 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें KYB एडजस्टेबल सस्पेंशन, BOSCH ABS, J. J. Juan डिस्क ब्रेक और Pirelli Scorpion Rally STR टायरों के साथ, यह ऑफ-रोड रास्तों और शहर की सड़कों दोनों को आसानी से संभालने के लिए बनाई गई है। इसमें 13.5L का फ्यूल टैंक, 195 kg का कर्ब वेट और 839 mm की सीट की ऊंचाई है, जो आराम और स्थिरता सुनिश्चित करती है। इसका डेजर्ट गोल्ड मैट फिनिश और सिग्नेचर एक्स-आकार का फ्यूल टैंक डिज़ाइन इसे ब्रिक्सटन की खास पहचान देते हैं।

सिर्फ 50 प्रतिशत रकम देकर ट्रैफिक चालान भरने का मौका, सरकार ने दी इतने दिनों की मोहलत

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने 23 अगस्त से 12 सितंबर तक लंबित ट्रैफिक जुर्माने पर 50% छूट दी है। कर्नाटक सरकार द्वारा अनुमोदित इस नीति का उद्देश्य वाहन चालकों को बकाया चुकाने में मदद करना है।

नई दिल्ली। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने 23 अगस्त से 12 सितंबर तक सभी लंबित ट्रैफिक जुर्माने पर 50 प्रतिशत की छूट की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार के जरिए अनुमोदित, इस नीति का उद्देश्य वाहन चालकों को सस्ती दर पर बकाया चुकाने और कानूनी कार्रवाई से बचने में मदद करना है। इस आदेश में कहा गया है कि यह छूट पुलिस द्वारा दर्ज किए गए सभी लंबित ई-चालान पर लागू है। इस सीमित समय सीमा के दौरान, वाहन चालक मूल जुर्माने का आधा भुगतान करके अपना बकाया को चुका सकते हैं।

ट्रैफिक चालान भुगतान के ऑप्शन

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने भुगतान करने के लिए कई तरीके के बारे में बताया है। जो निम्नलिखित है-

कर्नाटक राज्य पुलिस (KSP) ऐप का इस्तेमाल करके।।

बेंगलुरु ट्रैफिक डिवीजन के जरिए शुरू किए गए BTP ASTraM ऐप का इस्तेमाल करके।

निकटतम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पर जाकर वाहन पंजीकरण संख्या बताकर।

ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर पर जाकर किया जा सकता है।

कर्नाटक वन या बेंगलुरु वन वेबसाइटों के जरिए।

वाहन चालकों को सलाह

पेंडिंग ई-चालान पर 50% की छूट की घोषणा के साथ ही वाहन चालकों को सलाह दी घई है कि वह अपने वाहन पंजीकरण संख्या को चेक करके किसी भी बकाया ट्रैफिक चालान का पता लगाएं और 12 सितंबर को समय सीमा खत्म होने से पहले उसका भुगतान कर दें। यह योजना केवल मोबाइल ई-चालान प्रणाली के माध्यम से दर्ज किए गए लंबित जुर्माने पर लागू होती है। इसमें पुराने परिवहन विभाग के मामले शामिल नहीं हैं।

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने किया पोस्ट

बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह छूट वाहन मालिकों को राहत प्रदान करने के साथ-साथ सभी को अपना बकाया चुकाने और यातायात अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। आइए, हम सब मिलकर एक सुरक्षित और अधिक जिम्मेदार बेंगलुरु की दिशा में आगे बढ़ें।

ऐसे 2023 में वसूल चुके हैं 5.6 करोड़ रुपये

बेंगलुरु में वाहनों की बढ़ती संख्या और सीमित सड़क बुनियादी ढांचे के कारण यातायात उल्लंघन के मामले बढ़ रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अकेले 2024 में शहर में 8.29 मिलियन से अधिक यातायात उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए। इनमें सिग्नल जंपिंग, गलत पार्किंग, तेज गति और खतरनाक ड्राइविंग जैसे अपराध शामिल थे। सबसे ज्यादा मामले दोपहिया वाहनों से थे, जिनकी संख्या लगभग 5.85 मिलियन थी। इसी तरह की छूट देकर बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस को साल 2023 में दो लाख से अधिक उल्लंघन मामलों को निपटाने और 5.6 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया जुर्माने को वसूलने में मदद मिली थी।

मारुति ग्रैंड विटारा को मिले नए शानदार कलर, सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट्स में मिलेंगे ये ऑप्शन

मारुति ग्रैंड विटारा के सिग्मा डेल्टा और डेल्टा+ वेरिएंट्स में नए रंग विकल्प पेश किए हैं। सिग्मा वेरिएंट में अब नेक्सा ब्लू ग्रैंड्योर ग्रे और पर्ल मिडनाइट ब्लैक रंग भी मिलेंगे जो पहले केवल आर्कटिक व्हाइट में उपलब्ध था। डेल्टा और डेल्टा+ वेरिएंट्स में पर्ल मिडनाइट ब्लैक रंग जोड़ा गया है। इन नए कलर वेरिएंट्स की बुकिंग 21 अगस्त से शुरू हो चुकी है।

नई दिल्ली। मारुति ने हाल ही में Nexa की 10वीं सालगिरह के सेलेब्रेशन के रूप में Maruti Grand Vitara का फैंटम ब्लैक एडिशन लॉन्च किया था। अब कंपनी ने Maruti Grand Vitara के Sigma, Delta और Delta+ वेरिएंट में नए कलर ऑप्शन को लेकर आया गया है। इन कलर ऑप्शन को लेकर इसके लिए और भी स्कीम को बढ़ा दिया गया है। इन नए कलर वेरिएंट्स की बुकिंग 21 अगस्त से शुरू हो गई है।

Grand Vitara के नए कलर

ग्रैंड विटारा के बेस सिग्मा वेरिएंट में तीन नए कलर ऑप्शन को सामिल किया गया है। यह तीनों मोनोटोन कलर हैं, जो नेक्सा ब्लू, ग्रैंड्योर ग्रे और पर्ल मिडनाइट ब्लैक है। पहले सिग्मा वेरिएंट को केवल केवल आर्कटिक व्हाइट ऑप्शन में ऑफर किया जाता था। अब इसे कुल चार कलर ऑप्शन में ऑफर किया जाएगा।

डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स में पर्ल मिडनाइट ब्लैक को एक नए कलर ऑप्शन को शामिल किया गया है। इसके अलावा बाकी वेरिएंट के साथ डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट्स में अब कुल सात कलर ऑप्शन हो गए हैं। पहले Grand Vitara को नेक्सा ब्लू, स्प्लेंडिड सिल्वर, ओपुलेंट रेड, ग्रैंड्योर ग्रे, आर्कटिक व्हाइट और चेस्टनट ब्राउन कलर ऑप्शन में पेश किया जाता था।

कब से शुरू होगी डिलीवरी?

Maruti Grand Vitara के नए कलर वेरिएंट की डिलीवरी की तारीख की भी घोषणा भी कर दी गई है। डेल्टा वेरिएंट के लिए नया ब्लैक कलर अगस्त 2025 के अंत तक उपलब्ध होगा। सिग्मा वेरिएंट के लिए नए कलर सितंबर के मध्य से उपलब्ध होंगे। डुअल-टोन ऑप्शन कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में काफी लोकप्रिय हैं, क्योंकि वे गाड़ी को स्पोर्टी लुक देते हैं। ग्रैंड विटारा में आर्कटिक व्हाइट के साथ ब्लैक, स्प्लेंडिड सिल्वर के साथ ब्लैक और ओपुलेंट रेड के साथ ब्लैक जैसे डुअल-टोन ऑप्शन मिलते हैं।

कितनी है कीमत?

Maruti Grand Vitara के नए कलर ऑप्शन की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। इसके सिग्मा MT वेरिएंट की शुरुआती कीमत 11.42 लाख रुपये है। डेल्टा MT और डेल्टा AT की कीमत क्रमशः 12.53 लाख रुपये और 13.93 लाख रुपये है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन वाला डेल्टा प्लस वेरिएंट 16.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है, जो मारुति ग्रैंड विटारा का सबसे किफायती स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है।

हुंडई एक्सटर प्रो पैक वेरिएंट लॉन्च, नया कलर ऑप्शन समेत मिले शानदार फीचर्स

हुंडई ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी Hyundai Exter Pro Pack को नए कॉस्मेटिक बदलावों डैशकैम और नए रंग विकल्प के साथ लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.98 लाख रुपये है। एक्सटर प्रो पैक में व्हील आर्च क्लैडिंग और एक नई साइड सिल गार्निश दी गई है। इसमें टाइटैन ग्रे मैट एक्सटीरियर रंग विकल्प भी मिलता है। SX(O) AMT वेरिएंट में डैशकैम भी मिलेगा।

नई दिल ली। हुंडई ने अपनी पॉपुलर SUV Hyundai Exter Pro Pack को लॉन्च किया है। इस प्रो पैक में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव, डैशकैम और एक नया कलर ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7.98 लाख रुपये है। आइए जानते हैं कि इसे और किन फीचर्स के साथ लॉन्च किया है?

Exter Pro Pack में क्या है नया?

एक्सटर पर नया प्रो पैक इसके रग्ड लुक को और बढ़ाता है। इसमें अधिक प्रमुख व्हील आर्च क्लैडिंग और एक नई साइड सिल गार्निश दी गई है। हुंडई ने प्रो पैक के साथ एक नया टाइटैन ग्रे मैट एक्सटीरियर कलर ऑप्शन भी पेश किया है।

इसमें दिए गए फीचर्स की बात करें, तो SX(O) AMT वेरिएंट में अब डैशकैम भी मिलेगा। पहले यह केवल SX Tech और SX Connect वेरिएंट में दिया जाता था।

बेस वेरिएंट से 5,000 रुपये महंगी

Hyundai Exter Pro Pack वेरिएंट को S+ वेरिएंट और उससे ऊपर के वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इसका मतलब है कि बेस EX, EX(O), S स्मार्ट और S वेरिएंट्स में ये एक्सेसरीज नहीं मिलेगी, जो इसमें दी जा रही है। वहीं, रेगुलर S+ मैनुअल वेरिएंट की कीमत 7.93 लाख रुपये से शुरू होती है, जिसका मतलब है कि प्रो पैक की कीमत बेस वेरिएंट से 5,000 रुपये ज्यादा है।

Hyundai Exter Pro Pack का इंजन

इस कॉम्पैक्ट SUV में और कोई बदलाव नहीं किया गया है। Exter में दिया जाने वाला 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ही इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 83hp की पावर और 114Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स दोनों के साथ ऑफर किया जाता है। CNG स्पेसिफिकेशन में यह इंजन 69hp की पावर और 95.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ऑफर किया जाता है। इसमें डुअल-सीएनजी सिलेंडर टैंक सेटअप भी मिलता है।

महिलाओं का सशक्तिकरण एक बहु-आयामी अवधारणा है

विजय गर्ग

महिला सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो महिलाओं और लड़कियों को रणनीतिक जीवन विकल्प बनाने और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने की शक्ति और नियंत्रण प्रदान करती है। इसका उद्देश्य महिलाओं को जीवन के सभी पहलुओं में अवसरों, संसाधनों और अधिकारों तक समान पहुंच प्रदान करके लैंगिक विषमताओं को खत्म करना है।

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताओं को समाप्त करने की प्रक्रिया से है। इस शब्द ने 19 वीं शताब्दी में प्रमुखता प्राप्त की, सशक्तिकरण के साथ शक्ति को सक्षम करने या प्रदान करने के कार्य को दर्शाता है। सदियों से, महिलाओं को दुनिया भर में कमजोर लिंग माना जाता रहा है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी, महिलाओं को समान सामाजिक-आर्थिक स्थिति से वंचित रखा गया। इसे संबोधित करने के लिए, भारत सरकार और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों दोनों ने समाज में महिलाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। महिला सशक्तिकरण के प्रकार महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जिसे पांच प्रमुख प्रकारों में तोड़ा जा सकता है:

सामाजिक सशक्तिकरण: यह प्रकार महिलाओं की सामाजिक स्थिति और संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यह पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों, भेदभाव और हानिकारक प्रथाओं को चुनौती देता है ताकि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य, विवाह और जीवन शैली के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार मिल सके।

शैक्षिक सशक्तिकरण: यह एक मूलभूत प्रकार है जो लड़कियों और महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करता है। आत्मविश्वास बढ़ाने, आत्मनिर्भरता में सुधार और महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है।

आर्थिक सशक्तिकरण: इसमें महिलाओं को आर्थिक संसाधनों, रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करना शामिल है। वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं को अपने अधिकारों का दावा करने, अपने निर्णय लेने और अपने घर और समुदाय की आर्थिक भलाई में योगदान करने की अनुमति देती है।

राजनीतिक सशक्तिकरण: यह प्रकार सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार और क्षमता हो। इसमें शासन, मतदान और सार्वजनिक कार्यालय में एक कहना शामिल है, जो उन नीतियों को आकार देने में मदद करता है जो महिलाओं के लिए फायदेमंद हैं।

मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण: यह महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के निर्माण के बारे में है। यह उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक वर्जनाओं को दूर करने और समाज में उनसे जो उम्मीद की जाती है उसे चुनौती देने का साहस

हासिल करने में मदद करता है। महिला सशक्तिकरण को प्राप्त करने में कठिनाइयाँ प्रगति के बावजूद, महत्वपूर्ण चुनौतियां विश्व स्तर पर महिला सशक्तिकरण में बाधा डालती हैं। कुछ प्रमुख कठिनाइयों में शामिल हैं:

सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड: गहराई से अंतर्वर्धित पितृसत्तात्मक विश्वास और सामाजिक रीति-रिवाज अक्सर महिलाओं की भूमिकाओं को निर्धारित करते हैं, उनकी स्वतंत्रता और अवसरों को सीमित करते हैं। बाल विवाह, महिला जननांग विकृति और दहेज जैसी प्रथाएं अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में प्रचलित हैं।

आर्थिक असमानता: महिलाओं को अक्सर एक महत्वपूर्ण वेतन अंतर, व्यावसायिक अलगाव और वित्तीय संसाधनों और संपत्ति के स्वामित्व तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है। यह आर्थिक असमानता उनके लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना और गरीबी के चक्र से बचना मुश्किल बना देती है।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की कमी: गरीबी, सांस्कृतिक परंपराओं या प्रारंभिक विवाह के कारण लाखों लड़कियों को शिक्षा तक पहुंच से वंचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को अक्सर खराब स्वास्थ्य सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित।

लिंग आधारित हिंसा: यह एक व्यापक मुद्दा है जिसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और मानव तस्करी शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की उच्च दर असुरक्षा और भय की निरंतर भावना पैदा करती है, जिससे सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने की उनकी क्षमता बाधित होती है।

सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व: महिलाओं को अक्सर राजनीतिक नेतृत्व और निर्णय लेने वाले निकायों में कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। प्रतिनिधित्व की इस कमी का मतलब है कि उनकी अनूठी जरूरतों और दृष्टिकोणों को अक्सर नीति और कानून में पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा सबसे व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है। यह महिलाओं की शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक भलाई को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जिससे लैंगिक समानता प्राप्त करने में बाधाएं पैदा होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों से 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 15.3% की वृद्धि हुई है। घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, तस्करी और ऑनर किलिंग महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा को कमजोर करती रहती हैं।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा कई रूप लेती है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सीमाओं को काटती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सबसे प्रचलित प्रकारों में से कुछ हैं:

घरेलू हिंसा: सबसे व्यापक रूपों में से एक, घरेलू हिंसा में एक अंतरंग साथी द्वारा मौखिक, गैर-मौखिक, शारीरिक, यौन, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार शामिल हैं। महिला शिशु / महिला हत्या: यह एक लड़की के बच्चे की जानबूझकर हत्या को संदर्भित करता है, या तो जन्म से पहले (सेक्स-चयनात्मक गर्भपात के माध्यम से) या जन्म के बाद, सिर्फ इसलिए कि वह महिला है। ऑनर किलिंग: ऑनर किलिंग में अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा एक महिला की हत्या शामिल है, जिसे अक्सर परिवार के तथाकथित सम्मान को संरक्षित करने के रूप में उचित ठहराया जाता है। ऑनलाइन हिंसा / साइबर अपराध: महिलाओं के लिए डिजिटल स्थान तेजी से असुरक्षित हैं। इस श्रेणी में साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, मॉर्फ्ड या अंतरंग छवियों का प्रचलन और प्रौद्योगिकी-सक्षम दुरुपयोग के अन्य रूप शामिल हैं। यौन हिंसा: इस श्रेणी के कई रूप हैं: यौन उत्पीड़न: अवांछित शारीरिक संपर्क, यौन टिप्पणियां, एहसान की मांग, या पीछा करना। बलात्कार: यौन प्रवेश का एक गैर-सहमति कार्य। मानव तस्करी: लाखों महिलाएं और लड़कियां तस्करी का शिकार होती हैं, जिन्हें अक्सर जबरन श्रम या यौन शोषण में धकेल दिया जाता है। (और पढ़ें: अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम) बाल विवाह: 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी को बाल विवाह के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का उल्लंघन करता है और शोषण और दुरुपयोग के आजीवन जोखिम के लिए लड़कियों को उजागर करता है। महिला सशक्तिकरण योजनाएं (भारत) भारत सरकार ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं:

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी): यह योजना बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में गिरावट को संबोधित करती है और इसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना है। यह सामाजिक मानसिकता को बदलने और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है।

प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना ( ): यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जो अपने पहले जीवित बच्चे के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मां और नवजात शिशु दोनों के लिए उचित पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।

वन-स्टॉप सेंटर (ओएससी) योजना: ये केंद्र सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता और सहायता प्रदान करते हैं। सेवाओं में चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय और मनोवैज्ञानिक परामर्श शामिल हैं।

महिला शक्ति केंद्र ( ) योजना: इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह उनके लिए कौशल विकसित करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंचने और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का समर्थन ( ): यह कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान करता है, जैसे कृषि, हथकरघा और हस्तशिल्प। यह उन्हें कौशल हासिल करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है।

केंद्र 'पुलिस स्टेशन'

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान के 130वें संशोधन वाले विधेयक लोकसभा में पेश किए। उनमें गंभीर और विवादास्पद प्रावधान किए गए हैं। दरअसल संविधान का बुनियादी सिद्धांत है कि जब तक किसी आरोपित को अदालत अपराधी या दोषी करार न दे, तब तक आरोपित व्यक्ति 'मासूम' है, 'निर्दोष' है, लेकिन प्रस्तावित बिल का विषय है कि कोई प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार का मंत्री 30 दिन हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन वह संवैधानिक पद के 'अयोग्य' हो जाएगा। उसे इस्तीफा देना पड़ेगा अथवा बर्खास्त कर दिया जाएगा। इन प्रावधानों को विपक्ष ने संविधान-विरोधी, न्याय-विरोधी और मौलिक अधिकार-विरोधी करार दिया है, लिहाजा कुछ विपक्षी सांसदों ने बिल की प्रतियां फाड़ी हैं और उन्हें सत्ता पक्ष की तरफ फेंका है। इसे 'राक्षसी बिल' भी करार दिया गया है। गृहमंत्री की दलील है कि यह बिल सरकार और राजनीति में नैतिकता और शुद्धिकरण के मद्देनजर लाया गया है। यह अद्र्धसत्य है, क्योंकि भाजपा में ऐसे कई नेता शामिल किए गए, जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे थे, लेकिन बाद में एजेंसियों ने उन्हें धूमिल कर दिया। ऐसे नेता मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक हैं। बहरहाल संसद में हंगामे और विरोध को देखते हुए संविधान संशोधन बिल संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने की घोषणा की गई। समिति में 21 सांसद लोकसभा और 10 सांसद राज्यसभा के होंगे। बेशक अधिक सांसद सत्ता पक्ष के होंगे, लिहाजा बुनियादी बिल में ज्यादा संशोधनों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जेपीसी को संसद के शीत सत्र के पहले दिन तक रपट सौंपने को कहा गया है। विषय का विश्लेषण करने से पूर्व एडीआर की रपट गौरतलब है कि 2024 के संसदीय चुनाव में जो सांसद लोकसभा के लिए चुने गए थे, उनमें से करीब 46 फीसदी पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में यह औसत 30 फीसदी था। सर्वोच्च अदालत के 'न्यायालय मित्र' ने उसे बताया है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ करीब 5000 आपराधिक मामले अब भी लंबित हैं। इस डाटा के मद्देनजर भी ऐसा संविधान संशोधन बिल संसद में पेश करना अपेक्षित और स्वीकार्य नहीं है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग भूमिकाएं संविधान में तय की गई हैं।

उनके अधिकार भी तय किए गए हैं। संघीय ढांचे पर आघात नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार 'पुलिस स्टेशन' की भूमिका में नहीं आ सकती। संभव है कि बिल बनाते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल का उदाहरण केंद्र सरकार और अधिकारियों के मानस में रहा होगा! केजरीवाल को 177 दिन तक जेल में रखा गया। उनके खिलाफ न तो आरोप अदालत में तय हुए और न ही किसी अदालत ने उन्हें 'दोषी' करार दिया। ऐसे कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 माह तक जेल में बंद रखा गया। अंततः उन्हें जमानत मिली, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं किया जा सका है। दिल्ली सरकार के मंत्री रहे सत्येन्द्र जैन को 2 साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया। अंततः सीबीआई ने उनके मामले में क्लोजर रपट अदालत में पेश की और जैन को बिल्कुल बरी कर दिया गया। इन जेलबंद नेताओं की 'निर्दोषता' की भरपाई कौन करेगा? केजरीवाल ने जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा और जेल से ही सरकार चलाते रहे। संविधान में ऐसी व्याख्या ही नहीं है कि जेल में रहने वाले मुख्यमंत्री और मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अथवा राज्यपाल द्वारा उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। सरकार ने प्रस्तावित बिल में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को भी जोड़ा है। यह ड्रामा है। सवाल है कि कितने प्रधानमंत्री 30 दिन तक हिरासत में रखे गए हैं? प्रधानमंत्री रहते हुए पीवी नरसिम्हा राव को अदालत ने 'अभियुक्त' करार दिया था। उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा गया? इंदिरा को जेल जाना पड़ा। कानून लागू हो जाता है, तो किसी भी विपक्षी दल की सरकार ढहाई जा सकती है।

वैज्ञानिक को शुरुआती सबूत मिलते हैं कि ऋग्वेद ने भारत के बाहर सभ्यताओं को प्रभावित किया

विजय गर्ग

ऋग्वेद और इसके छंद, इसके संगीत नोट्स और ताल, अन्य सभ्यताओं तक पहुंचे और उन्हें कांस्य युग की अन्य संस्कृतियों में साझा किया गया। एक वैज्ञानिक ने इस बात का प्रमाण पाया है कि भूमध्य सागर में लिखे गए 3,000 वर्षीय भजन में वैदिक छंदों के साथ समानता है।

कैलिफोर्निया में वैज्ञानिकों ने शुरुआती प्रमाणों में से एक पाया है कि वैदिक संस्कृति भारत तक सीमित नहीं थी। साक्ष्य संगीत में निहित है, जैसा कि एक अध्ययन में बताया गया है कि 3,000 साल पहले भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर लिखा गया एक भजन ऋग्वेद के साथ हड़ताली समानताएं साझा करता है, जो सबसे पुराने भारतीय पवित्र ग्रंथों में से एक है। दान सी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा के बीऔऐसीआईयु, प्रीप्रींट.उआरजी सर्वर पर अपने तुलनात्मक विश्लेषण प्रकाशित किया। उनका कहना है कि उगारित और ऋग्वेद की आयतों में लिखे गए निक्कल के भजन ने एक ही ताल, या बार-बार मधुर या लयबद्ध इकाइयों को साझा किया। शोधकर्ता ने काम के दो निकायों के बीच समानताएं खींचने के लिए कंप्यूटर की सहायता प्राप्त लय और मेलोडी मैपिंग का

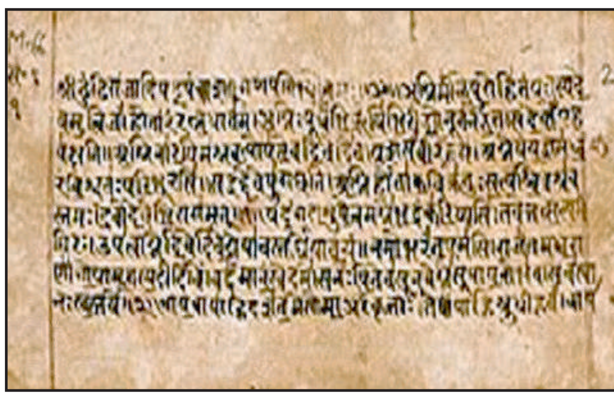

उपयोग किया। उन्होंने अपने अध्ययन में लिखा है कि पाँच ऋग्वेद में से एक आयत उसी ताल के साथ समाप्त होती है जो भजन से लेकर निक्कल तक होती है। यह पेचीदा बनाता है कि, उसके अनुसार, दुर्घटना से होने वाली इस बाधाओं को एक मिलियन में एक से कम है। भूमध्य सागर में लिखे गए एक में, दो ताल हैं - एक सरल और दिल की धड़कन की तरह, और एक और जटिल बीऐसीआईयु का कहना है कि दोनों मॉडल ऋग्वेद के छंदों में भी मौजूद हैं, 'एक सबसे अधिक बार समाप्त होने वाले छंदों के साथ और दूसरा त्रिशुभ मीटर से निकटता से जुड़ा हुआ है,'

संगीत से जुड़े राज्य, सभ्यताओं के समाप्त होने के बाद भी जीवित रहे जबकि उनमें से एक सरल है, दूसरा जटिल है, और बासीयू का कहना है कि यह जानबूझकर किया गया था। साझा लय के अलावा, गूँजती हुई मधुर प्रवृत्तियाँ भी हैं, जिन्हें ₹ऋग्वेद पर प्राचीन टिप्पणीकारों ने उच्चारण सिलेबल्स पर बढ़ते और उसके बाद गिरने के रूप में वर्णित किया।₹ एक डिजिटल पुनर्निर्माण से पता चला कि दो टुकड़े कितने चौंकाने वाले थे। बासीयू की खोज से पता चलता है कि संगीत को विभिन्न संस्कृतियों में साझा किया गया था और शाही फरमान और राजनीतिक गठबंधनों की तुलना में तेजी से फैल गया था। वास्तव में, राज्यों के गायब होने के बाद भी, संगीत कायम रहा। उगारिट ने मेसोपोटामियन और अनातोलियन संस्कृतियों को जोड़ा, और इतिहासकारों का कहना है कि मितानी साम्राज्य ने उगारित और भारत के बीच एक सांस्कृतिक पुल के रूप में कार्य किया। माना जाता है कि इस कांस्य युग के राज्य ने उस चैनल के रूप में काम किया है जिसके माध्यम से वैदिक परंपराओं और संगीत रूपों का आदान-प्रदान किया गया था। यह भी पढ़ें: मास्की शिलालेख के 110 साल बाद, कर्नाटक शहर में 4,000 साल पुरानी मानव बस्ती मिली ऋग्वेद संगीत ताल ग्रीक कविता तक पहुंचा बासीयू ने अपने पेपर में लिखा, 'मितानी ने हमें दो उपहार छोड़ दिए। भारत के बाहर वैदिक संस्कृति का पहला प्रमाण है। दूसरा यह भजन है, जो दर्शाता है कि कैसे संगीत सभ्यताओं को एकजुट करने में सक्षम था।' उनका कहना है कि संगीत की ताल फैलती चली गई, सैकड़ों साल बाद ग्रीक गीत की कविता में इसी तरह के पैटर्न देखे जा रहे थे. साफो के काम, यूरोपीय साहित्य के टुकड़े, और 1801 में जर्मन कवि फ्रेडरिक हॉल्डरलिन के छंद सभी एक ही संगीत पैटर्न ले जाते हैं। बासीयू के शोध से पता चलता है कि संगीत पहली वैश्विक भाषा थी, और उन धारणाओं को चुनौती देता है जो सभ्यता अलगाव में मौजूद थीं।

प्रतिभा के अंतर को पाटना: उद्योग और शिक्षा को हाथ में क्यों काम करना चाहिए

विजय गर्ग

कार्यबल की व्यावहारिक जरूरतों के साथ शैक्षिक पाठ्यक्रम को संरेखित करके प्रतिभा अंतर को पाटने के लिए उद्योग और शिक्षा के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। यह साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि स्नातक प्रासंगिक कौशल से लैस हों, जिससे वे अधिक प्रतिस्पर्धी और नौकरी के लिए तैयार हों। यह एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध है जहां दोनों पक्ष महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। टैलेंट गैप क्यों निकलता है प्रतिभा का अंतर तब उत्पन्न होता है जब नियोक्ताओं की आवश्यकता वाले कौशल और कौशल नौकरी चाहने वालों के बीच एक बेमेल होता है। विश्वविद्यालय, पारंपरिक रूप से सैद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, कभी-कभी तकनीकी प्रगति की तीव्र गति और उद्योग की मांगों को विकसित करने के लिए संघर्ष करते हैं। यह स्नातकों की ओर जाता है, जो मजबूत शैक्षणिक नींव होने के बावजूद, व्यावहारिक, हाथों पर अनुभव और अप-टू-डेट कौशल की कमी करते हैं जो कंपनियां ढूंढ रही हैं। उद्योग-अकादमिया सहयोग के लाभ हाथ से काम करना, कंपनियां और शैक्षणिक संस्थान एक निरंतर फीडबैक लूप बना सकते हैं जो इसमें शामिल सभी को लाभ पहुंचाता है। छात्रों और विश्वविद्यालयों के लिए

बढ़ी हुई रोजगार: छात्र इंटर्नशिप, सह-ऑप कार्यक्रमों और लाइव परियोजनाओं के माध्यम से वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। यह व्यावहारिक अनुभव उन्हें नियोक्ताओं के लिए कहीं अधिक आकर्षक बनाता है।

प्रासंगिक पाठ्यक्रम: उद्योग विशेषज्ञ पाठ्यक्रम विकास पर प्रत्यक्ष इनपुट प्रदान कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पाठ्यक्रम वर्तमान हैं और सबसे अधिक मांग वाले कौशल और प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित हैं।

संसाधनों तक पहुंच: विश्वविद्यालय अनुसंधान के लिए विशेष उपकरण, सॉफ्टवेयर और धन जैसे उद्योग संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं, जो अकादमिक संस्थानों के लिए अपने दम पर अधिग्रहण करना महंगा हो सकता है। कंपनियों और अर्थव्यवस्था के लिए

एक कुशल प्रतिभा पूल तक पहुंच: कंपनियों को नौकरी के लिए तैयार स्नातकों की एक पाइपलाइन मिलती है जिन्हें कम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, काम पर रखने और ऑनबोर्डिंग लागत को कम करना।

नवाचार और अनुसंधान एवं विकास: सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाएं कंपनियों को अकादमtकि विशेषज्ञता और अत्याधुनिक अनुसंधान के एक विशाल पूल में टैप करने की अनुमति देती हैं। यह नए उत्पादों और समाधानों के विकास में तेजी ला सकता है।

लागत प्रभावी प्रशिक्षण: महंगे इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने के बजाय, कंपनियां अपने मौजूदा कर्मचारियों के लिए अनुकूलित मॉड्यूल और पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी कर सकती हैं। कैसे उद्योग और अकादमिया सहयोग कर सकते हैं सफल भागीदारी स्पष्ट संचार और साझा लक्ष्यों पर बनाई गई है। यहाँ सहयोग के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियाँ हैं:

पाठ्यक्रम सह-निर्माण: कंपनियां और विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से पाठ्यक्रम, कार्यशालाओं और डिग्री कार्यक्रमों को डिजाइन कर सकते हैं जो सीधे उद्योग की जरूरतों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक तकनीकी कंपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता में एक नई विशेषज्ञता बनाने के लिए विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग के साथ साझेदारी कर सकती है।

अनुभवात्मक अधिगम: मजबूत इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और सह-ऑप प्रोग्राम स्थापित करें जहां छात्र वास्तविक परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं। यह उन्हें अमूल्य व्यावहारिक अनुभव देता है और कंपनियों को संभावित कर्मचारियों को ₹ऑडिशन₹ देने की अनुमति देता है।

संयुक्त अनुसंधान और विकास: वास्तविक दुनिया उद्योग की चुनौतियों को संबोधित करने वाली अनुसंधान परियोजनाओं पर सहयोग करें। इससे सफलताओं और नए पेटेंट हो सकते हैं, जिससे कंपनी और शैक्षणिक संस्थान दोनों को लाभ हो सकता है।

अतिथि व्याख्यान और मेंटरशिप: अतिथि व्याख्यान देने या छात्रों को संरक्षक के रूप में सेवा करने के लिए उद्योग के पेशेवरों को आमंत्रित करें। यह छात्रों को वर्तमान रुझानों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और उन्हें पेशेवर नेटवर्क बनाने में मदद करता है।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: विश्वविद्यालय और कंपनियां शैक्षणिक अनुसंधान का व्यवसायीकरण करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं, नवीन विचारों को विपणन योग्य उत्पादों और सेवाओं में बदल सकते हैं। इन साझेदारियों को गले लगाकर, दोनों क्षेत्र अधिक कुशल, अनुकूलनीय और अभिनव कार्यबल बना सकते हैं, अंततः आर्थिक विकास को चला सकते हैं और प्रतिभा अंतर की लगातार चुनौती से निपट सकते हैं।

किताबें इसलिए भी पढ़िए

विजय गर्ग

आजकल बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्मार्ट सीईओ हर हफ्ते एक किताब पढ़ते हैं। जी हां! हर हफ्ते एक किताब । वे पढ़ने से प्यार करने लगे हैं और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। येल यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार, जो लोग किताबें पढ़ते हैं, वे उन लोगों के मुकाबले दो साल अधिक जीवित रहते हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ते। रिपोर्ट कहती है कि शुरू से अंत तक किताब पढ़ने से भावनात्मक बौद्धिकता और समानुभूति को काफी बढ़ावा मिलता है, यानी खाली वक्त में टीवी देखना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करना आपको स्मार्ट नहीं बनाता, इसलिए इस वक्त को किताबें पढ़कर उत्पादक बनाइए ।

पढ़ने की यह आदत गहरी नींद में सहायक है। अच्छी नींद के लिहाज से दो चीजों का प्रबंधन काफी अहम होता है- रोशनी और आवाज। तमाम डिजिटल उपकरण, जैसे स्मार्टफोन, टीवी, टैबलेट आदि प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनके प्रकाश में स्पेक्ट्रम का एक नीला हिस्सा होता है, जो समस्या बढ़ाने वाला है, क्योंकि यह नीला हिस्सा आपको अधिक चौकस रखता है और गहरी नींद के लिए जरूरी मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को कम कर देता है। अगर आप इस माहौल में भी सो लेते हैं, तब भी गुणवत्तापूर्ण नींद नहीं ले पाएंगे, जो आपके शरीर की जरूरत है। फिर किताबें प्रकाश का उत्सर्जन भी नहीं करतीं, जो आपकी आंखों में तनाव पैदा कर सके। दुनिया की अनेक ब्लॉकबस्टर फिल्में मशहूर कहानियों पर आधारित हैं। लेकिन अब भी अनगिन शानदार कहानियां परदे से दूर किताबों में ही दर्ज हैं और आप उनसे

वंचित हैं। मसलन, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला जैसी कई हस्तियों ने इस दुनिया को बदला है और ऐसी कोई फिल्म उपलब्ध

नहीं, जो उनके संघर्ष की सही मायने में व्याख्या करती । आप उनकी आत्मकथाएं या जीवनियां पढ़ेंगे, तो आपको उससे एक दृष्टि मिलेगी और उनका अनुभव आपके साथ होगा। शोधों से पता चला है कि उतार-चढ़ाव से भरे विवरणों वाली किताबें पढ़ने से मानव मस्तिष्क की संज्ञानात्मक प्रणाली पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसी किताब को पढ़ने से आपको जो आनंद और अनुभव मिलता है, वह कितना टिकाऊ है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उस किताब को कितना वक्त दिया। यदि आप उसे पढ़ते हुए आनंद ले रहे हैं, उसमें दर्ज हरेक विवरण पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हर किरदार को उसकी स्थिति में समझने की कल्पना कर रहे हैं, तो इसका स्थायित्व अधिक होगा और आनंद भी हफ्तों बना रहेगा। किताबों का अध्ययन आपके शब्दों के खजाने को ही समृद्ध नहीं करता, बल्कि यह दिमाग की मांसपेशियों का व्यायाम भी है।

स्वतंत्रता संग्राम को सुनते-पढ़ते रहो

डॉ. नीरज भारद्वाज

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जब भी पढ़ने बैठता हूं तो आंखों से आंसू स्वतः ही निकल आते हैं। मेरे परदादा हमें अंग्रेजों के अत्याचार की बातें बताते थे। कैसे वह लोगों को बुरी तरह मारते-पीटते थे। लोगों को भेड़-बकरियों की तरह हाथ बांधकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। गांव में कितने ही लोगों का पता ही नहीं लग पाता था कि वह कहां गए हैं। विचार करें तो वर्तमान युग की तरह उस समय ना कोई सूचना तंत्र था और ना ही अपना तंत्र अर्थात हम स्वतंत्र थे। किससे पूछे? क्या पूछे? लोग अपने दर्द में बैठे केवल अपने परिवारजन के व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा करते थे। किसी व्यक्ति की कोई लिखा-पढ़ी नहीं होती थी। कागज कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं, अब वह जीवित है या मर गया, कोई आंकड़ा नहीं था। उस समय मेरा बाल मन इन बातों को सुनकर बहुत आहत होता। तब कहां पता था कि हम भी लिखने की विधा में आयेंगे अर्थात लेखक के रूप में कार्य करेंगे।

साहित्य के विद्यार्थी बने तो राष्ट्रीय काव्य धारा को पढ़ा, साथ में इतिहास की कुछ पुस्तकें भी पढ़ीं। उसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को फिर पढ़ा और जाना। वास्तव में अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों पर बहुत अत्याचार किया हैं। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट के सर्च इंजन पर जाकर देखेंगी तो पता चल जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों की संख्या में भारतीय जवान मारे गए जबकि हमारा इन दोनों विश्व युद्ध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लेना-देना नहीं था। अंग्रेज अपने देश के नाम पर लड़ रहे लड़ाई को जीतने के लिए हमारे देशवासियों का अर्थात हमारे युवाओं का सहारा लेते रहे। हमें स्वतंत्र कर देंगे, यही बातें बताते रहे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

जब हम गांधी जी के आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं, वहां भी हमें पता चलता है कि अंग्रेजी सरकार कितनी क्रूरता के साथ हमारे देशवासियों को मारती थी। जलियांवाला बाग की घटना को देखते-समझते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे देश की शांत प्रिय जनता को अंग्रेजों ने कैसे निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा। बच्चें, बूढ़े, जवान, माताएं-बहनें सभी पर गोलियाँ चलवा दी। आज भी वह रक्तरंजित भूमि सब कुछ बता रही है। विचार करें, देखें, समझें और जानेंगे तो पता चलता है कि भारतवर्ष के हर घर से कोई ना कोई हमारा पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम के महायुद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे चुका है।

स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ की ज्वाला सन् 1857 से जली और 1947 तक ऐसे ही जलती रही। इससे पहले भी बहुत प्रयास हुए. उन्हें भी नहीं भुलाया जा सकता है। स्वतंत्रता की ज्वाला कभी तीव्र गति से तो कभी धीमी गति से जलती रही। लोग अपने प्राणों की आहुति देते रहे लेकिन इस ज्योत को अर्थात स्वतंत्रता की ज्वाला को लोगों ने अपने हृदय में जलाये रखा। 15 अगस्त,1947 को हमें आखिरकार स्वतंत्रता मिल गई। देश में नया रंग और जोश भर गया। हमारा प्यारा तिरंगा शान से लहरा उठा, जो लहर अंदर थी, अब वह बहार भी

उठकर सामने आई। देश की आजादी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लोग अपनों के जाने की पीड़ा या दर्द को कैसे भूल सकते थे लेकिन हंसते मुस्कुराते स्वतंत्रता दिवस को मानते रहे।

अंग्रेज स्वतंत्रता देने के बाद भी नहीं रुके, उन्होंने एक चाल फिर चल दी। इस देश का विभाजन कर इसमें एक नई त्रासदी भर दी। लोग हिंदू-मुस्लिम के झगड़ों में पड़कर आपस में मारने- काटने लगे। यहां भी मौत का बहुत बड़ा आंकड़ा जाना जा सकता है। देश पहले भी कितने ही अपने युवाओं, माताओं-बहनों, बुजर्गों आदि को खो चुका था और अब विभाजन की विभीषिका ने एक बार फिर लोगों के अंदर नया वैमनस्य भर दिया। लोग आपस में मरने-मारने लगे। अंग्रेज इस देश के अंदर अपने धर्म का प्रचार भी बहुत तेजी से कर रहे थे और जगह-जगह उन्होंने अपने धर्म की प्रचार के बड़े-बड़े कार्य करने शुरू किए। लोगों का धर्मांतरण कराया, उन्हें अपने धर्म में मिला लिया। लोगों में धर्म की नई राजनीति पैदा करते रहे। अंग्रेज तो चले गए लेकिन इस देश के अंदर आज तक भाईचारे की बहुत सारीबातें सही से जुड़ नहीं पा रही हैं। इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम की बहुत सारी बातें ऐसे ही पढ़ते, सुनते, जानते रहो जिससे की आने वाली पीढ़ियों को ठीक से बताया जा सके।

वल्ला पहूँच डा. इंदरबीर सिहं निज्जर ने लिया अमृतसर बल्क वॉटर स्पलाई प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा

अमृतसर (साहिल बेरी)

अमृतसर दक्षिण हल्के से विधायक व पूर्व मंत्री स्थानिय निकाय विभाग पंजाब डा. इंदरबीर सिहं निज्जर द्वारा वल्ला के पास अमृतसर बल्क वॉटर स्पालई प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करके प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया गया। जिस दौरान उनके द्वारा निर्माणाधीन वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करके प्लांट के तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। ज्ञात हो की नगर निगम द्वारा विश्व बैंक और एशियन इन्फरास्ट्रक्चर इनवेस्टमैंट बैंक के सहयोग से पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसिस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। जिसके तहत आने वाले समय में अपर बारी दौआब नहर के पानी को शुद्ध करके घर-घर स्पलाई किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 44 करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले आधुनिक वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का निमार्ण, 45 नई पानी की टैंकीयों के निर्माण, 24 मौजूदा टैंकियों के नवीनिकरण के साथ-साथ शहर में 112 कि.मी लंबी पाईपलाईन बिछाने का काम का चल रहा है। इस मौके पर डा. निज्जर द्वारा प्रोजेक्ट की प्रगति को लकेर प्रोजेक्ट पर काम कर रही लार्सन एंड टूब्रो कंपनी और नगर निगम के अधिकारीयों के साथ बैठक भी गई। डा. निज्जर ने इस मौके पर कहा की तेजी से गिरते भूजल और शहरवासियों का साफ पानी की स्पालई के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे ना सिर्फ भूजल पर से हमारी निर्भरता कम होगी बल्कि आम लोगों को शुद्ध पानी की स्पालई भी सुनश्चित होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को आने वाले 30 सालों के लिए शहर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है, जिससे की वर्ष 2055 में शहर की अनुमानित 25 लाख की आबादी को पानी की स्पालई सुनश्चित हो सकेगी। उन्होंने प्रोजेक्ट की अहमियत को ध्यान में रखते हुए शहरवासियों से अपील की कि वह प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उनके घरों या दुकानों के आस-पास प्रोजेक्ट को लेकर अगर कोई निर्माणकार्य हो रहा है तो उसको पूरा करने में अपना सहयोग करें। वहीं इस प्लांट परिसर में दिल और फेफड़ों के रोगों की जांच के लिए आयोजित किए गए एक विशेष कैंप की शुरूआत भी डा. निज्जर द्वारा की गई। इस कैंप में डा. विजय कोटवाल, जिला टी.बी अधिकारी, डा. अनिल हृदय रोग विशेषज्ञ तथा डा. अमित मैडिकल ऑफसर, सिविल अस्पताल द्वारा प्लांट में काम करने वाले मजदूरों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों के स्वास्थय की जांच की गई तथा फेफड़ो और हृदय को सेहतमंद रखने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में जानकारी भी दी। इस मौके पर डा. निज्जर द्वारा प्लांट परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। इस मौके पर जीतिन वासुदेवा एस.ई प्रोजेक्ट, लार्सन एंड टूब्रो के प्रोजेक्ट मैनेजर राहुल पटेल, अश्वनी शर्मा सीनियर कंसट्रक्शन मैनेजर, रणजीत सिहं एस.डी.ओ. डा. मौनिका सभ्भरवाल, गीरिराज सिहं हाडा, हरप्रीत सिहं, आदि भी उपस्थित थे।

केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए वोटर कार्ड कैंप में लगभग 195 लोगों ने कार्ड बनवाए : हर वार्ड में लगेगा वोटर कार्ड बनवाने का कैंप : विधायक डॉ अजय गुप्ता

अमृतसर, (साहिल बेरी)

केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉ अजय गुप्ता ने आज वार्ड नंबर 57,58,59 और 60 के मतदाताओं के लिए वोटर कार्ड बनवाने हेतू डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाथी गेट में कैंप का आयोजन करवाया। आज इस कैंप में लगभग 195 लोगों ने अपने अपने वोटर कार्ड बनवाएं। विधायक डॉ गुप्ता ने कहा कि वोटर कार्ड बनवाने के लिए केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक वार्ड में दो दो कैंप आने वाले दिनों में लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन कैंप में नए वोटर कार्ड, वोटर कार्ड की करेक्शन, वोटर कार्ड शिफ्ट करने और मृत हो चुके लोगों के वोटर कार्ड काटने के लिए फॉर्म नंबर 6, 7, 8 भरकर कैंप में ही कार्य करवा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को किसी भी कार्यालय में जाने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विधायक डॉ अजय गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों की सरकार है। उन्होंने कहा कि जिसके तहत लोगों को प्रत्येक सुविधाए देने के लिए ₹ सरकार आई आपके दवार ₹ के तहत केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र में लगातार कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैंपों में राशन कार्ड, नीले कार्ड, पीएम आवास योजना के तहत घर बनवाने, जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट, आमदनी के सर्टिफिकेट और अन्य योजनाओं के तहत एक छत के नीचे लोगों को सुविधाए दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक वार्ड और तीन पंचायतो में कैंप लगाकर नए वोटर कार्ड बनवाए जाएंगे। इस अवसर पर राविंदर सिंह डावर, गुरदास सिंह, सुरजीत सिंह, चरणजीत सिंह, हैप्पी चोपड़ा, ऋषि कपूर और भारी संख्या में लोग शामिल हुए।

आर्यभट्ट से गगनयान: प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएँ (23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस विशेष आलेख)

सुनील कुमार महला

23 अगस्त को दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस- 2025 विशेष रूप से चर्चा में है, क्योंकि यह चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की दूसरी वर्षगांठ है। पाठकों को बताता चलूं कि इस दिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त के दिन 2023 में इसरो की चंद्रयान-3 लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रयान-3 मिशन की सफलता को याद करना और युवाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (एसटीईएम) में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना है। गौरतलब है कि पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन 23 अगस्त 2024 को किया गया, जिसका विषय/थीम- 'चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना: भारत की अंतरिक्ष गाथा' रखा गया था, तथा इस बार दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस(वर्ष 2025) की थीम 'आर्यभट्ट से गगनयान: प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएँ', रखी गई है,जो भारत की खगोलशास्त्रीय विरासत से लेकर आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान (गगनयान) तक की यात्रा को दर्शाता है। पाठक जानते होंगे कि 23 अगस्त 2023 को इसरो के चंद्रयान-3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तैनाती शामिल थी, जिससे भारत यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इसके अवतरण स्थल को 'शिव शक्ति' बिंदु नाम दिया गया था। बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने जिस ऊँचाई को छुआ है, उसका श्रेय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को जाता है। अपने स्थापना काल से ही इसरो की उपलब्धियां बहुत ही शानदार रहीं हैं।1969-1980 तक इसरो का आरंभिक दौर था,जब 1969 में डॉ. विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इसरो की स्थापना की गई थी। इसके बाद वर्ष 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा तथा साल 1980 में रोहिणी उपग्रह को स्वदेशी प्रक्षेपण यान (एसएलवी-3) से प्रक्षेपित किया गया। कहना ग़लत नहीं होगा कि इसरो ने दूरसंचार और मौसम उपग्रह में शानदार प्रगति की है।इनसैट और आईआरएस श्रृंखला के उपग्रहों ने भारत को संचार, प्रसारण, मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनाया है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि भारत ने पहली बार चंद्रमा पर चंद्रयान-1(वर्ष 2008) मिशन भेजा और वहां जल-बर्फ की उपस्थिति का प्रमाण विश्व को दिया।भारत ने अपनी पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में(मंगलयान एम ओ एम-2013) पहुँचकर इतिहास रचा। यह उपलब्धि पाने वाला भारत एशिया का पहला और विश्व का चौथा देश बना। इतना ही नहीं साल 2017 के दौरान पीएसएलवी-सी37 से एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित कर इसरो ने विश्व रिकॉर्ड बनाया।इसके बाद चंद्रयान-2 (साल 2019) का प्रक्षेपण किया गया। यद्यपि लैंडर सफलतापूर्वक उतर नहीं सका, परंतु ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षा से महत्वपूर्ण आंकड़े भेज रहा है। चंद्रयान-3 (साल 2023) के बारे में तो पाठक जानते होंगे कि दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया। आधुनिक मिशनों की यदि हम यहां पर बात करें तो आदित्य-एल1 (2023-24) सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है। इतना ही नहीं, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान,भी आने वाले वर्षों में लॉन्च होने की संभावना है। गौरतलब है कि वर्तमान में निसार उपग्रह (अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ) पृथ्वी के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहा है। पाठकों को बताता चलूं कि 30 जुलाई 2025 को, इसरो ने नासा के साथ मिलकर विकसित निसार (नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार) उपग्रह को जीएसएलवी-एफ16 रॉकेट से कक्षा में स्थापित किया था। यह पृथ्वी की सतह पर होने वाले छोटे बदलावों को सेमी-स्तर की सटीकता से मापने की क्षमता रखता है—जैसे ग्लेशियर का पिघलना, भूकंपीय हलचल, आदि। यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक सहयोग और पर्यावरण-अवलोकन उपलब्धि है। इतना ही नहीं संयुक्त राज्य, रूस और चीन के बाद भारत स्पेस डॉकिंग में सफलता प्राप्त करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन और तकनीकी परीक्षणों में भी अभूतपूर्व प्रगति की है। आदित्य-एल1 मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजे गए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप (एसयूआईटी) ने सूर्य की तस्वीरों और फ्लेयर्स की एनयूवी क्षेत्र में लगातार एक वर्ष तक सफल अवलोकन किया। यह उपकरण हमारे सौर वातावरण की समझ को और मजबूत करता है। इसरो ने जीएसएलवी-एफ15 से अपना 100वाँ रॉकेट लॉन्च करते हुए एनवीएस-02 नेविगेशन सैटेलाइट को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया, जिससे NavIC नेटवर्क और मजबूत हुआ। यह इसरो का लोकल और विदेशी लॉन्च दोनों के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था। इतना ही नहीं इसरो वर्तमान में मानवोन्मुख मिशन (गगनयान मिशन) पर लगातार काम कर रहा है।इसरो अगली पीढ़ी के ऐसे रॉकेट विकसित कर रहा है जो लगभग 40-मंज़िला इमारत जितने ऊँचे (120एम+) होंगे और 75 टन वजन का पेलोड भेज सकेंगे—यह भारी उपयोगों जैसे स्पेस स्टेशन मॉड्यूल्स की तैनाती हेतु जरूरी है।इसरो चंद्र और शुक्र मिशन के अलावा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भी काम कर रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की अपनी अंतरिक्ष स्टेशन की परियोजना जिसमें लगभग 20 टन भार का स्टेशन 400 किमी कक्षा में बनाया जाएगा, जहां पर 15–20 दिनों के लिए चालक दल रह सकेगा। यह 2028–2035 के बीच परिकल्पित है।चिप विकास और सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता पर भी इसरो लगातार काम कर रहा है। पाठकों को बताता चलूं कि आइआइटी मद्रास और इसरो के सहयोग से विकसित आईआरआईएस नामक चाकती(CHAKTI) सीरीज का RISC-V आधारित माइक्रोप्रोसेसर चिप, जो विशेष रूप से अंतरिक्ष मिशनों के लिए फाल्ट टोरेंट मेमोरी, वाचडोग टाईमर्स आदि के साथ तैयार किया गया है। यह सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंत में यही कहूंगा कि आज हमारा इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ रहा है और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इसरो की उपलब्धियों ने भारत को अंतरिक्ष जगत में विश्व में सिरमौर तथा एक बड़ी महाशक्ति बना दिया है। आज अंतरिक्ष केवल शोध का क्षेत्र नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन चुका है।दो पंक्तियां समर्पित हैं - 'जिस धरती की मिट्टी में,सपनों की उड़ान बसी है,उस भारत मां के बेटों ने चाँद-सूरज तक राह रची है। पसीने से सींची मेहनत, ज्ञान से गढ़ा विज्ञान, हर सफलता पर गर्व करे पूरा हिन्दुस्तान।' जय-जय।

राजनीतिक भ्रष्टाचार पर मोदी का बड़ा प्रहार

राजेश कुमार पासी

भ्रष्टाचार हमारे देश की एक बड़ी समस्या है लेकिन राजनीतिक भ्रष्टाचार उससे बड़ी समस्या है क्योंकि राजनीति ही भ्रष्टाचार को संरक्षण देती है। अगर राजनीति का संरक्षण भ्रष्टाचारियों के ऊपर से खत्म हो जाये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में बड़ी सफलता मिल सकती है। बेशक हमारे नेता और न्यायपालिका भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हो लेकिन सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार इनकी छत्रछाया में ही फल-फूल रहा है। जज के नीचे बैठे कर्मचारी जमकर रिश्वत लेते हैं लेकिन जज कुछ नहीं कर पाते। इसी तरह नेताओं के राजनीतिक और प्रशासनिक सहयोगी जमकर भ्रष्टाचार करते हैं और नेता कुछ नहीं कर पाते। भ्रष्टाचार के प्रति मोदी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है. इसके बावजूद देश में भ्रष्टाचार में कमी नहीं आई है।

मोदी सरकार राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बिल लायी है जिसमें प्रावधान किया गया है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाते हैं और उन्हें लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें 31वें दिन अपना पद छोड़ना होगा। इसके साथ यह शर्त भी जोड़ी गई है कि आरोपों में कम से कम पांच साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए 130 वां संशोधन विधेयक, 2025, केन्द्रशासित प्रदेश सरकार(संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन(संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया गया है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239एए में संशोधन का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक को विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। मोदी सरकार ने कहा है कि भविष्य में जेपीसी के सुझावों और सिफारिशों के आधार पर विधेयक पेश किया जाएगा। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी खुद को कानून के दायरे में लाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाए हैं जबकि इंदिरा जी ऐसा विधेयक लाई थी जिससे वो कानून के दायरे से बाहर हो गई थी। विपक्ष ने इस विधेयक का जबरदस्त विरोध किया है और संसद में भारी हंगामा किया है। यह हंगामा इसके बावजूद किया गया है कि सरकार ने विधेयक पर विचार करने के लिए जेपीसी को भेजने

की सिफारिश की है। सवाल यह है कि जब विपक्ष के पास अपनी बात जेपीसी के सामने रखने का मौका है तो हंगामा करने की क्या जरूरत थी।

इन विधेयकों के पेश होते ही विपक्ष के कई सदस्य हंगामा करते हुए लोकसभा की वेल में पहुंच गए। विपक्षी दलों का आरोप है कि विधेयक से केन्द्र सरकार विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने की साजिश कर रही है। विपक्षी सांसदों का कहना था कि केन्द्र सरकार इस विधेयक के कानून बन जाने पर इसका इस्तेमाल विपक्षी दलों की सरकारों को गिराने के लिए करेगी। विपक्ष इसे संविधान और लोकतंत्र विरोधी बता रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसकी कार्य संस्कृति और नीति प्रधानमंत्री को संविधान से भी ऊपर मानने की रही है जबकि भाजपा की संस्कृति है कि हम अपने प्रधानमंत्री, मंत्री एवं मुख्यमंत्रियों को ही कानून के दायरे में ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन संख्या-39 से पीएम को ऐसा विशेषाधिकार दिया कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई।

जनता में बीजेपी के बढ़ते ग्राफ से बौखलाई भगवंत मान सरकार: हरविंदर सिंह संधू

अमृतसर, 22 अगस्त (साहिल बेरी)

भाजपा जिलाध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू ने कहा कि पंजाब की जनता को मूलभूत सुविधाएं देने का काम मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा उनकी सरकार है, जिसमें आम आदमी पार्टी पंजाब की भगवंत मान सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। अगर केंद्र की नरेंदर मोदी सरकार पंजाब की जनता को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त CSC सेंटरों के माध्यम से पंजाब के ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश कर रही है, तो यह भगवंत मान को हजम नहीं हो रहा। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पुलिस बल का सहारा लेकर भाजपा नेताओं द्वारा लगाए जा रहे कैम्पों से भाजपा नेताओं को जबरन हिरासत में लेकर कैंप बंद करवाए गए। जिसके रोष-स्वरूप आज भाजपा अमृतसर के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू के नेतृत्व में अमृतसर के पाँच विधानसभा क्षेत्रों में भगवंत मान सरकार के विरुद्ध अलग-अलग जगहों पर जमकर रोष प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की तथा मुख्यमंत्री भगवंत मान के पुतले फूंके।

उत्तरी विधानसभा में विधानसभा इंचार्ज सुखमिंदर सिंह पिंटू की अध्यक्षता में विधानसभा के पाँचों मंडलों के कार्यकर्ताओ ने मिलकर खंडेवाला चौक में रोष प्रदर्शन किया, जिसमें पूर्व सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक, बलदेव राज बग्गा, कपिल शर्मा, शक्ति कल्याण, पार्षद श्रुति विज, मंडल अध्यक्ष किशोर रैना, अमित अबरोल, सुखदेव सिंह हनेरीयाँ, नुरीन महाजन, नवदीप हांडा, जज्जी प्रधान, अर्जुन कुमार आदि उपस्थित थे। पश्चिमी विधानसभा में विधानसभा इंचार्ज कुमार अमित की अध्यक्षता में अविनाश शैला, चारों मंडल अध्यक्ष मोहित वर्मा, शाम भगत, सतीश पुंज मोहना, राजीव शर्मा (सन्नी) आदि सहित कार्यकर्ताओं ने खंडवाला चौक में, दक्षिणी विधानसभा में विधानसभा इंचार्ज हरजिंदर सिंह ठेकेदार की अध्यक्षता में गुरप्रताप सिंह टिक्का, अजयबीर पाल सिंह रंधावा, जसपाल सिंह शंटू, मनिंदर सिंह ठेकेदार, चारों मंडल अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह राजा, संजीव शर्मा, अशोक कुमार, जसविंदर सिंह आदि सहित कार्यकर्ताओं ने सुल्तानविंड चौक में, केन्द्रीय विधानसभा में विधानसभा इंचार्ज डॉ. राम चावला की अध्यक्षता में जिला महासचिव सलिल कपूर, चारों मंडल रोमी चोपड़ा, टहल सिंह, सुधीर अरोड़ा, संभव जॉली आदि सहित कार्यकर्ताओं तथा आम जनता ने मिलकर लोहगढ़ चौक में पंजाब सरकार के विरुद्ध रोष-प्रदर्शन किया तथा भगवंत मान के पुतले फूंके।

हरविंदर सिंह संधू ने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र की नरेंदर मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही केंद्रीय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं का लाभ पंजाब की गरीब जनता तक सीधा पहुँचाने के लिए यह कैंप लगाए जा रहे थे, ताकि उनकी जेबों पर किसी भी तरह का कोई आर्थिक बोझ ना पड़े और उन्हें कहीं भी धक्के ना खाने पड़े। लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को यह बात हजम नहीं हुई और वह इतना नीचे गिर गए हैं कि अब पंजाब की गरीब जनता से उनके हक़ छीनने पर उतर आए हैं।

हरविंदर सिंह संधू ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के करीब तीन वर्षों के शासन के दौरान पंजाब के हालात बद से बदतर हो गए हैं। इन लोगों ने पंजाब की जनता को तो कुछ दिया नहीं, उल्टा जनता को गुमराह करने के लिए हर काम में झूठ बोल रहे हैं और अपनी नाकामियों का दोष केंद्र की मोदी सरकार पर मढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के विकास के लिए भेजे जा रहे फंडों का भी भगवंत मान सरकार जमकर दुरूपयोग कर रही है। यहाँ तक कि पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाओं को भी यह तो बंद किया जा रहा है या उन्हें अपने नाम से चलाने का झांसा देकर जनता को मुर्ख बनाया जा रहा है। जनता के टैक्स के पैसे का भी अपने झूठे प्रचार के लिए दुरूपयोग किया जा रहा है। सत्ता के नशे में चूर भगवंत मान सरकार ने पंजाब की जनता के सिर पर 1 लाख करोड़ रुपए का नया कर्ज चढ़ा दिया है, जो आगे भी लगातार जारी है। अब तो भगवंत मान सरकार ने अपनी सारी हदें पार करते हुए गरीब जनता को केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं को भी रोकने के लिए पुलिस बल का प्रयोग शुरू कर दिया है।

हरविंदर सिंह संधू ने भगवंत मान सरकार को चेतवानी देते हुए कहा कि अगर आप सरकार द्वारा जनता के विरुद्ध की जा रही मनमानियां बंद नहीं की, तो भाजपा अपना संघर्ष और तेज करेगी।

स्वास्थ्य विभाग ने "हर शुक्रवार डेंगू से जंग" अभियान के तहत केंद्रीय कारागार में डेंगू के लार्वा की खोज की

अमृतसर, (साहिल बेरी)

पंजाब सरकार के आदेशानुसार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री पंजाब डॉ. बलबीर सिंह जी के निर्देशन में, सिविल सर्जन अमृतसर डॉ. किरणदीप कौर द्वारा ₹हर शुक्रवार डेंगू से जंग₹ अभियान के अंतर्गत केंद्रीय कारागार स्थित केंद्रीय सुधार गृह में डेंगू जागरूकता अभियान चलाया गया और डेंगू के लार्वा की खोज की गई। इस अभियान के दौरान, केंद्रीय कारागार और आसपास के सभी क्षेत्रों में लार्वा-रोधी गतिविधियाँ चलाई गईं और डेंगू व चिकनगुनिया के बारे में जागरूकता फैलाई गई। इसके बाद, उन्होंने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और डेंगू व चिकनगुनिया के लार्वा की खोज की और मौके पर मिले लार्वा को नष्ट किया।

इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर ने कहा कि बरसात के मौसम में जगह-जगह पानी जमा होना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ ही जहां पानी जमा होगा, वहां मच्छर भी पनपेंगे, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें और कहीं भी पानी जमा न होने दें, क्योंकि डेंगू से बचने के लिए मच्छरों को पनपने से रोकना सबसे जरूरी है। इसके साथ ही पूरी बाजू के कपड़े पहनना और मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करना भी हमें डेंगू से बचा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहर के सभी हॉटस्पॉट क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं और एंटी-लार्वा गतिविधियां भी चला रही हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ. हरजोत कौर ने बताया कि डेंगू एक वायरल बुखार है जो एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। यह मच्छर साफ पानी में अंडे देता है, जो एक सप्ताह में अंडों से लार्वा और लार्वा से वयस्क मच्छरों में बदल जाते हैं। इसलिए सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को डेंगू अभियान चलाया जा रहा है ताकि मच्छर के जीवित चक्र को तोड़ा जा सके और इसे लार्वा अवस्था में ही समाप्त किया जा सके। इस अवसर पर जिला एम.ई.आई.ओ. अमरदीप सिंह ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि डेंगू के सामान्य लक्षण तेज सिरदर्द व तेज बुखार, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, उल्टी, नाक, मुंह व मसूड़ों से खून आना है। इसलिए डेंगू बुखार का संदेह होने पर तुरंत सरकारी अस्पताल से मुफ्त जांच व उपचार करवाना चाहिए। इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री हेमंत शर्मा, ए.एम.ओ. गुरदेव सिंह, एस.आई. सुखदेव सिंह, राजिंदर सिंह, कुलदीप गिल, हर कमल सिंह सहित सभी आशा वर्कर व सरकारी नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस: एक राष्ट्र की आकांक्षाओं का उत्सव

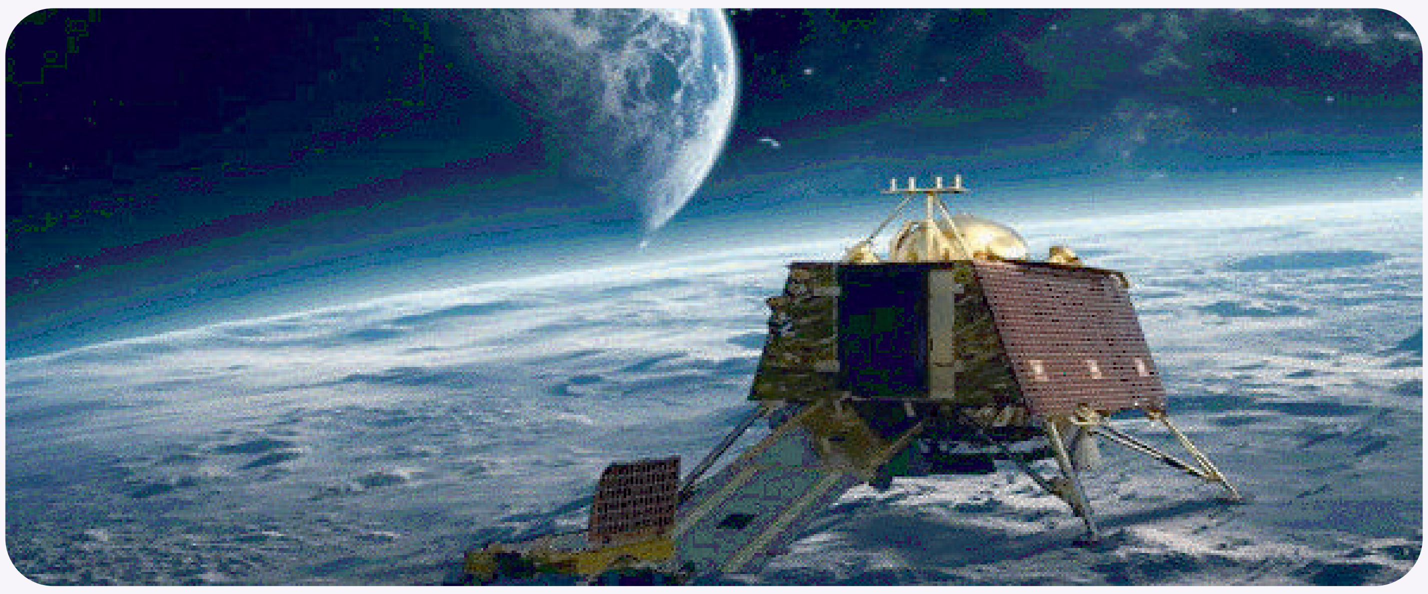

23 अगस्त का सूरज जब उगा, तो वह सिर्फ़ एक दिन को नहीं, बल्कि एक युग को रोशन कर गया। यह तारीख अब केवल कागज़ पर नहीं, बल्कि हर भारतीय के हृदय पर अंकित हो चुकी है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर न केवल भारत का झंडा गाड़ा, बल्कि मानवता की आकांक्षाओं को एक नया आकाश दिया। यह क्षण वह नहीं था जब मशीनें चाँद की मिट्टी पर उतरीं; यह वह पल था जब एक राष्ट्र ने अपनी आत्मा को तारों के पार भेजा। यह दिन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, विज्ञान की जीत से कहीं बढ़कर है—यह सपनों का उत्सव है, जो असफलताओं की राख से फीनिक्स की तरह उभरे।

जब चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की अनछुई सतह को स्पर्श किया, तो उसने न केवल वैज्ञानिक इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर अंकित किए, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात किया। चंद्रयान-2 की असफलता को विश्व ने पराजय माना, पर भारत ने उसे एक प्रेरणा बनाया। इसरो के वैज्ञानिकों ने उस ठोकर को सीढ़ी में ढाला, और सिद्ध कर दिखाया कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संदेश है। यह भारतीय दर्शन की वह शक्ति है, जो टूटे को जोड़ती है और असंभव को संभव बनाती है। 23 अगस्त 2023 को, जब विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा, तो वह केवल एक मिशन की जीत नहीं थी—यह एक प्राचीन सभ्यता की उस अटल मान्यता की विजय थी, जो कहती है कि असंभव महज एक शब्द है, और सपने सितारों तक ले जाते हैं।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का असली महत्व इसकी वैज्ञानिक उपलब्धि में नहीं, बल्कि इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव में है। जब एक ग्रामीण स्कूल का बच्चा रात को तारों की ओर देखता है और यह सोचता है कि उसका देश उन तारों तक पहुँच चुका है, तो उसके मन में एक नया विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है; यह उसे जीवन की हर चुनौती को पार करने की प्रेरणा देता है। इसरो की यह उपलब्धि सिर्फ़ डेटा और तकनीक की बात नहीं करती; यह हर उस व्यक्ति की कहानी कहती है जो अपने छोटे से गाँव में बड़े सपने देखता है।

चंद्रयान-3 की लागत को देखें तो यह आश्चर्यजनक है। नासा के मिशनों के सामने भारत का यह मिशन एक छोटे से बजट में रचा गया चमत्कार था। इसरो ने लगभग 615 करोड़ रुपये (लगभग 74 मिलियन डॉलर) में यह मिशन पूरा किया, जो कि हॉलीवुड की एक औसत ब्लॉकबस्टर फिल्म के बजट से भी कम है। फिर भी, इस मिशन ने न केवल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की अनछुई मिट्टी पर कदम रखा, बल्कि भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल किया, जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। यह सिद्ध करता है कि भारत की ताकत उसके संसाधनों में नहीं, बल्कि उसके संकल्प में है। यह वही देश है जो मंगल पर भी कम बजट में मंगलयान भेज चुका है, जिसकी लागत (450 करोड़ रुपये) भी कई देशों के अंतरिक्ष मिशनों की तुलना में नगण्य थी।

23 अगस्त का उत्सव केवल वैज्ञानिकों का नहीं है। यह उन गुमनाम नायकों का भी उत्सव है जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। वे इंजीनियर, जो रात-रात भर डेटा विश्लेषण करते हैं। वे तकनीशियन, जो एक-एक तार को जोड़ते हैं। और वे परिवार, जो अपने प्रियजनों की अनुपस्थिति को सहते हैं ताकि देश का नाम आकाश में चमके। जब इसरो के नियंत्रण कक्ष में तालियों की गूंज उठी, तो वह सिर्फ़ एक लैंडर की सफलता की गूंज नहीं थी; वह उन अनगिनत बलिदानों की आवाज़ थी जो इस मिशन को साकार करने में लगे।

चंद्रयान-3 की लैंडिंग का वैज्ञानिक महत्व भी कम नहीं है। दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ की खोज ने न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान को नई दिशा दी, बल्कि मानवता के भविष्य के लिए एक नई संभावना खोली। इसरो के प्रज्ञान रोवर ने चंद्र सतह पर सल्फर और ऑक्सीजन जैसे तत्वों की उपस्थिति की पुष्टि की, जो भविष्य में चंद्रमा पर मानव बस्तियाँ स्थापित करने की दिशा में एक कदम है। यह खोज केवल वैज्ञानिक डेटा नहीं है; यह एक संदेश है कि अंतरिक्ष अब केवल दूर की कौतूहल भरी दुनिया नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का अगला पड़ाव हो सकता है।

यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल तकनीक का प्रदर्शन नहीं है; यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का विस्तार है। जिस सभ्यता ने वेदों में तारों की गणना की, जिसने आर्यभट्ट के ज़रिए खगोलशास्त्र को नई ऊँचाइयाँ दीं, उसी सभ्यता ने आज चंद्रमा पर अपनी छाप छोड़ी है। यह संयोग नहीं है कि चंद्रयान-3 का लैंडर "विक्रम" और रोवर "प्रज्ञान" कहलाया। ये नाम हमारी प्राचीन बुद्धिमत्ता और आधुनिक महत्वाकांक्षा का संगम हैं।

23 अगस्त हमें यह भी सिखाता है कि अंतरिक्ष की खोज केवल प्रतिस्पर्धा का मैदान नहीं है। जहाँ अमेरिका और सोवियत संघ ने शीत युद्ध के दौरान अंतरिक्ष को अपनी शक्ति का प्रतीक बनाया, भारत ने इसे मानवता की साझा विरासत के रूप में देखा। चंद्रयान-3 का मिशन केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि उन सभी देशों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों में बड़े सपने देखते हैं। यह मिशन वैश्विक सहयोग का निमंत्रण है, न कि प्रतिद्वंद्विता का।

इस दिन का उत्सव केवल अतीत की उपलब्धि का जश्न नहीं है; यह भविष्य के लिए एक सवाल भी है। हमारा अगला कदम क्या होगा? क्या हम मंगल पर जीवन की खोज करेंगे? क्या हम सौरमंडल से बाहर की सैर करेंगे? या फिर, क्या हम अंतरिक्ष की खोज को धरती के संकटों—जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट, भूख—का हल बनाएँगे? नेशनल स्पेस डे हमें यही चुनौती देता है—सपने देखने की, और उन सपनों को हकीकत में बदलने की।

23 अगस्त हमें यह सिखाता है कि सीमाएँ केवल मन की बेड़ियाँ हैं। जब एक राष्ट्र अपनी कल्पनाओं को ब्रह्मांड की असीम ऊँचाइयों तक उड़ान देता है, तो वह न केवल चंद्रमा पर अपने कदमों की छाप छोड़ता है, बल्कि अपनी नियति को तारों की स्याही से नवीन रंग देता है। यह दिन हर भारतीय के हृदय में यह अटूट विश्वास जागृत करता है कि हमारी मंज़िलें सितारों में बसी हैं, और हमारा पथ अडिग संकल्प की ज्योति से प्रकाशित है।

-प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान: 10वीं तक सभी बच्चों को मुफ्त किताबें, BSE और CHSE का विलय कर एक बोर्ड बनाया जाएगा

मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

भूबनेश्वर : मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले तीन सालों में राज्य में 45,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इनमें से 40,000 नए शिक्षक पद सृजित किए जाएँगे।यहां तक कि दसवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।राज्य सरकार ने योजनाबद्ध प्राथमिक शिक्षकों को नियमित करने का निर्णय लिया है। बीएसई और सीएचएसई को मिलाकर एक ही बोर्ड बनाया जाएगा। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा परिषद और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद का विलय करने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ओडिशा में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2036 तक समृद्ध ओडिशा के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा का बहुत महत्व है। इसलिए, इसे ध्यान में रखते हुए, उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। आज, मुख्यमंत्री ने लोक सेवा भवन में स्कूल और लोक शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा की और ये सुझाव दिए और कई नए निर्णय लिए। मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार, योजनाबद्ध प्राथमिक शिक्षकों को नियमित करने के लिए कदम उठाए जाएँगे।

नई शिक्षा नीति के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है। वर्तमान में, राज्य के 45,292 प्राथमिक विद्यालयों में 1,60,319 शिक्षक पद हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार, 39,366 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा। इसके साथ ही, दिसंबर 2025 तक 5,067 शिक्षण पद भी रिक्त हो जाएँगे। अतः मुख्यमंत्री ने इन सभी पदों को मिलाकर अगले तीन वर्षों में 44,433 पदों को भरने के निर्देश दिए। प्रतिवर्ष लगभग 15 हजार पद भरे जाएँगे।

बैठक में यह विचार व्यक्त किया गया कि स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए राज्य में एक बोर्ड की आवश्यकता है। तदनुसार, राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSE, CHSE) को मिलाकर एक बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार, राज्य में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं, जबकि कक्षा नौ और दस में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को ही पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने कक्षा नौ और दस के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने का निर्णय लिया।

छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ-साथ स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। अतः बैठक में छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के लिए एएनएम की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक 300 बच्चों पर एक एएनएम या बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार, बैठक में निजी स्कूलों की नई स्वीकृति प्रणाली को पूरी तरह से ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने पर ज़ोर देने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे बच्चों के साथ भाषाई संवाद सुगम होगा और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी।

इसके साथ ही, कोरापुट में एससीएसटीआरटीआई के सहयोग से एक बहुभाषी शिक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएँगे। इसके बाद, बी.एड. कर चुके नियमित शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न संकुलों में संसाधन व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि एससीईआरटी को एनसीईआरटी मॉडल के अनुरूप विकसित करने के लिए कदम उठाए जाएँगे। पाठ्यपुस्तक प्रकाशन एवं विपणन निदेशक को भी सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में राज्य के स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गैंद, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव शाश्वत मिश्रा, वित्त विभाग के प्रधान सचिव संजीव मिश्रा, स्कूल एवं जन शिक्षा सचिव शालिनी पंडित, ओएसईपीए की निदेशक अनन्या दास और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सजा पुनरीक्षण पर्षद झारखंड का 35 वां बैठक संपन्न, आजीवन सजा के 51 कैदी होंगे रिहा

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 35वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में रिहाई से संबंधित 37 नए मामलों के साथ-साथ 66 वैसे कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत किया गया था।

बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्रीमती वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, प्रधान प्रोवेशन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे

बैठक में मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे कुल 103 कैदियों को कारामुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार गहन विचार-विमर्श किया। राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा रिहाई हेतु अनुशंसित एक-एक कैदियों की फाइल पर गंभीरता से विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति तथा न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा दिए गए मंतव्य की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने रिहाई हेतु अनुशंसित कैदियों की उम्र एवं पारिवारिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक स्थिति की भी पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच रिहाई हेतु प्रस्तावित सभी मामलों पर गहन विचारोपरान्त कुल 51 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में समीक्षा के उपरांत राज्य के विभिन्न कारागारों में 14 वर्ष या उससे अधिक समय से सजा काट रहे वैसे कैदी जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है तथा जेल में उनका आचरण अच्छा है उन्हें रिहा किया जाता है, अतएव रिहा हो रहे कैदियों को एक बेहतर सामाजिक जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि रिहाई से संबंधित अनुशंसित मामलों में कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें कैदियों के बीमार होने तथा कुछ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने की बात कही गई है, इन सभी मामलों के लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार कर ऐसे कैदियों को शारीरिक एवं मानसिक चिकित्सा प्रदान किए जाएं, चिकित्सा के उपरांत डॉक्टरों द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार वैसे कैदियों की रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए ताकि वे अपना जीवन सुचारू रूप से व्यतीत कर सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों को हर हाल में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़ें।

बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में सहमति के उपरांत वर्ष 2019 से अबतक राज्य के विभिन्न कारागारों से 619 कैदियों को रिहा किया जा चुका है, जिसमें 558 कैदियों का विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन भी किया गया है। 61 बंदियों का भौतिक सत्यापन किया जाना बाकी है। यह भी बताया गया कि वर्ष 2019 से अबतक रिहा हुए 619 में से 470 कैदियों को सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा ई० श्रम कार्ड इत्यादि योजनाओं के लाभ से जोड़ा गया है। रिहा हुए वैसे कैदी जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें संबंधित योजनाओं से जोड़ने का कार्य प्रक्रियाधीन है, जल्द ही सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया जाए

श्रीमंदिर में 15 सितंबर से लाइन दर्शन शुरू होगा - कानून मंत्री

मनोरंजन सासमल, बरिष्ठ पत्रकार

पुरी/भूबनेश्वर : पुरी मंदिर में 15 सितंबर से कतारबद्ध दर्शन व्यवस्था शुरू हो जाएगी। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि मंदिर प्रशासन कतारबद्ध दर्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। इससे भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और श्रद्धालुओं को आसानी होगी।संचालन समिति का गठन 3 से 4 दिनों में कर दिया जाएगा। पहली बैठक में हुंडी शिफ्ट होने के बाद कतार दर्शन शुरू हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि अबधा दरा चार्ट का काम पूरा हो चुका है, मंदिर प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मंदिर के अंदर महाप्रभु के दर्शन के दौरान भीड़ से निजात दिलाने के लिए कतार दर्शन की व्यवस्था करने का वादा किया था। मंदिर में महाप्रभु के दर्शन के लिए अक्सर भारी भीड़ होती है। भगदड़ में भक्त घायल हो जाते हैं और महाप्रभु के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। नई सरकार ने व्यवस्थित दर्शन के लिए मंदिर में कतार दर्शन व्यवस्था लागू करने का वादा किया था। मंदिर प्रशासन ने पिछले साल कार्तिक माह के बाद भक्तों के व्यवस्थित दर्शन की व्यवस्था करने को कहा था। बताया गया कि बाहरी लकड़ी या नटमंडप पर बिना किसी भीड़ के भक्तों को ठाकुरजी के दर्शन कराने की योजना तैयार की गई है और पुरुषों, दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था की जाएगी। भक्त सात सीढ़ियों से प्रवेश करेंगे और घंटाघर से बाहर निकलेंगे। बताया गया कि कुल छह पंक्तियों में भक्त प्रवेश करेंगे और चतुर्धा विग्रह के दर्शन के लिए लकड़ी के बैरिकेड्स से गुजरेंगे।

अवैध रेत, मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने अंकित राज समेत छह पर आरोप पत्र दाखिल की

रू 3 करोड वैध आय, 28 अचल संपत्ति, दो एफ डी समेत रू 3 करोड कुर्क संपत्ति जप्त

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, 'झारखंड टाइगर ग्रुप' नाम के गैरकानूनी संगठन का संचालन जैसी कई आपराधिक गतिविधियां के साथ जबरन वसूली, समय सीमा समाप्त के बाद अवैध तरीके से रेत खनन, सरकारी काम में बाधा डालने जैसी आरोप योगेंद्र साव के बेटे के पर ईडी ने लगाया है। झारखंड में अवैध रेत खनन से जुड़े मनी लॉनड्रिंग के मामले में ईडी ने झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के बेटे अंकित राज और छह अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर दिया। कांग्रेस नेता साव झारखंड के कृषि मंत्री रह चुके हैं। ईडी का आरोप है कि अंकित राज राज्य में चल रहे एक व्यापक, व्यवस्थित और बहुस्तरीय अवैध रेत खनन सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था, जिसने इस अपराध के जरिए काफी कमाई अर्जित की।एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि अंकित राज ने 2019 में अपने खनन लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लंबे समय तक हाहारो, प्लांडु और दामोदर नदियों से अवैध रूप से रेत निकालना और बेचना जारी रखा।ईडी का कहना है कि, 'सिंडिकेट ने इस अवैध काम के जरिए हुई कमाई को सफेद करने के लिए एक खास तरीका अपनाया। उसने बताया कि अवैध रूप से खनन की गई रेत को आरोपी अपने सहयोगियों के लाइसेंस प्राप्त यार्डों में भेज देते थे, और उसे वैध स्टॉक के साथ मिलाकर बताते थे। इस तरह उन्होंने वैधानिक नियमों की अवहेलना करके आपराधिक आय अर्जित की और नकदी जमा करने के साथ ही वित्तीय लेनदेन के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से अवैध धन को सफेद किया।'

ईडी की जांच के अनुसार, इस तरह रेत खनन करके सिंडिकेट ने 3.12 करोड़ रुपए की आपराधिक आय अर्जित की। जिसके बाद इस केस में ईडी ने अंकित राज की 28 अचल संपत्तियों और दो फिक्स्ड डिपॉजिट सहित 3.02 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी ने पिछले साल मार्च और जुलाई में इस मामले के सिलसिले में तलाशी ली थी।

मनीलॉन्ड्रिंग का यह मामला पूर्व मंत्री साव, उनके परिवार और उनके सहयोगियों के खिलाफ झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज 16 विभिन्न प्राथमिकी से जुड़ा है। जिनमें जबरन वसूली, अवैध रेत खनन, सरकारी कामकाज में बाधा डालना और झारखंड टाइगर ग्रुप नाम के एक गैरकानूनी संगठन को चलाने जैसी कई आपराधिक गतिविधियों के लिए दर्ज प्राथमिकी शामिल हैं।जांच एजेंसी की तरफ से बताया गया कि इस मामले में जिन पांच अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उनके नाम मनोज कुमार अग्रवाल, पंचम कुमार, संजीव कुमार, मनोज प्रसाद दांगी, अनिल कुमार और बिंदेश्वर कुमार दांगी हैं। इस बारे में अभियोजन पक्ष की शिकायत गुरुवार को रांची स्थित पीएमएलए (धनशोधन निवारण अधिनियम) की एक विशेष अदालत में दायर की गई थी।

डीजीपी नियुक्ति नियमावली याचिका हाईकोर्ट ने भेजा सुप्रीम कोर्ट

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड- झारखंड

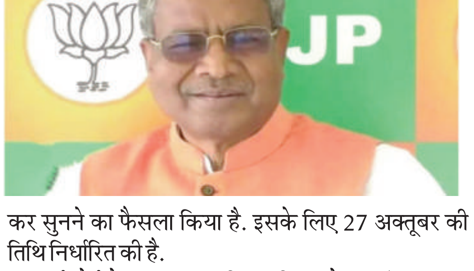

रांची, झारखंड डीजीपी नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है. अब इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है.

उल्लेखनीय है कि प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायाधीश एनवी अनजारिया की पीठ में सुनवाई हुई.

झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के मुद्दे पर जारी सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह कहा कि इस मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में ही याचिकाएं दायर है. यह नियम संगत नहीं है.

एक साथ दोनों जगह याचिका दायर होने का मामले उठने के बाद Amicus Curiae ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका की ओर न्यायालय से यह अनुरोध किया कि झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करे.

कोर्ट ने Amicus Curiae के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका 1194/2025 की सुनवाई करने का फैसला किया.

झारखंड हाईकोर्ट में यह याचिका बाबूलाल मरांडी ने दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर इस याचिका को प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार की मूल याचिका के साथ जोड़ कर सुनने का फैसला किया है. इसके लिए 27 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है.

हाईकोर्ट में दायर इस जनहित याचिका में झारखंड सरकार द्वारा डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए बनायी गयी नियुक्ति नियमावली की वैधता को चुनौती दी गयी है. झारखंड सरकार ने इसी नियुक्ति नियमावली के सहारे अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया है.

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023